



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

18 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा

18 मार्च, 2017 ई०

पंचम सत्र

शनिवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1938(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11 बजे पूर्वा०)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तरकाल ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तरकाल होने दीजिए न।

श्री प्रेम कुमार,ने०वि०द० : महोदय, हमारा आग्रह इतना ही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि नाम बताइये आप, जब नाम आ गया है कृष्ण नन्दन वर्मा जी का, आलोक मेहता जी का तो इन्हें बर्खास्त सरकार करे।

अध्यक्ष : समय पर उठाइयेगा।

(इस अवसर पर भाजपा एवं सी०पी०आइ०एम०एल० के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न। डा० मेवालाल चौधरी।

अल्पसूचित प्रश्न सं०-11(डा० मेवालाल चौधरी)(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न। अरे आप समय पर उठाइयेगा न।

तारांकित प्रश्न सं०-1281(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा कोशी निरीक्षण भवन, घोघरडीहा पी०डब्लू०डी० रोड से दिघिया टोला तक सड़क के लगभग आधे हिस्से रामेश्वर मुखिया के घर से नजाम अंसारी के घर तक में पी०सी०सी० सड़क का निर्माण 14वें वित्त आयोग मद से कराया जा चुका है। पेट्रोल पंप से दिघिया सामूहिक दलान तक पी०सी०सी० सड़क एवं ढक्कन सहित नाला निर्माण हेतु योजना का चयन मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण योजना के तहत किया जा चुका है। यह योजना नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत तैयार किये गये दीर्घकालीन कार्य योजना में वार्ड सं०-3 के प्राथमिकता सूची के क्रमांक-22 पर अंकित है। नगर पंचायत घोघरडीहा

द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत प्राथमिकता के अनुसार वर्णित सड़क एवं नाला का निर्माण करा दिया जायेगा।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, अल्पसूचित में मेवालाल चौधरी का प्रश्न आया था, ये कहां हैं, फरार हैं, सरकार बचा रही है। उनकी पहले गिरफ्तारी तो करे।

अध्यक्ष : माननीय प्रेम बाबू, हमलोग तो इतना जानते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-1282(श्री शम्भुनाथ यादव)

डा0 मदन मोहन झा,मंत्री : स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत सड़क पर से अतिक्रमण हटाने हेतु अंचल कार्यालय, सिमरी में अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण वाद सं0-02/2008-09 संधारित किया गया। चिन्हित कुल 32 अतिक्रमणकारियों के द्वारा अलग-अलग मौजों के अलग-अलग खातों एवं खेसरों में ज्यादातर स्थाई प्रकृति की यथा ईट की सीढ़ी, दीवार, चबुतरा एवं मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमणवाद के तहत आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाया भी गया है। परन्तु अतिक्रमणवाद सं0-02/2008-09 के संबंध में अतिक्रमणकारी बैजनाथ पाण्डेय के द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज वरीय कोटि प्रथम डुमरांव के यहां स्वत्व वाद सं0-225/16 दायर किया गया है। जिसमें उक्त न्यायालय से प्राप्त नोटिस एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रश्नगत स्थल की पुनः मापी दिनांक 06.12.2016 से 09.12.2016 तक करायी गयी। मापी के आधार पर कुल 20 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया जिसमें ज्यादातर अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्का मकान, चबुतरा आदि का निर्माण कर स्थाई अतिक्रमण कर लिया गया है। चिन्हित किये गये सभी अतिक्रमणकारियों को दिनांक 20.12.2016 एवं 07.01.2017 को अतिक्रमण खाली करने हेतु नोटिस जारी की गयी और लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अंतिम आदेश 07.02.2017 को पारित किया जा चुका है। इसके उपरान्त इन्टरमीडियेट/बिहार बोर्ड की परीक्षा एवं होली की वजह से पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की उपलब्धता के अभाव में अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। एक माह के अन्दर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

अध्यक्ष : चलिए यह तो साफ है।

तारांकित प्रश्न सं0-1283(श्री रामविलास पासवान)

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए श्री अत्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव अधिकृत हैं।

श्री रामविचार राय,मंत्री : 1-उत्तर अस्वीकारात्मक है। भागलपुर जिला के पीरपैती प्रखंड के मिट्टी नमूना कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा किसानों के खेत से लिया जाता है। संग्रहित

नमूनों को भागलपुर जिला स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में जाँचकर प्रखंड में किसानों को मृदा स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध कराया जाता है। भागलपुर जिला के पीरपैँती प्रखंड में वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य 1190 नमूना के विरुद्ध 835 नमूना संग्रहीकरण 682 नमूनों की जाँच कर अब तक 2272 मृदा स्वास्थ्य केन्द्र वितरित किये गये हैं। शेष नमूना संग्रह जाँच एवं कार्ड वितरण कार्य अप्रैल 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस प्रकार किसानों के मिट्टी जाँच के लिए सुविधा जिला स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अत्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पीरपैँती का जो इलाका है भागलपुर से बहुत ज्यादा दूर है और उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है जब मिट्टी क्षारीय और अम्लीय होता है और ज्ञान किसानों को वहां तक नहीं हो पाता है कि हमारी मिट्टी किस स्थिति में है। उसमें किस तरह के उर्वरक का हम इस्तेमाल करें, किस मात्रा में करें तो ऐसी स्थिति में चूंकि भागलपुर की जो दूरी है पीरपैँती से काफी दूरी है। इस स्थिति में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अस्वीकारात्मक है तो पीरपैँती के सन्दर्भ में सवाल पूछा गया था कि पीरपैँती में है कि नहीं तो पीरपैँती में इस तरह का विचार माननीय मंत्री जी ने नहीं लाया है। क्या सरकार ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है प्रखंड में प्रयोगशाला का क्या किसान हित में माननीय मंत्री महोदय उस इलाके का चूंकि धनहर का इलाका है पीरपैँती का इलाका, बड़ा उन्नत किस्म का धान वहां होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या वहां किसानों को देखते हुए, वहां के हालात को देखते हुए आप प्रयोगशाला निर्माण करने का विचार रखते हैं ?

श्री रामविचार राय,मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि वर्तमान में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रखंड स्तर पर सरकार के यहां कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, हम आग्रह कर रहे हैं आसन से.....ध्यान नहीं देंगे तो बोलना पड़ेगा लगातार ना। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जानकारी आपको भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने पूरे बिहार और देश के लिए- पूरी दुनिया में 64 तरह के मिट्टी पाये जाते हैं उसमें बिहार में 46 तरह के मिट्टी पाये जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुगुना करने के लिए भारत सरकार का फैसला भी है, लेकिन बिहार में जो स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाना है उसकी गति काफी धीमी है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि किसानों के हित में उसमें तेजी लाने का आप काम करें।

(व्यवधान)

मतलब है, मतलब उसी से न है, किसानों की आमदनी बढ़ाने का भारत सरकार की सोच है, प्रधानमंत्री की सोच है कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो। इसी निमित्त स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात आयी थी। हम आग्रह कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि जो भारत सरकार का फैसला है बिहार में स्वाइल हेल्थ कार्ड का जो प्रगति कार्य अभी धीमी है उसमें किसानों के हित में तेजी लाने का काम करें।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय विपक्ष के नेता इस प्रश्न को पूरक के रूप में अभी उठा सकते हैं ?

तारांकित प्रश्न सं०-1284(श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री रामविचार राय,मंत्री : यह ट्रांसफर है नगर विकास विभाग को।

टर्न-2/अशोक/18.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या-1285-(श्री अमीत कुमार)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री :अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत बैरगनिया के द्वारा नगर क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तीन स्थानों पर पार्किंग स्थल का निर्धारण किया गया है:-

1.- टैम्पू, जीप, मोटरसाईकिल, टमटम, एवं सभी प्रकार हल्के एवं भारी वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बनवारीलाल बेनीलाल धर्मशाला से प्रारम्भ होकर पूरब की ओर बाजार समिति तक जिला पर्षद सड़क के दोनों भाग में पी.सी.सी. सड़क छोड़कर किया गया है ।

2.-धर्मशाला रोड में जमीन अख्तर खां के मकान से गौरीशंकर साह चूड़ा वाले के मकान तक

3- गौशाला रोड में पुराने रेलवे के पश्चिमी गेट से स्व० रामचन्द्र प्रसाद जायसवाल के मिल तक।

इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में अवस्थित जिला परिषद् की सड़कों पर जिला परिषद् के द्वारा चलन्त दुकान के बंदोबस्ती से जाम की समस्या होती है। ऐसे दुकानों की बंदोबस्ती नहीं करने हेतु नगर पंचायत, बैरगनिया के द्वारा उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी से अनुरोध किया गया है । साथ ही वाहनों के जाम की समस्या से निजात हेतु नगर निकाय द्वारा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया गया है । इस प्रकार नगर पंचायत, बैरगनिया द्वारा सड़क पर जाम की समस्या के निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अमीत कुमार : मैं पूछना चाहता हूँ कि बैरगनिया सीमावर्ती इलाका है, नेपाल के बोर्डर पर हैं और रोड 30 फीट चौड़ा है, क्या वहां पर पार्किंग किया जा सकता है ? मंत्री महोदय ने बतलाया रोड के किनारे पार्किंग की व्यवस्था की गई तो उससे वहां के जाम की समस्या हट जायेगी ? और वो बतला रहे हैं कि जिला परिषद् की जमीन पर चलन्त दुकान, दुकाना भी है, वहीं पर ऑटो और रिक्शा जो भी लगता है तो कैसे इसका निबटारा होगा ?

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है?

श्री अमीत कुमार : पूरक है कि सर वहां उससे निबटारा नहीं हो रहा, वहां जाम लगातार लगा रह रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, चूंकि जिला पर्षद के सड़कों पर, जिला पर्षद का सड़क है और सड़क की बन्दोबस्ती उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है दुकान का इसलिये हमलोगों ने आग्रह किया, वहां के कार्यपालक पदाधिकारी, बैरगनिया पत्रांक 837 दिनांक 27.8.16 द्वारा उन्होंने आग्रह किया है कि वहां पर उसको टेन्डर नहीं किया जाय, निविदा न किया जाय जिससे कि जाम नहीं लगे, तो उनसे आग्रह किया गया है, वहां पर टेन्डर नहीं होगा तो जाम नहीं लगेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1286(श्री वीरेन्द्र कुमार)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगाधीन नाला निर्माण हेतु नगर पंचायत, तेघड़ा द्वारा योजना प्रस्तावित है । नगर पंचायत, तेघड़ा के पत्रांक-820, दिनांक 29.12.2016 द्वारा योजना का डी.पी.आर. तैयार करने एवं तकनीकी सहयोग हेतु कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय से अनुरोध किया गया है । विभाग में डी.पी.आर. प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आलोक में योजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1287(डॉ राजेश कुमार)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि केसरिया बौद्ध स्तूप के चारों ओर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग(ASI) के दिशा-निर्देश के अनुसार 200 मीटर तक कोई नवनिर्माण नहीं किया जा सकता है । 200 मीटर के आगे की भूमि रैयती

है, जिस पर नगर निकाय द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया जा सकता है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1288(श्री (मो0) तौसीफ आलम)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज दिघलबैक प्रखंड मुख्यालय ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना वर्ष 2007-08 में स्वीकृत हुई थी । इस योजना में प्रावधानित अवयवों का कार्य कराकर चालू किया गया है एवं योजना चालू है । परन्तु वर्तमान में सड़क एवं पुल निर्माण के क्रम में 65 मीटर पाईप क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कुछ क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित है । क्षतिग्रस्त पाईप वाले क्षेत्र में पाईप की मरम्मत दो माह में कराकर इस क्षेत्र में भी जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी ।

2-उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री (मो0) तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि चालू है, मैं कह रहा हूँ चालू हुआ था लेकिन अब तक बंद पड़ा हुआ है, सरकार दो महीना के अन्दर काम शुरू करा देगी इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा लेकिन वहां से जो जवाब आया है वह गलत आया है।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री सदानन्द सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह योजना कब चालू की गई और बंद कब हुई है, अब तक कितने दिनों से वह बंद पड़ी हुई है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वर्ष 2007-08 में स्वीकृत हुई थी और इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है परन्तु कुछ क्षेत्र में पुल और सड़क निर्माण के क्रम में पाईप क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण वहां जलापूर्ति बाधित है ।

श्री सदानन्द सिंह : जवाब नहीं दे रहे हैं । मैंने पूछा चालू कब हुआ, बंद कब हुआ तिथि दीजिये और कब से बंद है, यह जानाकारी चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : योजना तो चालू है महोदय ।

श्री सदानन्द सिंह : योजना चालू नहीं है । माननीय सदस्य कह रहे हैं चालू नहीं है, आपने खुद स्वीकारा है कि बंद है, पुल बनने से ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : मैंने तो कहा कि योजना पूर्ण हैं, वहां पाईप क्षतिग्रस्त हो गया है ।
अध्यक्ष : ठीक है, आप कर दीजियेगा चालू ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1289(श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सन्हौली अंचल ग्राम-पंचायत बनयड्डा के स्व0 सदरी पासवान, पिता स्व0 संतोषी पासवान एवं सैरू पासवान , पिता- स्व0 संतोषी पासवान सा0 बनियड्डा, अंचल सन्हौला को भूदान के तहत नहीं बल्कि बंदोबस्ती तहत अनाबाद बिहार सरकार की भूमि मौजा-बनयड्डा थाना नं.-504, पुराना खाता-52 नया खाता-178, पुराना खेसरा-82, नया खेसरा-418 में से 0.33-0.33 डी0 परवाना सदरी पासवान एवं सैरू पासवान को बंदोबस्ती परवाना अभिलेख सं0-36/70-71 के तहत वर्ष 1970-71 में दिया गया था ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

पर्चाधारी सदरी पासवान के मरणोपरान्त उनकी पत्नी मसोमात करमलता देवी एवं सैरू पासवान के मरणोपरान्त उनकी पत्नी मो0 अगहनी देवी के नाम बंदोबस्ती वाली जमीन का जमाबंदी कायम किया गया, जिसका लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत है । दिनांक 04.03.2017 को अंचल अमीन द्वारा पर्चाधारी के परिजनों के समक्ष नापी कर भूमि को चिन्हित करते हुए दखल दिला दिया गया है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1290(श्री रामसेवक सिंह)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उचकागाँव प्रखंड के बलेसरा ग्राम पंचायत के बलेसरा ग्राम में वर्ष 16-17 में एक सौर उर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित किया गया है । इन योजना में भैट/सिन्टैक्स का प्रावधान है । जलमीनार का नहीं । इस योजना अंतर्गत 150mmX100mmx90mm उच्च प्रदायी नलकूप, पम्प चैम्बर तथा चाहर दीवारी का निर्माण हो चुका है तथा अन्य प्रावधानित अव्यवों के कार्य प्रगति में है । जिसे मई-2017 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति चालू करने का लक्ष्य है।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नाधीन ग्राम पंचायत बलेसरा की जनसंख्या 10770 है । इस पंचायत में 51 अदद चापाकल चालू अवस्था में है जिससे जलापूर्ति की जा रही है तथा पेयजल का कोई संकट नहीं है ।

3-उपर्युक्त खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री राम सेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह योजना तीन वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ, काम लगने के बाद संवेदक के द्वारा वहां काम बंद किया हुआ है माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जून तक काम पूरा कर लिया जायेगा लेकिन जिस तरह से उदासीनता है संवेदक का अध्यक्ष महोदय, उस तरह काम होना सम्भव नहीं है । क्रमशः...

टर्न-3/ज्योति

18-03-2017

क्रमशः

श्री राम सेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस तरह काम होना सम्भव नहीं है इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जून तक का जो समय सीमा निर्धारित किये हैं उस अवधि तक निश्चित रूप से काम कराने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1291 (श्री शमीम अहमद)

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड में दो प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं जो निम्न प्रकार हैं :

(1) सेमरा और (2) जटवा ।

वस्तुस्थिति यह है कि डा0 निरंजन कुमार प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हरसिद्धी को अपने कार्य के अलावे प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सेमरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है एवं डा0 प्रमोद कुमार आर्य कनीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी को जटवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है । उल्लेखनीय है कि 903 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है । पशु चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्त कर पदस्थापित किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1292 (श्री डा0 सुनील कुमार)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी- सह- अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा के

आदेश संख्या 984 दिनांक 10-8-2016 के द्वारा प्रश्न में वर्णित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1228 दिनांक 25-2-2016 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली, गली पक्कीकरण निश्चय योजना प्रारम्भ की गयी है । उक्त संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री नगर विकास योजना समाप्त करते हुए इस योजनान्तर्गत पूर्व से लंबित योजना एवं अवशेष राशि इस नयी योजना में समाहित कर दिया गया है । चूँकि मुख्यमंत्री शहरी नाली, गली पक्कीकरण निश्चय योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में वर्णित नागरिक सुविधा से संबंधित योजना का प्रावधान नहीं है ।

उक्त के आलोक में प्रश्न में वर्णित योजना भी बंद कर दी गयी है । दिनांक 16-3-17 को अल्पसूचित प्रश्न के संदर्भ में दिए गए आश्वासन के आलोक में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री (डा0) सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पूर्व माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था।....

अध्यक्ष : उसी का हवाला उन्होंने दिया है ।

श्री (डा0) सुनील कुमार : स्वीकार किया था कि जो भी स्वीकृत योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन कराया जायेगा । मंत्री महोदय ने कहा कि इसका निर्देश हमने सभी कलक्टर को दिया है। क्या मंत्री महोदय उसकी प्रतिलिपि सभी माननीय सदस्य जो इस मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में अनुशंसक सदस्य हैं, उनको देने की कृपा करेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक से अनुरोध करेंगे कि हम बुलेट ट्रेन की तरह नहीं चल रहे हैं । 16 तारीख को आश्वासन दिए हैं । तुरत इसका कैसे लेटर चला जायेगा, इसका आश्वासन हम कैसे देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वह पूरक की बात नहीं कह रहे हैं । आप सदन में दिये गये आश्वासन के आलोक में जो भी दिशा निर्देश जिला समाहर्ता लोगों को देंगे उससे सदस्यों को भी अवगत करा दीजियेगा ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : डाक्टर साहेब कह रहे हैं कि तुरत दीजिये । हम तो देंगे ही । उसका विवरण दिए हैं ।

श्री (डा0) सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि वह जो निर्देश देंगे उसकी प्रति तो हमलोगों को देंगे लेकिन ये योजनाएं कबतक पूर्ण करा देंगे ?

अध्यक्ष : अभी तो निर्देश की बात हो रही है योजना पूर्ण की बात कहाँ से आ गयी ?

तारांकित प्रश्न संख्या 1293 (श्री वाशिष्ठ सिंह)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। नगर पंचायत, कोचस के गठन के पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी को छोड़कर कार्यालय कर्मियों का आजतक पद श्रृजन नहीं हो पाया है। जिला स्तर से एक कार्यपालक सहायक कार्यरत है एवं कार्यालय कार्य निष्पादन हेतु 6 कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक पर रखा गया है। सभी नगर निकाय में पद की संरचना एवं श्रृजन की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

श्री वाशिष्ठ सिंह : महोदय, इसमें जो बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी 6 को रखा गया है दैनिक पारिश्रमिक पर तो बिल्कुल काम आधा अधूरा हो रहा है। जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का डिमान्ड है कि कर्मचारी की नियुक्ति करायी जाय ताकि विकास का काम अवरुद्ध न हो इसलिए माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि शीघ्र इसको करने की कृपा करें।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि नगर पंचायत में कर्मियों को संविदा पर रखने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सभी नगर निकायों में पद श्रृजन एवं पद पुनर्संरचना हेतु संबंधित संलेख पद वर्ग समिति के विचार के लिए प्रेषित किया जा रहा है उसका उत्तर आ जाने के बाद जवाब दिया जायेगा।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1294 (श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)

श्री राम विचार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को वन एवं पर्यावरण विभाग को स्थानान्तरित किया गया है।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मीनापुर प्रखण्ड अंतर्गत हर साल हजारों हेक्टेयर फसल क्षति की अधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है। वन्य प्राणियों से कृषि फसल की क्षति हेतु 25 हजार रुपये प्रति एकड़ सहाय्य राशि प्रावधानित है, किसानों से किसी प्रकार का दावा प्राप्त होने पर साहाय्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पिछले वर्ष इसी नील गाय और सुअर की बर्बादी से दो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। अखबार में भी और सब जगह आया था। एक बच गए और एक मर गए। हजारों हेक्टेयर में फसल बर्बाद होती है - इनके अधिकारी कोई गलत रिपोर्ट किए हैं। ये जाकर जाँच करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप, बल्कि ये सभी सदस्यों के लिए जानकारी रखने वाली बात है कि अगर नीलगाय या कोई इस तरह का वन्य प्राणी या जो जानवर हैं, फसल की बर्बादी करते हैं, तो इसकी विधिवत् सूचना स्थानीय पदाधिकारियों को देकर सरकार ने प्रावधान किया है प्रति एकड़ का मुआवजा, तो उसका लाभ किसानों को दिलवाना चाहिए, उसकी विधिवत् रिपोर्टिंग करवा देनी चाहिए।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : पहले अध्यक्ष महोदय, नीलगाय को तो मारने का प्रावधान था...

अध्यक्ष : रुका कब ?

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : रुक गया है , केस हो जा रहा है । अब एक तरफ नील गाय है और दूसरी तरफ सुअर है, सुअर मारो तो उसमें भी दंगा का डर, गाय मारो तो उसमें भी दंगा का डर किसान परेशान हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1295 (श्रीमती भागीरथी देवी)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटाण्ड को अतिरिक्त प्रभार देकर गौनाहा प्रखंड के आपूर्ति कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है तथा रामनगर प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर रामनगर प्रखंड के आपूर्ति कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है । वर्तमान में पनन पदाधिकारी के 316 स्वीकृत बल के विरुद्ध 129 कार्यरत हैं तथा आपूर्ति निरीक्षक के 616 स्वीकृत बल के विरुद्ध 253 कार्यरत हैं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि सात वर्ष हो गया, एम0ओ0 के लिए, जिस समय में श्री श्याम रजक जी मंत्री जी थे उन्होंने इस बात को भूला दिया और कहे कि आज देंगे, कल देंगे । आप ध्यान देंगे एक चीज पर कि जब प्रभारी को प्रभार दिया जाता है सी0ओ0 और बी0डी0ओ0 को तो वह लोग कहते हैं कि हम यह काम करें कि, वह काम करें । उन लोगों का रोज लूट खसोट का काम है चाहे इधर से आए या उधर से आए इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि प्रभार नहीं देकर वहाँ के लिए एम0ओ0 बहाल किए जाय जबकि गौनाहा के बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम गौनाहा में प्रभार दिए तो प्रभार सिकटा के एम0ओ0 को गौनाहा में जो प्रभार दिया गया है, उनसे बात हुयी तो वो कहते हैं कि नहीं हमको सिकटा से फुर्सत होगी तब न वहाँ का कार्य करेंगे तो प्रभार वाली बात छोड़ दी जाय, उसके लिए आदेश दिया जाय ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष जी हमको बोलने दिया जाय और आप सब के समय कहते हैं कि हो गया, हो गया ।

(व्यवधान)

टर्न-4/18.3.2017/बिपिन

श्रीमती भागीरथी देवी: दो मिनट अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : तो आपको तो प्रश्न न पूछना होगा ?

श्रीमती भागीरथी देवी: पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप सब बात तो बता ही दिए तो अब न कहेंगे हो गया, तब कब कहेंगे ?

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कब तक एम.ओ. को प्रतिनियुक्त कर देंगे ?

श्री मदन सहनी,मंत्री: कर देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । बोल दिए कि कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1296 (श्री ललन पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखण्ड अन्तर्गत रायपुर चौर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वर्ष 2009-10 में दी गई थी जिसकी प्राक्कलित राशि 92.304 लाख रूपए हैं । योजना अन्तर्गत स्वीकृत सभी अव्यवों को पूर्ण कर वर्ष 2015-16 से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है तथा लगभग 70 प्रतिशत आबादी लाभान्वित हो रही है । इस योजना के अंतर्गत कुछ वार्ड, यथा-वार्ड सं0-6. 11 एवं 12 में पाइप अभी नहीं बिछाया गया है । पाइप से आच्छादित क्षेत्र में योजना से अब तक 107 अदद गृह जल संयोजन भी लाभुकों को दिया जा चुका है । शेष बचे वार्डों में हर घर नल निश्चय योजना के तहत पाइप बिछाने का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में लक्षित है ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सूचना देना चाहते हैं कि अभी तक आपका जो सूचना है, गलत है । पानी टंकी आपका प्रारंभ ही नहीं हुआ है।

दूसरी बात कि पूरी तरह गांव में आपने ठीक बात कहा कि आधा, मैं तो लिखा ही हूँ कि 70 प्रतिशत जगह बिछा हुआ है लेकिन बाकी जगह नहीं बिछा हुआ है। कितने दिनों की सीमा के अंदर चालु कर दिया जाएगा, पूरे गांव में आप नल से जल दे दीजिएगा ? सीमा निर्धारित करके मुझे बताने की कृपा करें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में लक्षित है और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो लक्ष्य है हमारा उसको समय-सीमा के अंदर पूरा करके पूरे गांव में जल संयोजन का काम करा देंगे ।

अध्यक्ष : बहुत आश्वस्त हैं मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1297 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव)

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला मधेपुरा अंतर्गत प्रखंड पुरैनी के अधीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है । सम्प्रति डा0 धनन्जय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, आलमनगर जून, 2015 से

भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी, पुरैनी के प्रभार में हैं। उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पशु चिकित्सालय, पुरैनी में जाकर चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 903 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित की गयी है। पशु चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अनुशांसा प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति कर पदस्थापित किया जा सकेगा।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखंड में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का पद जो सृजित नहीं है और 1994 में इस प्रखंड का सृजन हुआ था महोदय, तो पद सृजन करने की कार्रवाई माननीय मंत्री महोदय करना चाहते हैं ?

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो पूछा गया, उसका जवाब दिया है। सृजन करने का जहां तक प्रोविजन है तो माननीय सदस्य पहले नियुक्ति हो जाने दें डॉक्टर का, उसके बाद इनसे विचार-विमर्श करके ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य तो कह रहे हैं कि

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रकाशित हो चुका। अब होने में कहां दिक्कत है ?

अध्यक्ष : आपने बताया कि वहां पद ही सृजित नहीं है, इसलिए उसके पद सृजन की कार्रवाई करने का आग्रह माननीय सदस्य कर रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वही हम बोल रहे हैं।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1298 (श्री महबूब आलम)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1322 दिनांक-26.2.2016 द्वारा नगर पंचायत बारसोई का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में होने वाले नगर निकायों के आम चुनाव के पश्चात् नगर पंचायत बारसोई में नगर निकाय बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के गठन होने एवं पी.एल. खाता खुलने के पश्चात् प्रसंगाधीन योजना की स्वीकृति के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह नगर पंचायत की सिर्फ घोषणा हुई है। उसका कोई पदाधिकारी भी अब तक बहाल नहीं हुआ है महोदय और उस पंचायत के, नगर पंचायत के अंदर जो तीन पंचायत का चुनाव स्थगित हो गया, मोलनापुर, सुल्तानपुर, रघुनाथपुर, उनके विकास के पैसे अब तक ठप हैं अध्यक्ष महोदय और 14वीं वित्त आयोग का पैसा खर्च नहीं हो रहा है और मनरेगा का भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वह पैसा खर्च करने का आदेश दिया जाए।

अध्यक्ष : ठीक है । वह अलग से कीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1299 (श्री बृज किशोर बिन्द)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण विकास विभाग को ट्रांसफर्ड है ।

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास विभाग । यह स्थानान्तरित हुआ है आपको 1299 ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1300 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री (डॉ०)मदन मोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिले के मनिहारी अंचल में मौजा बगहार थाना नं०-249 के खाता-612 गैर-मजरूआ आम कुल रकबा-4.48 एकड़ जमीन का जमाबंदी उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मिर्जापुर के नाम से कायम है । प्रश्नगत जमीन के मापी के क्रम में इस जमीन के अंश भाग रकबा-28.330 वर्ग भूमि पर श्री राम अयोध्या यादव, पिता स्वर्गीय जीवन यादव का अवैध कब्जा पाया गया है । मापी के विरुद्ध कब्जाधारी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी के कार्यालय में परिवाद की अनन्य स० 5103101021600133 लाया गया था जिस कारण अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी । परिवाद पत्र का निष्पादन हो चुका है । अतएव, अब अतिक्रमण वाद संख्या 3/2016-17 दायर कर अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है । आशा है एक महीना के अंदर अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाएगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या-1299 का उत्तर तैयार है । अगर आपकी अनुमति हो तो उसका उत्तर दे देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, दे दीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1299 (श्री बृज किशोर बिन्द)

श्री श्रवण कुमार मंत्री : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का प्रश्न है सुलभ शौचालय के निर्माण का। माननीय सदस्य अगर जमीन उपलब्ध करा देंगे और ग्राम पंचायत के आम सभा से योजना पारित कराने का सरकार का निर्देश उनको दिया जाएगा और जैसे यह जमीन उपलब्ध होगी और जमीन उपलब्ध के बाद जैसे ही आम सभा से पारित होगी, उसके दो महीने के अंदर सुलभ शौचालय का निर्माण करा दिया जाएगा ।

श्री बृज किशोर बिन्द : महोदय, भगवानपुर, अधौरा में बिहार सरकार की काफी जमीनें हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ जमीन उपलब्ध होने से नहीं होगा, स्थानीय ग्राम पंचायत से एक प्रस्ताव पारित करा कर दे दीजिएगा तो निर्माण हो जाएगा ।

श्री बृज किशोर बिन्द: हम तैयार हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा ।

श्री बृज किशोर बिन्द : ठीक है । हम तैयार हैं । दे देंगे ।

टर्न:05/कृष्ण/18.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या : 1301 (श्री ललन पासवान)

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी विधान सभा क्षेत्र स्थित नौहट्टा, रोहतास एवं शिवसागर प्रखंडों में पशु अस्पताल सरकारी भवनों में अवस्थित है । शिवसागर पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक स्थायी रूप से नियुक्त है तथा नौहट्टा एवं रोहतास में नियोजित पशु चिकित्सक पदस्थापित थे । वर्तमान में संविदा अवधि समाप्त हो गयी है । नियोजन विस्तार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । यह उल्लेखनीय है कि जिलान्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है ।

2. उक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । उक्त आलोक में कार्रवाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि शिवसागर में है । लेकिन मेरा कहना है कि इनके का कोई डाक्टर का अता-पता वहां नहीं है और न नौहट्टा, रोहतास में ही है । मैंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में तो एक जगह है कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है लेकिन मैं तीनों प्रखंडों चेनारी सहित मैं कह रहा हूं । माननीय मंत्री जी सासाराम के संबंध में जो कह रहे हैं तो पहले व्यवस्था थी, पहले कई तरह के पशु रहते थे गर्भाधान के लिये, लेकिन हमारे यहां प्रखंडों में शून्य के बराबर है । माननीय मंत्री जो कह रहे हैं कि संविदा पर डाक्टर का नियोजन किया गया था लेकिन न नौहट्टा है और न रोहतास में है । मेरा इलाका पहाड़ी का इलाका है, वहां पशुओं का अम्बार है, काफी पशु रहते हैं पहाड़ों पर, सभी नीचे उतर कर उसी रास्ते से जाते हैं । हमने कहा कि डाक्टर पदस्थापित नहीं है, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था कब तक करा दीजियेगा चारों प्रखंडों में, एक समय-सीमा बताया जाय और जहां नहीं है, वहां डाक्टर का पदस्थापन कब तक कराईयेगा ?

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को स्पष्ट किया है कि चेनारी विधान सभा क्षेत्र स्थित नौहट्टा, रोहतास, शिवसागर प्रखंडों में पशु अस्पताल सरकारी भवन में अवस्थित है । शिवसागर में पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक स्थाई रूप से नियुक्त हैं । रोहतास और नौहट्टा के संबंध में हम बताये कि संविदा पर चिकित्सक नियुक्त थे, उसकी संविदा की अवधि खत्म हो गयी है और गर्भाधान के लिये हमने कहा है कि सासाराम में व्यवस्था है ।

श्री ललन पासवान : हमारा इलाका उग्रवाद प्रभावित है और बहुत गरीब इलाका है और अनुसूचित जाति का इलाका है, दलितों की बड़ी आबादी है । वहां गौ पालकों की बड़ी संख्या है।

वहां हमलोगों के जीने का साधन पशु ही है । माननीय मंत्री संविदा पर कह रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि पशु चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति कब तक करेंगे और कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था कब तक करेंगे ?

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, स्थायी नियुक्ति के संबंध में हमने सदन को बताया कि बी०पी०एस०सी० के माध्यम से 903 चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया हो रही है, जैसे ही डाक्टर आ जायेंगे, उनका पदस्थापन किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव जी का पूरक सुन लीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, आप जानते हैं कि कृषि के विकास के लिये पशुधन का विकास बहुत आवश्यक है । इस प्रदेश के अंदर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था, इन्होंने जैसा कहा है, केवल जिला केन्द्र, सासाराम पर है । महोदय, आप जानते हैं कि जिला केन्द्र से विभिन्न प्रखंडों की दूरी कहीं-कहीं तो सौ-सौ किलोमीटर होती है, कहीं 80 किलो मीटर होती है तो कोई व्यक्ति अपने पशु को 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर जिला गर्भाधान केन्द्र पर ले जायेगा तो यह कैसे संभव है ? क्या व्यवस्था हो सकती है ? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था का लाभ किसानों एवं पशुपालकों को मिल सके, इसके लिये और भी केन्द्रों की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बहुत चिन्तित है और सरकार भी बहुत चिन्तित है । कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था सरकार निश्चित करेगी । अभी चूँकि डाक्टर की कमी है तो हम अभी सासाराम में इसकी व्यवस्था किये हुये हैं । जैसे ही हमारे यहां डाक्टरों की नियुक्ति हो जायेगी, हम सभी प्रखंडों में कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1302 (श्री नौशाद आलम)

श्री राम विचार राय,मंत्री : यह आपदा प्रबंधन विभाग को ट्रांसफर्ड है ।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री नौशाद आलम : महोदय, इसका जवाब कब मिलेगा ?

अध्यक्ष : जिस दिन आपदा प्रबंधन विभाग की तिथि होगी, उस दिन इसका जवाब मिलेगा । आप तो पुराने सदस्य हैं । आप तो मंत्री भी रह चुके हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1303 (श्री संजय सरावगी)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड क : स्वीकारात्मक है ।

खंड ख: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के पत्रांक 597 दिनांक 02.03.2017 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुरूप सक्शन-सह-जेंटिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है ।

खंड ग : नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के पत्रांक 597 दिनांक 02.03.2017 के द्वारा प्रेषित किया गया है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा समय-समय पर तीन बार लैंड फिलिंग साईट क्रय हेतु निविदा निकाली गयी, परन्तु वह निविदा सफल नहीं हुआ । पुनः निविदा निकालने की कार्रवाई की जा रही है । लैंड फिलिंग साईट क्रय होते ही परिचालन शुरू किया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि साईट उपलब्ध नहीं है, इसलिए 18 महीने से कम्पैक्टर मशीन खरीद कर रखा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तो शहर में ट्रैक्टर से गिराने के लिये जगह है और कम्पैक्टर मशीन से गिराने के लिये जगह उपलब्ध नहीं है । यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है । महोदय, कूड़ेदान में जनता कूड़ा डालती है और 18-18 लेबर उसको दूसरे दिन खाली करता है और कम्पैक्टर मशीन से वह ऑटोमेटिक उठता है, कूड़ादान भी डैमेज होता है तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रैक्टर से कूड़ा गिराने के लिये जगह है और कम्पैक्टर मशीन से कूड़ा गिराने के लिये जगह नहीं है, क्या यह माननीय मंत्री जी का सही उत्तर है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चिन्तित हैं और सरकार भी चिन्तित है । सच्चाई यह है कि लैंड फिलिंग साईट यदि नहीं था तो कम्पैक्टर मशीन नहीं खरीदी जानी चाहिए थी । कम्पैक्टर मशीन खरीद कर 18 महीने से पड़ा हुआ है । सरकारी पैसे का यह दुरुपयोग है । इसलिये कमिटी बनाकर इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, चूँकि बिना जगह के क्रय करना बहुत ही गलत बात है ।

श्री संजय सरावगी : कार्रवाई के साथ-साथ प्रारंभ कब तक हो जायेगा ? यह मैं जानना चाहता हूँ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1304 (श्री विनोद कुमार सिंह)

श्री राम विचार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य तौर पर राज्य में 5,01,441 हेक्टेअर में दलहन की खेती होती है । वर्ष 2016-17 में 13 लाख 25 हजार हेक्टेअर में दलहनी फसलों की बोआई में 15 लाख 25 हजार मे0टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

खण्ड 2 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि ठंडे मौसम में रब्बी दलहन की खेती की जाती है । राज्य के टाल क्षेत्रों में जनवरी के अंतिम पखवारे में उत्तर भारत में हिमपात के फलस्वरूप मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण छिट-पुट रूप से हरदा रोग का प्रकोप देखा गया । परन्तु तापमान बढ़ जाने से इस रोग से क्षति

की संभावना नहीं हैं। जाड़े के ठंड का विशेष प्रभाव इस बार दलहनी फसलों पर नहीं पड़ा है। दलहनी फसल की कीट व्याधी प्रकोप की सतत् निगरानी एवं संरक्षण कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि पदाधिकारियों के दल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। साथ ही समय-समय पर किसानों के फसल की सुरक्षा हेतु आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य प्रसार माध्यम से सम्यक रूप से अगाह किया जाता रहा है ताकि फसल को क्षति नहीं पहुंच पावे।

खण्ड 3 : उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं। आपने अस्वीकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करते हुये प्रश्न को बहुत हल्का बना दिया है।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री को चुनौती दे रहे हैं। इनके जवाब को चुनौती देंगे न।

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, सदन में बोलने का तात्पर्य वही है।

अध्यक्ष : विनोद जी, माननीय मंत्री जी के जवाब के किस अंश को आप चुनौती दे रहे हैं ?

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि अस्वीकारात्मक है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : विनोद जी, आपके प्रश्न का जो ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें आप ने पूछा है और सरकार जो जवाब दे रही थी, उसमें भी हम देख रहे थे। इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार दलहन की खेती में संभावित नुकसान के लिये किसानों को मुआवजा देना चाहती है ? तो क्या कोई नुकसान संभावित है, उसके लिए आप मुआवजा देते हैं ?

टर्न-6/राजेश/18.3.17

श्री राम विचार राय, मंत्री: नहीं देते हैं।

अध्यक्ष: तो आपके उत्तर में यह कहीं परिलक्षित नहीं था, किसी संभावित नुकसान का तो मुआवजा होता नहीं है, मुआवजा की तो बात ही होती है नुकसान के बाद, इसलिए संभावित नुकसान पर मुआवजा कैसे दे देगी सरकार ?

श्री विनोद कुमार सिंह: महोदय, खेती में जो बिहार के किसानों की क्षति हुई है, तो क्या उसके नुकसान का आकलन करायी है सरकार ?

अध्यक्ष: अगर क्षति हो चुकी है, तो वह संभावित है नहीं, वह तो हो चुकी है, उसका आकलन करके मुआवजा देना चाहिए, वह आप पूछिये न।

श्री विनोद कुमार सिंह: उसका आकलन करके मुआवजा देने का विचार रखती है सरकार।

श्री राम विचार राय, मंत्री: मैंने तो बताया कि सामान्य तौर पर 5,01,441 हेक्टेयर में दलहन की खेती होती है और 2016-17 में 13 लाख 25 हजार हेक्टेयर में दलहनी फसल बोआई तथा 15 लाख 25 हजार मिट्टिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जाड़े की ठंड इस बार फसलों पर नहीं पड़ी है और इसपर कोई असर नहीं पड़ा है, तो मुआवजा का कहां सवाल है इसमें ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिंता तो जायज है, अगर दलहन की खेती करने वाले किसानों की क्षति होती है, अगर उनका नुकसान होता है, तो उसका आप आकलन करा लीजिये और जो मुआवजा देय होगा, वह दीजियेगा ।

श्री राम विचार राय, मंत्री: महोदय, क्षति का आकलन करेगी सरकार ।

श्री विनोद कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसी में हमारा सप्लीमेंटरी यह है कि ठंड के कारण जो दलहन

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आगे भी आप ही का प्रश्न है ।

श्री विनोद कुमार सिंह: ठीक है । महोदय, ठंड के कारण दलहन की खेती में जो कमी आयी है, उस कमी को रोकने के लिए सरकार कोई अनुसंधानात्मक कार्य कराना चाहती है ?

अध्यक्ष: ठीक है । वह सरकार देखेगी । अब आप अगला प्रश्न पूछिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1305 (श्री विनोद कुमार सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: विषयवस्तु अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य सचिव के पत्रांक-6556 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा आदेश निर्गत कर राज्य में 15.11.2016 से धान की खरीद प्रारंभ कर दी गयी थी, इस वर्ष राज्य में धान की अच्छी फसल होने की वजह से अनुमानित उत्पादन लगभग 134 लाख मिट्टिक टन था, धान क्रय की सीमा का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था अर्थात् उत्पादन के अनुरूप कृषक के पास उपलब्ध धान की मात्रा का क्रय किया जाना था लेकिन अग्रणी धान पाँच जिलों में जहाँ पर अग्रणी धान की खेती हो रही थी, उस धान की कटाई पहले शुरू हो जाती, इसीलिए नवंबर, 2015 से वैसे ही पाँच जिलों में धान की अधिप्राप्ति का निदेश दिया गया था और उसके बाद बाकी जिलों में दिसम्बर से धान की अधिप्राप्ति का निदेश दिया गया था लेकिन चूँकि एफ0सी0आई0 द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत मोआईश्चर तक धान में नमी नहीं आने की वजह से धान की अधिप्राप्ति में कठिनाई हुई । बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर और उसकी यानि नमी की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया, कई पत्र लिखने के बाद केन्द्रीय कमिटी आयी, उसने यहाँ का ऑब्जर्वेशन किया और अन्ततः जनवरी, 2019 जब धान में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नमी की मात्रा 17 प्रतिशत आने लगी, तो उस समय केन्द्र सरकार

के द्वारा एक निदेश जारी किया गया, एक परमिशन दिया गया कि 19 प्रतिशत तक की धान की अधिप्राप्ति की जा सकती है सिर्फ इस वर्ष के लिए, जब 17 प्रतिशत मोआईश्चर पहुंचने लगा था, अधिप्राप्ति तेज होने लगी थी, इस वजह से धान की अधिप्राप्ति शुरुआती दौर में कम थी लेकिन आज के दिन में धान की अधिप्राप्ति का दर बहुत अच्छी है, 13 लाख मिट्टिक टन धान की अधिप्राप्ति आज और अभी तक हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय लगभग पौने 12 लाख मिट्टिक टन थी ।

खण्ड 2: उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और राज्य के सभी किसानों को उक्त निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उनके द्वारा उपजाये गये धान का क्रय करके दिया जा रहा है । दिनांक 18.3.2017 को जिस तिथि को माननीय मंत्री जी ने प्रश्न में कहा है कि धान खरीद नहीं होने से बाजार में एक हजार से 1100 रुपये प्रति क्विंटल

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: जरा सुन लीजिये । जो सही जवाब है, उसको तो सुन लीजिये । महोदय, एक हजार से 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय की यह बात है, उस समय धान का मूल्य एक हजार रुपये नहीं बल्कि 900 रुपये से शुरु हुआ था और बाजार मूल्य 900 रुपये था लेकिन धान की अधिप्राप्ति जैसे-जैसे तेज हुई, उसके साथ बाजार मूल्य बढ़कर आज 1350 रुपये क्विंटल हो गया, जो किसानों के लिए लाभकर था और सरकार अधिप्राप्ति भी इसी परपस से करती है कि किसानों को अच्छे मूल्य का बाजार मिल सके.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब हो गया । माननीय मंत्री जी, आप इनका पूरक सुन लीजिये, एक ही साथ जवाब दीजियेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, मुझे पहले प्रश्न का जवाब तो देने दिया जाय उसके बाद ये पूरक पूछेंगे ।

खण्ड 3:- खण्ड: 1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट है ।

श्री विनोद कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तो मेरे बारे में बोला है कि माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, तो लगता है कि हमलोग उधर जल्द जाने वाले हैं और इधर वो आने वाले हैं, खैर यह दूसरी बात है ।

अध्यक्ष: अगर वह आपको हड़बड़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं ?

श्री विनोद कुमार सिंह: नहीं सर । हम हड़बड़ा नहीं रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 31 मार्च, 2017 तक राज्य सरकार को 30 लाख मिट्टिक टन धान का क्रय करना था, तो अब तक कितना क्रय हुआ है और शेष क्या 12-13 दिनों के अंदर सरकार कर लेगी, तो लक्ष्य के अनुरूप तो इन्होंने जवाब दिया नहीं है ।

दूसरी बात हमारा यह है अध्यक्ष महोदय कि पूरे राज्य में 71 लाख किसान हैं और 71 लाख किसानों में मात्र दो लाख किसानों का ही निबंधन हुआ है और जो गैर निबंधित किसान हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है, वह न पूछिये ।

श्री विनोद कुमार सिंह: मैं पूछना चाहता हूँ कि गैर निबंधित किसानों को 1470 रुपया समर्थन मूल्य पैक्स और व्यापार मंडल के द्वारा धान खरीद कराने का विचार रखती है सरकार ?

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, इन्हें पूरक पूछने दीजिये न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष धान की पैदावार अच्छी हुई है और इससे किसानों को बहुत उम्मीद थी कि बिहार सरकार जो भारत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य तय किया था, उसके अनुसार करेगी लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ महोदय, सरकार ने 15 नवंबर को एलान किया कुछ क्षेत्रों के लिए और बाकी लोगों के लिए हम बाद में कार्रवाई करेंगे लेकिन मैं महोदय दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि किसान तो सब बड़े हैं नहीं, काफी परिश्रम, मेहनत करके पूंजी लगाकर काम करते हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: महोदय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार में किसानों ने महोदय बड़ी संख्या में, लगभग 71 लाख किसानों की आबादी है और वहाँ किसान मजबूर हो करके, चूंकि सरकार की व्यवस्था वहाँ पर समय पर नहीं थी, जिसके कारण महोदय एक हजार, 1100 प्रति क्विंटल बेचने के लिए मजबूर हुए, तो क्या सरकार इन बातों की जांच कराना चाहती है और वैसे किसानों को क्या शेष राशि मुआवजा देने का विचार रखती है ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, यह बड़ी ही अफसोस की बात है कि दिनांक 15.3.2017 को इसी सदन में सहकारिता विभाग का बजट पेश हो रहा था, तो हमारे विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यगण का बर्हिगमन हो गया, जिसकी वजह से उन सारे प्रश्नों का

जवाब हमने अपने भाषण के क्रम में दिया था। महोदय, सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, सरकार ने लक्ष्य इसलिए निर्धारित नहीं किया था कि धान की अधिप्राप्ति स्टॉक बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है, धान की अधिप्राप्ति दो कारणों से की जाती है, एक तो हम धान की अधिप्राप्ति करेंगे, उठाव करेंगे, तो बाजार मूल्य उपर बढ़ेगा।

टर्न-7/सत्येन्द्र/18-3-17

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: ताकि सामान्य तौर पर किसान यदि अपना फसल बेचना चाहते हैं, अपने अनाज को बेचना चाहते हैं तो सामान्य बाजार में उनको अच्छा मूल्य मिल सके और जिसकी सफलता हमें मिली कि आज धान का मूल्य 1350/-रु०..

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री:अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, ये अपनी बात बोलकर सुनना नहीं चाहते हैं...

अध्यक्ष: पूरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री:ये दूसरा परपस है महोदय झारखंड में ढाई लाख मे० टन धान की अधिप्राप्ति हुई है। वहां पर मंडी के माध्यम से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति नहीं हुई है महोदय और इस तरह के जितने भी स्टेट हैं, बिहार इतना विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का मतलब है कि मंझोले और छोटे किसानों से इतना ज्यादा धान कहीं देश में नहीं लिया गया और 13 लाख मे० टन ...

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उसे सदन पटल पर रख दिये जायें।

(व्यवधान)

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष: आज दिनांक 18 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं: श्री मिथिलेश तिवारी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विद्या सागर केशरी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री राणा रणधीर, श्री श्याम बाबू प्रसाद, श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री विजय कुमार सिन्हा।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत

नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश पर हम बैठ गये थे ।

अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं । बैठ तो गये थे भूतकाल में, वर्तमान में आप बोल रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : हम कहना चाहते हैं महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलान किया था कि पेपर लीक कांड में यदि किसी मंत्री का नाम आप बतलाईए तो माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा जी का और आलोक कुमार मेहता जी का नाम महोदय आ गया है तो सरकार उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है, नं0-1 और दूसरा महोदय इसकी सी0बी0आई0 जांच से सरकार क्यों भाग रही है ? मामला बहुत आगे बढ़ गया है महोदय.....

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्वायंट ऑफ आर्डर है। उनका सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंह: प्वायंट ऑफ आर्डर है अध्यक्ष महोदय..

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: सुन लीजियेगा उनका भी अध्यक्ष महोदय, हमारा स्पष्ट आरोप है कि सरकार क्यों बचा रही है अपने मंत्रियों को, क्यों बचा रही है लोगों को, सरकार आखिर बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है । इसकी सी0बी0आई0 जांच से नीतीश कुमार क्यों भाग रहे हैं, हमारी मांग है महोदय कि सरकार इसकी सी0बी0आई0 से जांच कराये और मंत्रियों को बर्खास्त करे ।

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता बोलते जरूर हैं बोलना भी चाहिए..

अध्यक्ष: अच्छा बोलते हैं ।

श्री सदानन्द सिंह: हां, अच्छा बोलते हैं विपक्ष के नेता हैं लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे कर देते हैं । ये ऐसे ऐसे क्या होता है और काहे करते हैं, ये संसदीय परम्परा में है क्या ?

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के पिड़ासीन के पास निलांजन नदी में पुल नहीं रहने से सैंकड़ों गांव के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । जनहित में पिड़ासीन के पास निलांजन नदी में पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, बी0एस0एस0सी0 घोटाले में राजद, जदयू, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों व विधायकों के नाम सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है

कि यह घोटाला भाजपा शासित मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले के समान है । मैं इस राजनीतिक संरक्षण की सी0बी0आई0 तथा दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एमएल) एवं भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान जारी)

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के मुकुरिया पंचायत में बाबा गोरखनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है । मंदिर में श्रावणी मेला के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं । मंदिर जाने की सड़क जर्जर होकर इसमें एक-डेढ़ फीट के गड्ढे हो गये हैं । मैं अविलम्ब सड़क बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक घोटाला का दायरा बढ़कर अब ए.एन.एम. नियुक्ति घपला तक पहुंच गया । इस मामले में सरकार के दो कैबिनेट मंत्री, नौकरशाह तथा विधायकों के नाम आने के बाद एस0आई0टी0 से जांच संभव नहीं है । अतः पूरे मामले की जांच सी0बी0आई0 से करायी जाय ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह: अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड में लडौली पीच रोड से पूर्वी गिरी टोला होते हुए जमालपुर पीच रोड तक जाने वाली सड़क काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जिसके कारण आमजनों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है । अतः सरकार उक्त सड़क का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र कराये ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधान-सभा क्षेत्र में अंसारी वर्ग के 20000 बुनकरों की स्थिति, प्रशिक्षण, उत्पादन एवं बिक्री केन्द्र के अभाव में दयनीय हो गयी है । बुनकर भूखों मरने की स्थिति में है । अतः बुनकरों के प्राण रक्षार्थ मधुबनी में प्रशिक्षण उत्पादन एवं बिक्री केन्द्र की स्थापना की जाय ।

श्री अचमित ऋषिदेव: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला में 14 जनरवरी, 2017 से मनरेगा का एम0आई0एस0 लॉक कर दिया गया है जिससे मानव दिवस सृजन में 39 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है । अतः मनरेगा में राशि रिलीज कर मजदूरों को शीघ्र भुगतान करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री मो0 नवाज आलम: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के आरा मुख्यालय में खेल कूद सुबह टहलने एवं अन्य सभा करने के लिए शहर का एक मात्र रमना मैदान है जिसका आधा से ज्यादा हिस्सा अतिक्रमण किया गया है। अतएव मैं सदन के माध्यम से आरा के रमना मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 मार्च, 2016 को जहानाबाद जिला के जहानाबाद अंचल के ग्राम कसई के श्री अवधेश राम श्री रणजीत एवं श्री विजय राम के घर में भीषण आग लगने से घर के साथ साथ सारा सामान जल कर खाक हो गया । श्री अवधेश राम को मुआवजा की राशि दी गयी जबकि अन्य दो को नहीं । अतः शेष दो पीड़ितों की मुआवजा की मांग करता हूँ ।

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, बिहार की बढ़ती आबादी एवं आवागमन की आवश्यकता को देखते हुए नदियों पर पुलों के निर्माण में दूसरे पुलों से 7 कि०मी० की सीमा प्रतिबंध से उत्पन्न बाधा को हटाये । जैसे गांधी सेतु, राजेन्द्र पुल के समानांतर बन रहे पुलों पर ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है ।

श्री जितेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गैर रैयतों से धान अधिप्राप्ति पर रोक लगा दिया गया है जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है । अतः सरकार से मांग करता हूँ कि गैर रैयतों से धान लेने का निर्देश दिया जाय ।

श्री अशोक कुमार सिंह: (नहीं पढ़ा गया)

श्रीमती बेबी कुमारी: अध्यक्ष महोदय, बोचहां विधान-सभा के बोचहां में न्याय मित्र की अभी तक बहाली नहीं हुई है जिसके कारण बोचहां में ग्राम कचहरी का संचालन नहीं हो रहा है इसलिए अविलंब बहाली कर प्रक्रिया आरंभ की जाय ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-8/मधुप/18.3.2017

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारूण प्रखंड में योगिया के पास बटाने नदी का पुल ध्वस्त हो गया है । आम जनता को आवागमन में भारी कठिनाई होती है । अतः मैं सरकार से उक्त ध्वस्त पुल को शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखण्ड के दुलारे पंचायत में कृषि विभाग के जलछाजन योजना अन्तर्गत जल संग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में तालाब निर्माण के लाभुकों के चयन में भारी अनियमितता बरती गई है । योजना के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारी द्वारा योजना का लाभ लिया गया है ।

अतः इसकी जाँच कराकर दोषी लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड के बलभद्रपुर गाँव के पास धर्मावती नदी में लाखों रूपये खर्च कर पुल का निर्माण हुआ है । लेकिन एप्रोच पथ नहीं बनने के कारण उस पुल की कोई उपयोगिता नहीं है ।

सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त पुल के उपयोगिता हेतु PMGSY सेन्दुआर से बलभद्रपुर होते हुए कौआडीह रोड तक पथ का निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री संजय सरावगी ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री सत्यदेव राम ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री विद्या सागर केशरी ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, सारण जिलान्तर्गत वित्तरहित कर्मी, जो वर्तमान में अपनी पन्द्रह सूत्री माँगों की पूर्ति हेतु जगदम्ब कॉलेज, छपरा में धरना पर बैठे हैं, की जायज माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए धरना को समाप्त कराने की दिशा में अविलंब पहल करने हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री अमीत कुमार : महोदय, राज्य में वर्ष 2003 में लोक शिक्षकों के साथ शिक्षामित्रों का नियोजन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया परन्तु 2006 में शिक्षामित्रों को पंचायत शिक्षक का दर्जा मिला, परन्तु लोक शिक्षकों को नहीं मिला ।

अतएव जनहित में लोक शिक्षकों को भी पंचायत शिक्षक के समान ही समायोजित करावें ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

(बेल में व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री अरूण कुमार सिन्हा । ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।
(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री शकील अहमद खॉ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रस्वीकृत सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवांत लाभ दिया जाता है, जबकि बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्रस्वीकृत सरकारी संस्कृत विद्यालयों एवं सरकारी मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवांत लाभ अब तक सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है ।

अतः बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्रस्वीकृत सरकारी संस्कृत विद्यालयों एवं सरकारी मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवांत लाभ दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के इन्टर स्तर तक के विद्यालयों/महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किया जाता है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को ही अनुमान्य सेवांत लाभ दिए जाने का प्रावधान है ।

विभागीय संकल्प संख्या-970, दिनांक-31.08.2013 द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1128 मदरसों एवं 531 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना एवं स्वीकृत महँगाई भत्ता के रूप में सहायक अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई भत्ता यथा सेवांत लाभ आदि अनुमान्य नहीं किया गया है । 205 एवं 609 कोटि के मदरसों में कार्यरत कर्मियों को नियत वेतन अनुमान्य नहीं किया गया है ।

उपरोक्त कोटि के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवांत लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, ऑनरेबुल हाईकोर्ट का यह निर्णय है कि सेम ट्रीटमेंट होना चाहिये गवर्नमेंट के स्कूलों को और संस्कृत शिक्षा बोर्ड और मदरसा के शिक्षकों को । हम तो

आफ्टर रिटारमेंट बेनिफिट के लिये कह रहे हैं कि वे रिटायर के बाद तो रोड पर टहलने लगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है । हाईकोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक हम चाहते हैं उनको भी लाभ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई निदेश है, आप उस आलोक में सारे चीज की समीक्षा करा लीजियेगा । माननीय मंत्री जी देख लेंगे ।

श्री मो० नेमतुल्लाह : ठीक है । धन्यवाद ।

(बेल में व्यवधान जारी)

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-287 (3) के तहत नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भवन निर्माण विभाग से संबंधित प्रतिवेदन में निहित समिति की अनुशंसाओं पर प्रतिवेदन(कार्यान्वयन) संख्या-616, अधिकाई व्यय के विनियमन पर प्रतिवेदन संख्या-618, 619 एवं 621 तथा सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन(सिविल) की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कंडिका पर प्रतिवेदन संख्या-622 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

.....

टर्न-9/आजाद/18.03.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : पथ निर्माण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा ।

इसके लिये 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 59 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 20 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल)	- 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 02 मिनट
निर्दलीय	- 03 मिनट
कुल	-180 मिनट

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

“पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 66,35,90,08,000/- (छियासठ अरब पैंतीस करोड़ नब्बे लाख आठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस माँग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री नितिन नवीन, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती-प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं। इसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

“इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटायी जाय, राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।”

अध्यक्ष महोदय, यह कटौती प्रस्ताव इसलिए भी आवश्यक है कि जब एन0डी0ए0 का कार्यकाल था 2005-10 और 2013 तक, उस समय बड़ी तेजी से सड़क का काम प्रारम्भ हुआ था, जो अब महागठबंधन के बाद महोदय, उसकी या तो गति धीमी हो गई है या उसका जो मेनटेनेन्स है, उसके अभाव में सब रोड जर्जर की स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, इसका जीता-जागता उदाहरण सिवान है, चूँकि हम बराबर जाते हैं, हमारा वहाँ घर भी है। हाजीपुर-छपरा-सिवान शहर जो वर्षों से बन्द पड़ा है, उधर से लोग नहीं जाते हैं बल्कि रेल चक्का कारखाना से होकर जाना होता है। अध्यक्ष महोदय, सड़क के निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता में कमी आयी है। महोदय, शहर, गांव, छोटे-बड़े सड़क, नाला निर्माण का काम, यह सब काम विधायकों के अनुशंसा पर होता था, उसपर भी रोक लगा दी गई है। महोदय, क्षेत्र में विधायक से ज्यादा जिम्मेवार पदाधिकारियों को समझा जाता है, यही सोच में इसको रोक लगा दी गई है। अधिकारी जिसको अनुमोदित करते हैं, वही मुख्यमंत्री करते हैं। महोदय, सड़क निर्माण में हत्या, रंगबाजों के द्वारा बदमाशों के द्वारा हत्या, हमला, रंगबाजी, कर्मियों, मुंशियों, इंजीनियरों पर हमला होते रहता है, धमकी, धौंस मिलता है और गतिरोध इसके वजह से बन गया है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कटौती प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुये बजट में सम्मिलित करें। बोलने के लिए महोदय समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री भोला यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव जो पथ निर्माण से संबंधित है के विरोध में बोलने के लिए आपके अनुमति मिली है, इसके लिए आपको बहुत, बहुत बधाई, बहुत, बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, हमलोग मांग के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हैं। जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर के लिए धमनियों में जो रक्त प्रवाह होती है, वह यदि अपनी गति से तीव्रता से चलते रहती है तो वह शरीर स्वस्थ माना जाता है और जब धमनियों में रक्त प्रवाह धीमी पड़ जाती है, धमनियों में सिकुंडन आ जाता है तो आदमी वह बीमार पड़ जाता है, वह अस्वस्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य के अन्तर्गत यदि सड़कों और सड़कों पर सरपट

दौड़ती हुई गाड़ियां चलती रहे तो यह माना जाता है कि यह राज्य विकसित है । आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय पथ निर्माण मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह से काम हो रहा है, वह काबिलेतारीफ है और पूरे राज्य में स्वस्थ शरीर की तरह पूरा राज्य की सड़कें पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं और इससे यह साबित हो रहा है कि हमारा बिहार राज्य विकसित राज्य के श्रेणी में आ गया है और विकसित है ।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर पुल-पुलिया, रोड का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय डिप्टी सी०एम० साहेब के नेतृत्व में किये जा रहे हैं । कहीं पर भी राज्य के किसी सुदूर इलाके से पटना शहर तक पहुँचने के लिए, राजधानी तक पहुँचने के लिए 5 घंटे का लक्ष्य रखा गया है और 5 घंटे में किशनगंज के भी लोग आसानी से पटना तक पहुँच सकते हैं । इस दिशा में बहुत तेजी से काम हुआ है और कार्य जारी है । मैं बताना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर आज तक 2232 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण किया गया है और चल रहा है। 4021 कि०मी० राज्य उच्च पथ का नवीकरण एवं उन्नयन किया गया है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस गति से राज्य उच्च पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है, नेशनल हाईवे को फोरलेन में परिवर्तित किया जा रहा है, उससे यह साबित होता है कि राज्य में चहुमुखी विकास चारों तरफ हो रहा है । इसके अलावा 13600 कि०मी० से अधिक वृहत जिला पथों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है । महोदय, आवागमन की सुविधा के लिए आवागमन में कहीं कोई बाधा न हो, चूँकि बिहार से होकर के कई नदियां क्रौस करती हैं और कई नदियों का बाढ़ क्षेत्र है । उसको देखते हुये 6700 से अधिक पुलों का निर्माण करवाया गया है और बड़े पैमाने पर पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है । मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा नदी पर भागलपुर-खगड़िया के बीच, बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच, कच्चीदरगाह-बिदुपर के बीच और आरा-छपरा के बीच पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक माईलस्टोन है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर के रूप में साबित हो रहा है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो गंडक नदी पर गोपालगंज जिला के बंगराघाट पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, पूर्वी चम्पारण जिला के सत्तरघाट पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, यह सब चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारें काम कर रही हैं, वह बहुत ही कसीदगी से इस कार्य को पूरा कर रही हैं ।

..... कमशः

टर्न-10/अंजनी/दि018.03.2017

श्री भोला यादव :क्रमशः..... सोन नदी पर भी दाउद नहर नासरीगंज के बीच में पुल का निर्माण कराया जा रहा है । सरकार के द्वारा कई महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है । जैसे-गंगा पथ, गंगा नदी के किनारे-किनारे, पटना शहर के किनारे-किनारे पथ का निर्माण कराया जा रहा है, उससे पटना शहर के अंतर्गत जो जाम की समस्या है, उससे निश्चित रूप से निजात मिलेगा । यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है । दूसरी बात यह कि पटना स्थित जो एम्स अस्पताल बना है, उस अस्पताल से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जल्द ही वह पूरा कर लिया जायेगा, यह अपने-आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ राजधानी क्षेत्र पटना के बिहटा एयरपोर्ट, पटना का जो एयरपोर्ट है, वह काफी छोटा है, उसमें बड़ी जहाज उतरने में बहुत कठिनाई हो रही है । मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना एयरपोर्ट को बिहटा एयरपोर्ट पर ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है तो उस दिशा में भी कार्य हो रहा है । पटना से बिहटा जाने के लिए लम्बी दूरी है, उस दूरी को पार करने के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे के द्वारा पटना और बिहटा को जोड़ने का काम हो रहा है। आने-वाले कल में जब बिहटा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जायेगा तब पटना से बिहटा की दूरी मात्र 20 से 25 मिनट में पूरी कर ली जायेगी । यह बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य के लिए होने जा रही है । आने-वाले कल में इसका प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और कार्य प्रगति पर है । महोदय, पथ निर्माण विभाग का विजन बहुत उंचा है और इसका विजन है उच्च गुणवत्ता, त्वरित निर्माण । आखिर अभी तक जो सड़कें बनती आ रही थी उसमें गुणवत्ता का अभाव रहता था और अब जो सड़कें बन रही हैं उसमें पांच वर्ष के लिए हमलोग देते हैं अगले ठीकेदार को, उसका काम करेंगे, उसका रख-रखाव करेंगे, उसका देखरेख करेंगे ताकि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं आ पाये । इसके लिए उच्च गुणवत्ता और त्वरित निर्माण की कार्रवाई तेजी से चल रही है । महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय ऐसा भी था बिहार के लिए वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक, हम पिछली बात याद दिलाना चाहते हैं, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार थी और केन्द्र में आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए जो पैसा था, उसको रोक दिया गया था । उस समय में मजबूरी में यहां के पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा रोड पर लिखाया गया कि यह पथ भारत सरकार का पथ है । दुर्भाग्य की बात है कि पैसे नहीं रहने के कारण राज्य सरकार बना नहीं पा रही थी और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उस समय लोगों को लगा कि वाकई में भारत सरकार दोहरी नीति अपना रही है, अन्य राज्य को पैसा दे रही है और बिहार को नहीं दे रही है, इसलिए इस बात की जितनी भी निन्दा करनी चाहिए थी लोगों ने की ।

मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है, ठीक है, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी-भी उनका सौतेलापन व्यवहार जारी है। वे कहते हैं कि हम पैकेज देंगे, वे पैकेज देने में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। असत्य वादा कर रहे हैं और बिहारवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं लेकिन उस समय राज्य का संसाधन कम था, आज राज्य का संसाधन पर्याप्त है। शराबबंदी होने के बाद भी हमारे राजस्व में कोई कमी नहीं आयी है, बल्कि हरेक विभाग का बजट बढ़ा है और बड़े पैमाने पर बढ़ा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस गति से नोटबंदी हुआ और नोटबंदी से बिहार के राजस्व में बहुत बड़ी क्षति हुई लेकिन उसके बावजूद भी हमारी राज्य सरकार कृतसंकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृतसंकल्प हैं, माननीय पथ निर्माण मंत्री जी कृतसंकल्प हैं, जो अपने चुनाव के समय में किये गये वादे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में राज्य सरकार प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है।

अध्यक्ष : एक मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी क्षेत्र की बात कुछ रखना चाहता हूँ। इसके लिए दो मिनट का समय दिया जाय, दो मिनट में अपनी बात को रख रहा हूँ। दरभंगा जिला के दोनार-धरौड़ा पथ के 12वें किलोमीटर पर अवस्थित सैनी चौक से डगरशाम-कपछाही-आमापट्टी, गैधरी-सतधारा-दरगाहपुर-दाईभ-उधरा होते हुए खैरा तक जो महादेव देकुली-शंकर लोहार पथ को जोड़ती है, के संबंध में माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उसका पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करके उसका निर्माण कराया जाय। महोदय, दूसरा पथ है- दोनार-धरौड़ा पथ के 11वें किलोमीटर पर अवस्थित चिकनी से फकिला-थलवारा होते हुए तारालाही एस0एच0 तक सड़क को अधिग्रहण कर पथ निर्माण विभाग अपने स्तर से इसका निर्माण कार्य कराये। तीसरा मेरा कहना है कि दोनार-धरौड़ा पथ के नारबोध से मेकना-कपछाही-लक्ष्मीपुर पररी-गोढ़िया-रघेपुरा होते हुए बेता चौक तक के सड़क को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण कर शीघ्र निर्माण कार्य कराये। लहेरियासराय-समस्तीपुर स्टेट हाई-वे के तारालाही से रामपुरडीह होते हुए सिमरी तक के पथ को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण कर इसका निर्माण कार्य कराये। पांचवां है रतनपुरा त्रिमुहान के पास बागमती नदी पर पुल जो दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर के गायघाट, समस्तीपुर के कल्याणपुर को जोड़ती है, उसका निर्माण कार्य कराये। महोदय, अंतिम है कमला नदी पर बराउर-कमलपुर को जोड़नेवाली पथ पर पुल का निर्माण कराये। महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अपने मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी देख-रेख में राज्य बहुत तेजी से प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया)

श्री रत्नेश सादा : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पथ निर्माण विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ । सभापति महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के बजट भाषण के पक्ष में और विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, जब से माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी को संभाला है तब से समाज से लेकर और 51वों विभाग में, सभी विभागों में तरक्की-ही-तरक्की हुई है । वर्ष 2006 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और एकल पद पर आरक्षण देकर समाज में लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया । महोदय, इतना-ही-नहीं, महादलित लड़के-लड़की को टोला सेवक, विकास मित्र बनाकर इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक संसाधन जुटाने का काम किया और इतना-ही नहीं, जो भूमिहीन महादलित लोग थे उनको तीन डिसमिल से पांच डिसमिल जमीन देने का काम किया । यह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की देन है । महोदय, लालू प्रसाद जब से मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरूबा के मुंह में आवाज देने का काम किया है। यह देन अगर गरीब गुरूबा के मुंह में आवाज आज है तो वह लालू प्रसाद की ही देन है और सत्ता में भागीदारी और इम्प्लीमेंट कराने का काम माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने किया है।

.....कमश:.....

टर्न-11/शंभु/18.03.17

श्री रत्नेश सादा : कमश:.....महोदय, मैं पथ निर्माण मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 2005-06 से लेकर 2017 तक जितना भी उद्ब्यय था उसमें 74 प्रतिशत खर्च करने का काम किया है। महोदय, राज्य निधि से 2232 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण किया और इतना ही नहीं राज्य निधि से 2104 कि०मी० राज्य उच्च पथों का राष्ट्रीय समविकास योजना से निर्माण किया। महोदय, इतना ही नहीं 1072 कि०मी० राज्य उच्च पथों को ए०डी०बी० सम्पोषित 2 लेन की योजना का निर्माण किया, 845 कि०मी० नवीकरण किया। महोदय, गुरू गोविन्द सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव में माननीय मुखिया नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री के द्वारा 36 परियोजना में 97.33 करोड़ खर्च किया। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 78.72 करोड़ रेलवे के उपरी पुल का निर्माण कार्य किया। हरमंदिर तक अशोक राजपथ का सौंदर्यीकरण किया। महोदय, आज 15 राज्य उच्च पथ एवं वैशाली कोरीडोर में कुल लगभग 891.44 कि०मी० 2 लेन का प्रस्ताव परिवहन एवं राजमार्ग

मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। महोदय, भारत-नेपाल सीमा परियोजना एवं 6 लेन गंगा ब्रिज कच्ची दरगाह-बिदुपुर के भूअर्जन का काम हो रहा है। सभापति महोदय, विश्व बैंक से संपोषित योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-104 शिवहर, सीतामढ़ी, जयनगर, नरहरिया एवं एन०एच०-106 बीरूपुर, बिदुपुर एवं एन०एच०-30(ए) फतुहा, हरनौत, बाढ़ एवं एन०एच०-98 अनीसाबाद, औरंगाबाद, हरिहरगंज तक 509 करोड़ औसतन कार्य प्रस्ताव भेज दिया गया है। महोदय, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से 2005-06 से 2015-16 तक 89 करोड़ 71 हजार 36 हजार की लागत से 673 बड़े एवं छोटे पुलों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 31 हजार 43.2 करोड़ की लागत से 534 योजनाओं को पूर्ण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बिहार के विश्वकर्मा हैं, उन्हीं के चलते आज बिहार में चहुंमुखी विकास हुआ है- चाहे वह पुल पुलिया की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ग्रामीण विकास हो, पशुपालन हो, युवा एवं कला हो चाहे जो विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो सभी विभाग में माननीय मुख्यमंत्री की देन है कि पूरे बिहार में आज काम प्रगति पर है। महोदय, इतना ही नहीं सड़क, पुल, पुलिया बन जाने से बेरोजगार लोग, बेरोजगार युवक रोजगार के तलाश में रहते थे। आज सड़क, पुल, पुलिया बन जाने से गांव घर में नौजवान लोग रिक्शा, टेम्पू, ठेला एवं अन्य तरह के बिजनेस करके स्वरोजगार उपलब्ध करा लिये हैं, अगर यह देन है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। महोदय, इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री के बनने के बाद महत्वपूर्ण परियोजना को चालू किया गया। इतना ही नहीं एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने का काम किया गया। महोदय, अगवानी घाट में पुल, गंगा नदी पर पुल 1710.77 करोड़ की लागत से सोन नदी में पुल, 619.28 करोड़ बंगरा घाट पर 5897, गंडक नदी पर पुल 1440 की लागत से 263.48 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया। इतना ही नहीं सहरसा जिला जो हमलोग आज तक आजाद नहीं हुए थे, कोशी नदी पर पुल बनाकर 531 करोड़ की लागत से पुल जो इन्होंने बनाया, हमलोग आज तक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री का कृपा हुआ- उन्होंने 2 कि०मी० के 531 करोड़ का पुल बनाकर के आज कोशी वासी को नया जीवन देने का काम किया। इतना ही नदी गंडल और बिरौल चौक में हाथी कोठी के अंदर 332 करोड़ की लागत से पहुंच पथ एवं पुल का निर्माण करा रहा है। दरभंगा-सहरसा का सीधा संपर्क हो गया है। किसी संत की वाणी है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आपका मात्र 1 मिनट समय बचा है।

श्री रत्नेश सदा : महोदय, हमारे मुखिया नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री कभी झूठ नहीं बोले हैं, जुमलेबाजी नहीं किये हैं। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं 2014 के लोक सभा चुनाव में तरह-तरह का लोभ देकर युवाओं को ठगने का काम किया, ग्रामीणों को ठगने का काम

किया और यूँ ही वादे करके जब इनकी सरकार बन गयी तब इन्होंने कहा कि यह तो जुमला था। जब ये मोतिहारी में आये तो कहा कि हम विशेष पैकेज देंगे। ऐसे करके कहते थे कि कितना लगे ? 1 करोड़, 2 करोड़ 140 करोड़ मैंने दिया, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। इन्होंने प्रत्येक भारत के लोगों को कहा था कि सबके खाता में 15 से 20 लाख रूपया देंगे, लेकिन आज तक 15 पैसा कहीं नहीं मिला है।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, इतना ही नहीं आज किसानों का ठगकर के उत्तर प्रदेश में जो वोट लेने का काम किया है, जुमला दिखाने का काम किया है, कहा कि हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो हम कर्ज को माफ कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वही हाल होगा और कहेंगे जुमला है। हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री कभी असत्य नहीं बोले हैं, असत्य का कभी सहारा नहीं लिये हैं।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये।

डा० सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं बिहार के विकास की ढोल पीटनेवाली सरकार के पथ निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर सरकार के कथनी और करनी फर्क नहीं होता तो मैं इस सदन में कटौती प्रस्ताव के प्रति बोलने के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन यह सरकार सिर्फ मीडिया के माध्यम से विकास का ढोल पीटकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन, जमीन पर कहीं काम नहीं होता। 2015 के विधान सभा चुनाव के दौरान आनन-फानन में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए गंगा नदी पर दीदारगंज राघोपुर पुल का निर्माण करने की घोषणा की, 6 लेन का ग्रीन फिल्ड पुल का निर्माण करने का शिलान्यास 23.08.2015 को किया, फिर सरकार बनने के बाद 25.07.2016 को कार्य प्रारंभ करने का शिलान्यास किया, लेकिन आज तक इस योजना में शिलान्यास के बोर्ड के अलावे पांच रूपया भी नहीं लगा। आज हर रोज मीडिया के माध्यम से गंगा पर बने पीपा पुल के बारे में न्यूज आता है कि रौशनी के कारण वह सड़क बाधित है, लेकिन सरकार के कान में जूँ नहीं रेंगता है। आज भी अखबारों में उसका आर्टिकल था। आज हर रोज मीडिया के माध्यम से खबर आती है कि पूरे राज्य में बिछेगा नये सड़कों का जाल, कभी आता है स्टेट हाइवे और जिला पथ होंगे और चौड़े, कभी आता है 10 हजार कि०मी० सड़क 5.5 मीटर चौड़ी होगी। क्रमशः

टर्न-12/अशोक/18.03.2017

डा० सुनील कुमार : क्रमशः कभी आता है पांच घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना, बिहार की राजधानी पहुंच सकते हैं। सभापति महोदय, सिर्फ पटना से निकलने में डेढ़ से दो घंटा लगता है। अभी एक मौका मिला मुझे, मैं बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ रजौली की दूरी 60 कि.मी. है, रजौली की दूरी 60 कि.मी. है

(व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): माननीय सदस्यगण, बैठे बैठे टिका-टिप्पणी न करें, इनकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनें, आप की बात भी सुनी जायेगी ।

डॉ सुनील कुमार : रजौली 60 कि.मी. हैं एक फंक्शन में जाने का मौका मिला, दो घंटे लगे मुझे सभापति महोदय । दो घंटे लगे, 60 कि.मी. की दूरी में दो घंटा लगता है, सरकार कैसे कहती है कि पांच घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सकते हैं । आज जो भी सड़कें अगर आप को अच्छी दिख रही हैं, वह केन्द्र सरकार के द्वारा बनाई गई है, चाहे पटना से बख्तियारपुर की सड़क हो या अन्य सड़क हो । सभापति महोदय,

(व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): माननीय सदस्य, इनकी बात को सुनिये आप सब, बैठे बैठे टिका-टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ।

डॉ. सुनील कुमार : कई माननीय सदस्यों के द्वारा टिका-टिप्पणी की जा रही है, मैं आपको दो पंक्ति कहता हूँ हमारी ताकत का अंदाजा हमारे जोश से नहीं, विरोधियों के सोच से पता चलता है । अभी बिहार राज्य में जो भी योजनायें चल रही हैं वह केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित है, जो पैकेज दिया गया था , अभी सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पैसे नहीं दिये हैं- बिहारशरीफ-बरबीघा-एनएच-82 का मोकामा तक 55 कि.मी. का सड़क में 399 करोड़ रूपया दिया गया । एनएच-30 पटना से कोईलवर- 33 कि.मी. की सड़क में केन्द्र सरकार द्वारा 492 करोड़ रूपया दिया गया, एनएच0-30 तथा एनएच-84 के कोईलवर-भोजपुर में 44 कि.मी. सड़क के लिए 750 करोड़ रूपया दिया गया, भोजपुर से वक्सर सेक्शन चार लेन के सड़क के लिए 48 कि. मी. में 595 करोड़ रूपया दिया गया, बख्तियारपुर-मोकामा सेक्शन में 45 कि.मी. सड़क में 970 करोड़ दिया गया, मोकामा मे गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए 520 करोड़ रूपया दिया गया, सिमरिया-खगड़िया 4 लेन में 1062 करोड़ रूपया दिया गया, फतुहा-हरनौत बाढ़ सेक्शन में 71 कि.मी. में 591 करोड़ रूपया दिया गया, शिवहर-सीतमढ़ी -जयनगबर-नरहिया रोड में 701 करोड़ रूपया दिया गया, एनएच 106 के बीरपुर-बीहपुर में 575 करोड़ रूपया दिया गया, गोपालगंज-छपरा सेक्शन में 748 करोड़ रूपया दिया गया, छपरा-रेवाघाट- मुजफ्फरपुर को पक्का कर दो लेन करने के लिए 73 कि.मी. की सड़क में 420 करोड़ रूपया दिया गया । अभी भी कई योजनायें जिसकी स्वीकृति के लिए लम्बित है जिस पर जल्द ही केन्द्र सरकार के द्वारा...

श्री मो0 इलियास हुसैन : आपके माध्यम से माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार ने पिछले कई वर्षों से लगातार इनके पथ, नेशनल हाई वे पर 1000 करोड़

जो खर्च कर दिये हैं वह अभी तक भारत सरकार उस पर चुप्पी लगाकर क्यों बैठी है ?

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): ठीक है, आप बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, यह कांग्रेस रिजिम की बात है, इसके लिए महागठबन्धन से न बात कीजिए । (व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): प्लीज, माननीय सदस्य संजय जी आप भी बैठ जाइये । माननीय सदस्य, आप दोनों बैठ जाइये । डॉ० सुनील कुमार को बोलने दीजिये ।

डॉ० सुनील कुमार : सभापति महोदय, इस तरह से केन्द्र सरकार ने, इस तरह से केन्द्र सरकार ने (व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): आप अपनी सीट पर बैठिये, सुनिये उनकी बात । बैठिये, प्लीज बैठिये, उनकी बात सुनिये आप । आपकी बारी जब आयेगी तो आपको बोलने दिया जायेगा, आप अपनी बात रखेंगे । प्लीज, संजय जी ।

डॉ० सुनील कुमार : इस तरह से भारत सरकार ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए काफी मदद कर रही है लेकिन यह सरकार न तो केन्द्र सरकार के सहयोग का नाम लेती है, बल्कि अपना पीठ थपथपाती रहती हैं । अभी हाल के दिन में बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सात निश्चय की यात्रा करा रहे थे, बिहार सरकार यहां की जनता को झांसा देने से बाज नहीं आ रही है । चुनाव के पूर्व बिहार के युवाओं को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जब सरकार बन गई तो कहा कि जो स्टूडेंट आई.एस.सी, आई.ए. पास किया और आगे (व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): प्लीज, आप बैठे बैठे न बोलें, इनकी बात को सुने । नो नो, आप, प्लीज सीट डाऊन, सीट डाऊन प्लीज, प्लीज सीट डाऊन, नो-नो, बोलिये आप।

डॉ० सुनील कुमार : इन्टर पास करने वाले को जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे उन्हीं को बरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । जो बी.ए., बी.एस.सी., पॉलिटिकल, इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिये रहेंगे तो उनको यह भत्ता नहीं दिया जायेगा, यह घोषणा करना था तो यह चुनाव के पहले न घोषणा करना था, इन्होंने टारगेट भी रखा कि 17 लाख युवाओं को यह भत्ता दिया जायेगा लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 20 हजार युवाओं को भी ये भत्ता नहीं दिया गया, चुनाव के पहले कहा गया कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे, और बिना किसी गारन्टी के 4 लाख रूपये विद्यार्थियों को मिलेगा, यह भारत सरकार की योजना है, यह भारत सरकार की योजना है, जिसको कहते हैं शिक्षा ऋण योजना । जिसके अन्तर्गत स्टूडेंट को बिना किसी...

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): एक मिनट डाक्टर साहब ।

श्री श्याम रजक : बरोजगारी भत्ता की कोई योजना नहीं, बल्कि राज्य सरकार का सात निश्चय जो था, है, उसमें है स्वयं सहायता भत्ता, बरोजगारी भत्ता नहीं है, लेकिन माननीय जो

सदस्य हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक ही कहा हमारे इलियास साहब ने कि केन्द्र सरकार ने हमारे पथ के लिए पैसा नहीं दिया । अभी आप जायेंगे यहां से फुलवारी होते हुये एम्स होते हुये....

(व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): माननीय सदस्य आपको भी मौका मिलेगा । प्लीज । श्री संजय जी, प्लीज, संजय जी, आप बैठ जाईये । बैठये ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): आदरणीय सदानन्द बाबू खड़े हैं ।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, मैं प्वायंट ऑफ इनफॉर्मेशन पर हूँ । पता नहीं, भाषा विधान सभा की हिन्दी है, सीट डाऊन कभी कभी न कह कर बैठिये कहिये, लेकिन हम कह रहे हैं कि संजय जी क्यों इतने उतावले हो जाते हैं, क्यों आप आवेश में आ जाते हैं, आप कूल रहिये, आप कूल रहिये विधान सभा में, कूल रहिये ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): डॉ साहब आप बोलिये ।

श्री संजय सरावगी : माननीय सदस्य मेरा नाम लेकर बोलें हैं, हम आवेश में नहीं आते हैं ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): वे काफी सिनियर लोग हैं, वे काफी सिनियर हैं । संजय जी, कोई बात आपके खिलाफ नहीं कहा गया है । प्लीज संजय जी, आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है।

डा० सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के दो सदस्यों ने अपनी विचार रखें हमलोगों ने कोई टिका-टिप्पणी नहीं किया और जब मैं विचार रखने लगा तो इनको कडुवा लगने लगा ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): अब आपका एक मिनट का समय बचा है ।

डा० सुनील कुमार : महोदय, मेरा समय तो बर्बाद कर दिया गया, मुझे समय दिया जाय । बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए टारगेट रखा था पांच लाख लेकिन अभी तक 100 स्टूडेंट को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिला । बिहार सरकार ने एक योजना चलाई घर-घर शौचालय की, यह प्रधान मंत्री ग्राम्य स्वच्छता अभियान की योजना है जिसका नाम बदला गया, 2016-17 में बिहार सरकार ने टारगेट रखा 40 लाख शौचालय बनाने का अभी तक 4 लाख भी नहीं बना पाये । 2 अक्टूबर, 2019 तक बिहार में डेढ़ करोड़ शौचालय बनना हैं ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल): मात्र एक मिनट का समय रह गया है ।

डा० सुनील कुमार : सभापति महोदय, हर घर में नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण करने का सुभारम्भ किया लेकिन आज तक ...क्रमशः

टर्न-13/ज्योति

18-03-2017

क्रमशः

डा0 सुनील कुमार : लेकिन आजतक..

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): अब आप दोनों आदमी बैठिये । संजय जी आप भी बैठिये।

डा0 सुनील कुमार : आजतक इसमें पैसे नहीं दिए जिसके कारण यह योजना शुरू भी नहीं हो पायी, कौशल प्रशिक्षण.....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, डा0 सुनील कुमार जी, अब आपका समय समाप्त हो गया।

डा0 सुनील कुमार : सभापति महोदय, हमारे समय को बर्बाद कर दिया गया, मुझे दो मिनट समय दीजिये अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में कहने के लिए । एन0डी0ए0 गठबंधन के समय में बख्तियारपुर से लेकर बिहार शरीफ होते हुए रजौली तक 4 लेन की स्वीकृति दी गयी थी । आज तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ । एन0एच0 31 बख्तियारपुर से बिहार शरीफ के बीच में भागनबिगहा और बेना में दो बाजार है एन.एच. 31 के बगल में नाले का निर्माण नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में हर साल सड़क खराब हो जाती है । इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इन सब बाजारों के बगल में, एन.एच. के बगल में, नाले का निर्माण कराया जाय । बिहार शरीफ सड़क में 15 से 18 फीट चौड़ी सड़कों में बीच में डिवाइडर दे दिया गया, अब वहाँ पर गाड़ियां चलती नहीं हैं, रेंगती हैं अगर ठेला भी आगे आ जाय तो उसके पीछे पीछे पाँच कि.मी. आपको चलना पड़ेगा ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): माननीय सदस्य अब आप बैठ जाईये । प्लीज बँठिये ।

डा0 सुनील कुमार : इस प्रकार विकास का ढोल पीटने वाली सरकार का कोई भी विकास का वीजन नहीं है । सभापति महोदय, इसीलिए मैं पथ निर्माण विभाग के बजट के कटौती की वकालत करता हूँ ।

श्री विजय शंकर दूबे : सभापति महोदय, राज्य के पथ निर्माण मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण विभाग के संबंध में 66 अरब 35 करोड़ 90 लाख 8 हजार रुपये से अनधिक राशि का डिमान्ड लेकर सदन के समक्ष आए हैं जिसपर चर्चा हो रही है । मैं डिमान्ड के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, डिमान्ड के पक्ष में बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री एक साल से, डेढ़ साल से इस विभाग को देख रहे हैं । उनको जिज्ञासा है, क्षमता बढ़ाये हैं । इस वर्ष के कर्णांकित राशि का 74 प्रतिशत पैसे दिसम्बर तक खर्च कर चुके हैं । इसलिए वकालत करता हूँ कि उनके डिमान्ड

से अधिक राशि पथ निर्माण विभाग को दिया, जाय उप मुख्यमंत्री सक्षम हैं राज्य के पथों का जीर्णोद्धार करने के लिए, निर्माण करने के लिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सड़कें पहले की भी सरकारें बनाती रही हैं और राज्य के संसाधन के अनुसार बिहार के पथ निर्माण विभाग की सड़कें बनती रहती हैं। अनेक सरकारें आयीं। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं और सभी सरकारों ने अपनी क्षमता के हिसाब से पथ का निर्माण किया।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल): माननीय सदस्या, भागीरथी जी बैठे बैठे नहीं बोलना है, सुनते रहिये। आपको भी बोलने का मौका लगेगा तो बोलियेगा।

श्री विजय शंकर दूबे : सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2005 से औनवर्ड नीतीश कुमार की हुकूमत, जब से राज्य में सरकार अस्तित्व में आयी है पथ निर्माण विभाग सहित सभी क्षेत्रों में और मैं नही केवल कह रहा हूँ। हम गठबंधन के सहयोगी हैं। महागठबंधन की हुकूमत है। देश मानता है कि नीतीश कुमार की हुकूमत ने राज्य में चहुंमुखी विकास किया है। बिहार आगे बढ़ा है। बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों राज्य में प्रकाशोत्सव महोत्सव पटना सिटी में मना। देश की जिज्ञासा लगी थी, देश जानना चाहता था कि इतनी बड़ी संख्या में दुनिया भर के सिख समुदाय के लोग आयेंगे, अंतिम गुरु की दर्शन करने, पूजा करने तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी? सरकार भी चिन्तित थी। साधन, संसाधन सीमित थे लेकिन नीतीश कुमार की हुकूमत ने पथ निर्माण विभाग ने उस महोत्सव के अवसर पर ऐसा काम किया - 36 परियोजनाओं पर 97.33 करोड़ और पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास से ऊपरी पुल परियोजना पर 78.72 करोड़ रुपये का व्यय करके एक इतिहास कायम किया। समय सीमा के अंतर्गत सारी योजनाओं को पूरा किया और बिहार के आतिथ्य की सराहना दुनिया में हुई। मुख्यमंत्री सम्मानित हो रहे हैं पंजाब में और वह केवल मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं है, मेरा मानना है कि बिहार का सम्मान है और बिहार सम्मानित हुआ है। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री को डिमान्ड से अधिक पैसा इसलिए भी मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक हैं। पिछले समय सदन में मार्च के महीने में इसी मार्च में मैंने सवाल उठाया कहलगांव का, छपरा का, किशनगंज का सिर्फ मैंने यहाँ सवाल उठाया सदन में सड़कों के बारे में, माननीय सदस्या कृपया चुप तो रहिये।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): माननीय सदस्या भागीरथी जी बार बार आपसे कह रहे हैं, बैठे बैठे नहीं बोलना है। बार बार कह रहे हैं कि बैठे बैठे नहीं बोलना है।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि वह तीन डिस्ट्रीक्ट के सड़कों के बारे में मैंने चर्चा की। उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में नोट किया उसकी परिणति हुई कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। रोड बनना आवश्यक था कहलगांव का रोड, छपरा सिवान का रोड, एकमा से लेकर के परसा होते हुए चेतन छपरा तक का पथ, बसडिल्ला से जलालपुर होते हुए शाहपुर तक का पथ इन सारे पथों का जीर्णोद्धार का काम और प्लान हेड में रख करके तीनों सड़कों के निर्माण की दिशा में उप मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार हुकूमत ने कार्रवाई की। आवंटन दिया, काम प्रारम्भ होने की स्थिति में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महोदय, उप मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र में सदन सर्वोपरि है। मैं उदाहरण देकर मेरा समय समाप्त हो जायेगा मुझे और कुछ आवश्यक अपना निवेदन भी करना है महोदय, लेकिन अन्य सदस्यों का केवल मेरा ही नहीं अन्य सदस्यों का भी चाहे वे किसी भी दल के वह सदस्य हों जो जेन्वीन मामला था, मसला था रोड के संदर्भ में भाषण किया कहा, निवेदन किया सदन में, उप मुख्यमंत्री ने टेक अप किया और सीमित संसाधनों में उप मुख्यमंत्री ने उसको बनाने की दिशा में आगे कार्रवाई की है। नीतीश कुमार की हुकूमत ने पैसे की व्यवस्था की है इसलिए महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग की सड़कें, हमारी जितनी सड़कें हैं उतनी धन राशि जितना डिमान्ड बिहार सरकार से केन्द्र सरकार से अधियाचना की गयी है वह पैसे पर्याप्त मिल नहीं पा रहे हैं जिससे सड़कों के निर्माण की दिशा में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्रमशः

टर्न-14/18.3.2017/बिपिन

श्री विजय शंकर दूबे : क्रमशः गंगा पुल परियोजना- केन्द्र सरकार ने अनेक बार आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया। पैसा देने की बात कही गई भारत सरकार से। पैसे मिल नहीं सके जिसके कारण गंगा ब्रीज की स्थिति वैसा ही पड़ा हुआ है। वह एन.एच. का रोड है। भारत सरकार के पैसे से बना हुआ मार्ग है। मरम्मत नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में और भारत सरकार ने जितने पैसे का कमिटमेंट किया था, हाल ही में उप मुख्यमंत्री जब गडकरी साहब से मिले थे। जो आश्वासन मिला, लगा की रोड बन जाएगा। प्रधानमंत्रीजी उसका शिलान्यास करने वाले थे, नहीं हो पाया। काम जिस गति से होने वाली थी, नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा है। यह महोदय स्थिति है। मैं भारत सरकार से और भाजपा के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी जिज्ञासार्त हैं, आप भी चाहते हैं, आपको भी सहयोग प्राप्त है कि बिहार आगे बढ़े, रोड की दिशा में हमारी समृद्धि हो। हम विकसित राज्य तभी कहे जाएंगे जब रोड के

मामले में, मार्ग के मामले में हम अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ेंगे। आपका भी सहयोग अपेक्षित है कि सरकार का सहयोग करें और केन्द्र सरकार से जो अपेक्षित धनराशि है, जो डिमांड है बिहार सरकार की, उसकी पूर्ति की जाए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथियों।

महोदय, अब हम अपने क्षेत्र का और जिले की बात करना चाहता हूँ। छपरा से बसडिल्ला से जलालपुर होते हुए शाहपुर पथ की ए.ए. हो चुका है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो गया, टेंडर हो गया, मांझी से लेकर जयछपरा पथ का टेंडर हो गया, एकमा से लेकर चेतनछपरा पथ का टेंडर हो चुका है। काम प्रारंभ होने वाला है। मैं उपमुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने समेकित रूप से वैशाली कॉरिडोर का एक जगह सारे वैशाली में बनने वाले पथों का शुभारंभ किया था, वैसे ही छपरा में, छपरा भी आपका राजनीतिक विरासत है

(व्यवधान)

आपका भी होगा। तो महोदय, वहां

(व्यवधान)

सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि उपमुख्यमंत्री छपरा में, छपरा जिला की और सिवान का, गोपलगंज का और रोहतास का भी शामिल करिए लेकिन रोहतास कहां है और छपरा कहां है

(व्यवधान)

सभापति(श्री राम नारायण मंडल): माननीय सदस्य बैठिये।

श्री विजय शंकर दूबे: तो महोदय, मैं आग्रह कर रहा था उपमुख्यमंत्री से कि छपरा में वैशाली की तरह सारे पथों का एक बार शुभारंभ करें। राज्य के अन्य हिस्सों में दक्षिण की जो सड़कें- सासाराम की सड़कें हैं, कैमूर की सड़कें हैं, बक्सर की सड़कें हैं, आरा की सड़कें हैं, उधर जितनी स्वीकृति हुई है उसका

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): मान्यवर दूबे जी, सामने आसन की ओर देखिए।

श्री विजय शंकर दूबे: तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार की हुकूमत संकल्पित है और स्वयं नीतीश कुमार बिना किसी भेदभाव के, मैं तो कभी-कभी मजाक में कह दिया करता हूँ कि भाजपा वालों पर भी पूर्ववत् आपकी दृष्टि बनी रहती है, उनका भी काम करते हैं, उनका भी काम हो और मुख्यमंत्री जब मिटिंग में बैठते हैं...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): मजाक में मत कहिए, सही-सही कहिए।

श्री विजय शंकर दूबे : मुख्यमंत्री जब मिटिंग में बैठते हैं, किसी भी माननीय सदस्य के मसले पर, वह चाहे दल किसी का हो, राज्य की विकास की बात करता है। किसी भी दल के

सदस्य हों, उसपर मुख्यमंत्री का ध्यान जाता है और मुख्यमंत्री एकनॉलेज करते हैं और योजना को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई करते हैं ।

महोदय, छपरा की अन्य सड़कें, जो एन.एच. की सड़कें छपरा, सिवान, गोपालगंज की है जो समय-सीमा के अंतर्गत पूरा हो जाना था, पैसे भी उपलब्ध हैं लेकिन उपमुख्यमंत्री जी से मैं ...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): माननीय दूबे जी, आप तो राज्य स्तर के नेता हैं, राज्य स्तर पर बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री विजय शंकर दूबे : वो समय-सीमा के अंतर्गत पूरा हो । उसको देख कर उसको जल्दी पूरा करावें । इसके अलावे राज्य की अन्य सड़कें जहां राशि कर्णांकित है, सरकार ने पैसा दिया है, समय-सीमा निर्धारित है, वहां कांट्रैक्टर के वजह से काम पूरा नहीं हो रहा है । निरीक्षण और पर्यवेक्षण के वजह से काम की गुणवत्ता बरकरार नहीं होती है । वहां उपमुख्यमंत्री का ध्यान जाना चाहिए, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं ।

महोदय, भवन निर्माण विभाग भी उपमुख्यमंत्री देखते हैं । वह गिलोटिन में है। पटना में माननीय सदस्यों का, किसी भी माननीय सदस्य का जो क्वार्टर आर्बिट्रिट है, एक बात आपको देखना होगा, सब मकान के ठीकेदार कब्जा किए हुए हैं । वही बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा और उसकी गुणवत्ता का स्वयं बनाएंगे, उनकी गुणवत्ता का भी देखरेख और मापदंड वही करेंगे, बिल वही बनाएंगे, भुगतान भी वही करा लेंगे । इस मोनोपोली को समाप्त करें । मकान की गुणवत्ता बनी रहे और मकान समय-सीमा पर पूरा हो, इस बात को आप जरूर करें । आप नौजवान उप मुख्यमंत्री हैं । आपसे राज्य को अपेक्षा है । यह पटना में राजधानी में नाक के नीचे अगर व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी, ठीकेदारी सिस्टम को अगर स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकेगी तो मैं समझता हूं कि आगे इस काम को करने में कठिनाई होगी । मामला और जटिल होता जा रहा है । माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल के हों, परेशान हैं । उनके पानी की व्यवस्था भी भवन निर्माण में आ गया । जो पानी पीते हैं माननीय सदस्य और उनके क्षेत्र के लोग, पटना में कई मकान में पीले पानी आ रहे हैं । वाटर सप्लाई के स्कीम को भवन निर्माण को ही देखना है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसको दुरूस्त करावें । इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, जो सरकार

(व्यवधान)

मच्छर पी.डब्ल्यू.डी. नहीं मारता है । छिड़काव की व्यवस्था माननीय सदस्यों के फ्लैट में जो इलाका है, जहां माननीय सदस्य रहते हैं, जहां अधिकारी-पदाधिकारी रहते हैं, छिड़काव का जो सिस्टम था, बंद हो गया । वह कभी-कभी रोड पर देखा जाता है कि छिड़काव होता गया, गाड़ी आगे बढ़ती गई, पीछे से धुंआ निकलता चला गया । वह

केवल ऑपचारिकतावश है । मच्छर मरते नहीं है । उसकी भी सरकार व्यवस्था करे । इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, सरकार जो डिमांड लेकर के उप मुख्यमंत्री आए हैं, उनके डिमांड का समर्थन करते हुए, पुरजोर समर्थन करते हुए भाजपा के माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव लाए हैं, उनको वापस करने का अनुरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं । धन्यवाद महोदय । सभापति जी ने बोलने का अवसर दिया, मैं आसन के प्रति अनुग्रहित हूँ । धन्यवाद ।

टर्न : 15/कृष्ण/18.03.2017

श्री मो० नवाज आलम : सभापति महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के प्रस्तुत अनुदान मांग के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ । महोदय, पथ निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसको लाईफ लाईन के रूप में जाना जाता है। महोदय, चाहे पूरा प्रदेश हो या पूरा देश हो, अगर किसी राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जायेगा तो उसमें पथ निर्माण विभाग ही सबसे अधिक अहम् विभाग के रूप में जाना जाता है । आदरणीय मुख्यमंत्री और जन-जन के नेता डिप्टी सी०एम० पथ निर्माण विभाग के मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने पथ निर्माण विभाग का जो चौमुखी विकास किया है । उसके बारे में हमें लगता है कि हमलोग जिस जगह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यह चर्चा का विषय बनता है कि लगभग सवा साल में जिस तरह से पथ निर्माण विभाग ने प्रगति किया है, चाहे वह भवन निर्माण विभाग का मामला हो, तमाम जो विकास की श्रेणी में हर पहलू पर लाने का काम किया है, उसके लिये मैं अपनी ओर से और पूरे आरा जनपद की ओर से, पूरे बिहारवासियों के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री और जन-जन के नेता श्री लालू यादव जी को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे युवा कर्मठ और एक तेजतर्रार तेजस्वी यादव जी को आपने इस तरह का विभाग का प्रभार दिया है । किसी ने ठीक ही अच्छे ढंग से कहा है कि

“हजारों साल नर्गिस अपने बेनूरी पर रोती है

बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ।”

महोदय, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक तेज तर्रार युवा तुर्क नेता भाई तेजस्वी यादव को आपने पथ निर्माण विभाग का प्रभार दिया है, सचमुच में एक नये स्वरूप में, नये उज्ज्वल के साथ आप एक दीदावर के रूप में पैदा हुये हैं । निश्चित रूप से तमाम युवा वर्ग आप के ऊपर टकटकी निगाह से देख रही है । आप ने 2016-17 में दिसंबर से 2,232 कि०मी० राजकीय उच्च पथ का राज्य निधि से निर्माण कराया है । आपने 2,104 कि०मी० राज्य उच्च पथ का राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत आप ने निर्माण कराने का काम किया है । आप ने 1072 कि०मी० राज्य उच्च पथ का ए०डी०बी० संपोषित योजनान्तर्गत आप ने इसके निर्माण के लिये एक अहम

भूमिका निभायी है। महोदय, राज्य योजना से 845 कि० मी० सड़क उन्नयन का काम पूर्ण करने का काम किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। आप ने 13,675 कि०मी० जिला पथों का चौड़ीकरण, उसका नवीकरण और सुदृढीकरण का काम आपने जो किया है, बिहार के इतिहास में आप का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

इसी तरह से आप ने पुल निर्माण विभाग में पुल का जाल बिछाने का काम किया है। पुल के कामों में 6,700 से अधिक आप ने पुल का निर्माण कराया है। उदाहरणस्वरूप : बिहार में पहला सिक्स लेन गया में फल्गु नदी पर बनाने का काम आप ने किया है। गंगा नदी पर भागलपुर-खगड़िया के बीच पुल का निर्माण एक सराहनीय कदम है। बखित्यारपुर-ताजपुर के बीच आप ने पुल का निर्माण किया है, जो बिहार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। कच्ची दरगाह-विदुपुर के बीच, आरा-छपरा के बीच, गंडक नदी पर गोपालगंज से बंगरा घाट पर, पूर्वी चम्पारण से सतर घाट पर, सोन नदी पर दाउदनगर-नासरीगंज के बीच बड़े पुल का निर्माण आप ने कराया है, जो सचमुच में एक सराहनीय कदम है। महोदय, माननीय सदस्य डा० सुनील कुमार जी कई बा तें सदन के बीच रखना चाहते थे, हम उनसे जानना चाहते हैं कि 13.01.2016 को समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड में निकला था कि एक कमिटी गठित की गयी थी बिहार आर्थिक पैकेज पर काम जारी करने के लिये। हम विपक्ष के साथियों से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र द्वारा घोषित 1.65 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा किया गया था, जिसमें एक भाजपा के प्रतिनिधि के साथ बैठक की गयी थी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, प्रेम कुमार जी, मंगल पांडे जी, उसी तरह 04.06.2015 को भी आप ने दैनिक जागरण समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड में देखा होगा महोदय, घोषणा किया था बिहार के सड़कों के निर्माण के लिये 50 करोड़ रूपया देंगे। हम जानना चाहते हैं विपक्ष के साथियों से कि आप ने जो इस घोषणा करने का काम किया था, आप ने कौन से वादे को निभाने का काम किया है। इस तरह से कहीं न कहीं माननीय सदस्य डा० सुनील जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया है। हम आप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और खास करके डिप्टी सी०एम० तेजस्वी यादव को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। हमलोगों को इस बात का फख है महोदय। फख यह है महोदय, किसी ने ठीक ही कहा है :

“न दौलत पर नाज करते हैं,
न शोहरत पर नाज करते हैं,
हुये हैं महागठबंधन में एम०एल०ए०,
अपनी किस्मत पर नाज करते हैं साथियों।

साथियों, हमलोग फख करते हैं, इस महागठबंधन के एम०एल०ए० होने के नाते कि आपने जिस दिलेरी और जिस मुस्तैदी के साथ युवा तुर्क नेता के रूप में आप

ने बिहार ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में एक नाम रौशन करने का काम किया है। आदरणीय लालू यादव जो जन-जन के सामाजिक न्याय के नेता हैं, जिन्होंने सचमुच में गरीबों को आवाज दी है और नवाज आलम सदन में बोलने की हिम्मत कर रहा है साथियों, वह लालू यादव की देन है, ऐसे न जाने कितने गरीब परिवार के लोगों को इस सदन में पहुंचने का मौका दिया है। ऐसे नेता को सचमुच में भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ने महात्मा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण करने के लिये आपने महात्मा गांधी प्रमंडल बनाने की योजना रखी, जो वर्षों से लंबित था, तमाम लोग परेशान थे, वैसे इस प्रमंडल को बनाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिये सदन के माध्यम से आप को धन्यवाद देते हैं।

महोदय, मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत आप ने 3 हजार 31 अरब 33लाख 200 करोड़ 2 लाख की लागत से मुख्यमंत्री सेतु योजना का जो काम किया है, वह सराहनीय है। आप ने सबेया मोतीपुर कार्य को करने का काम किया।

आपने संत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350 वें जन्म दिन के अवसर पर आप ने जो सराहनीय काम किया है, यह कोई बनावटी बात नहीं है, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व में आप की चर्चा चल रही है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) माननीय सदस्य, आप का मात्र एक मिनट समय बचा है।

श्री मो० नवाज आलम : महोदय, मेरा अभी समय है। महोदय, 77.82 करोड़ की लागत से रेलवे पुल का बनाने का काम किया है। महोदय, तमाम चीजों को कहीं न कहीं रेखांकित करने का काम किया गया था। भवन के मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री का, डिप्टी सी०एम० का काम उल्लेखनीय रहा है। सेल्स टैक्स भवन का निर्माण करना, 603.77 लाख रूपये का कोषागार ऑफिस का, उसके निर्माण एवं मरम्मत में 200 लाख रूपये देने का, नया पुलिस लाईन मुख्यालय भवन निर्माण में 100 करोड़ रूपया देने का काम किया है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आप का समय समाप्त हुआ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पथ निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मेरी पार्टी की ओर से 5 मिनट का समय इनको आवंटित कर दिया जाय।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : ठीक है। बोलिये।

श्री मो० नवाज आलम : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से बिल्डिंग डिपार्टमेंट का भी कुछ आईना दिखाने का काम कर रहे थे। आज बिल्डिंग विभाग जो आज गिलोटीन में है, उस मामले में भी बहुत सारे मंत्री बने।

क्रमशः

टर्न-16/राजेश/18.3.17

श्री मो0 नवाज आलम, क्रमशः लेकिन जो कोषागार था, ट्रेजरी ऑफिस था, तमाम जगहों के ट्रेजरी ऑफिस में पानी चू रहा था, वैसी जगहों को कहीं न कहीं उसके जीर्णोद्धार या उसके निर्माण कार्य में 200 लाख रुपये का प्रावधान किया है महोदय, नया पुलिस भवन के निर्माण पर 100 करोड़ रुपये, लेबर ऑफिस भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये, प्रखंड ऑफिस के लिए 301.14 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण में 25 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास समिति में 148 करोड़ रुपये दिये गये महोदय, इसी तरह से 42 करोड़ अनुसूचित-जाति के भवन के लिए और 477 करोड़ सांस्कृतिक भवनों के निर्माण के लिए दिये गये हैं महोदय, आपने 200 करोड़ पिछले वर्ग के लिए, आज लोग स्व0 कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करते हैं, आज अति पिछड़े के नाम पर लोग राजनीति करते हैं लेकिन अति पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के कल्याण हेतु जो माननीय मुख्यमंत्री और हमारी गठबंधन की सरकार ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो संकल्प लिया था महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसको इन्होंने सरजमीं पर उतारने का काम किया है महोदय, लगभग डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले लोगों को 10 हजार रुपये स्टैण्ड देने का काम भी किया गया है महोदय, इसी तरह से अनेक योजनाएँ चलायी गयी है महोदय, इसी लिए ठीक किसी ने कहा है, हम माननीय तेजस्वी यादव जी के उपर एक शेर कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा महोदय कि:

“मंजिल पर पहुंचना है, तो कौटे पर चलना सीखो,
कौटे ही बहा देते हैं, रफ्तारे कदम साथियो ।”

अगर आपका इरादा मजबूत होगा, अगर आप दृढ़ संकल्पित होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको राष्ट्रीय नेता के रूप में न जाने, आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है, आपका जो संकल्प है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको धूमिल नहीं कर सकती है, क्योंकि साथियों मैं भी 30-32 सालों से राजनीतिक जीवन में एक अचूक नेता को, जिसके कंधों पर सवा साल में पथ निर्माण विभाग में पता नहीं, कौन-कौन सी योजनाएँ लाए, कितना पुलों का निर्माण किया, हम विपक्ष के साथियों से पूछना चाहते हैं, आप भी विभाग में रहते थे, आपको भी मंत्रालय मिला था, आपने कौन सी योजनाएँ चलाये, माननीय पहले के मंत्री इलियास हुसैन जी ने जो सारी योजनाएँ, जैसे पुल निर्माण का काम किया था, उसको भी ये लोग पूरा नहीं करा सके, लेकिन सवा साल के इस छोटे से मौके पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो सोच रखी थी, जो संकल्प रखा था, जो विजन दिया था, जो जनता की अदालत में वादा किया था, उसको

सरजमीं पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है, तो महागठबंधन के नेता, तमाम जो हमारे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी का यह विजन है, श्री नीतीश कुमार जी का विजन है और जो माननीय मंत्री है, उनका दृढ़संकल्प का इरादा है, अटूट इरादा है और इसी इरादे के साथ इन्होंने इन योजनाओं को सरजमीं पर उतारा है महोदय । इसलिए आपके माध्यम से, हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातों की थी, इसी आरा के सरजमीं पर आपने कहा था कि हम सवा सौ करोड़ रुपये हम पैकेज देने का काम करेंगे, आपने आरा की सभा में बिहार की बोली लगाने का काम किया था, आप लोगों की बोली लगाये थे, लेकिन आपने कोई भी काम सरजमीं पर नहीं उतारा, महोदय, आरा की पावन धरती से मैं आता हूँ और यह शहीद वीर कुँवर सिंह जी की पावन धरती है, यह शहीद अशफाकउल्लाह की धरती है साथियों, न जाने कितने शहीद हुए, इसी धरती पर सामाजिक धारा को बोलने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी की देन थी कि कई जगह आज जो कुछ भी नजर आ रहा है, चाहे अल्पसंख्यकों का छात्रावास नजर आ रहा हो, चाहे अति पिछड़ा समाज का छात्रावास नजर आ रहा हो, यह सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का ही देन है ।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल): माननीय सदस्य अब आप बैठ जाइये । आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर बोलने के लिए आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए हम महागठबंधन की ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देना चाहते हैं और बधाई इसलिए कि आज और कल का बिहार अगर हम इस वाद-विवाद में एक नजर से देखेंगे कि हमने जो कल का बिहार देखा था महोदय, उस बिहार को भी याद करने की जरूरत है लेकिन आजादी के बाद जिस बिहार की कल्पना हमलोगों ने किया था और उसके बाद जिस बिहार को हमने पाया और बिहार से झारखंड अलग हुआ और उस बिहार को हम देखते हैं महोदय, तो आज हमारी यादें ताजा हो जाती हैं । बोलने का मौका मिलता है, लोग सच और झूठ को नहीं देखते हैं, पक्ष और विपक्ष को नहीं देखते हैं लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बिहार के बँटवारे के बाद बिहार का जो असली रूप था, उस रूप को अगर हम देखना चाहते हैं, तो वह दिन याद आता है जब 2005 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था, तो उस बिहार का याद आ जाता है और याद इसलिए आता है कि उस समय बिहार सड़कों के बारे में पूरे देश में चर्चित था । हम कहना चाहते हैं कि आज वही बिहार जिस बिहार की कल्पना हम महागठबंधन की सरकार के रूप में देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस सड़क पर आज चर्चा हो रही है, हम उस ओर जाना चाहते हैं । महोदय, हमने देखा है, बिहार में पहले

एक जिला से दूसरे जिला जाने में, जब नालंदा से हमें पटना पहुंचना पड़ता था, तो पाँच घंटा में उसकी दूरी तय करते थे, जब बिहारशरीफ से फतुहा होकर पटना की दूरी तय की जाती थी, तो छः घंटे में दूरी तय की जाती थी, जब सहरसा से पटना आने की बात होती थी, तो 16 से 20 घंटा में लोग आते थे, महोदय हम वहाँ जाना चाहते हैं । महोदय, आज आदरणीय हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, पी0डब्लू0डी0 मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, पथ निर्माण विभाग ने जो आज 2016-17 में उपलब्धि हासिल किया है, वह पूरे देश को चौकाने वाला है, हमसे पहले पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से उसपर जाने का काम किया है, हम उस आँकड़ा की ओर जाने का काम नहीं करेंगे । हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय, जब वे चुनाव में बोल रहे थे, तो वे 7 निश्चय को लागू करने का काम किये, पूर्ण शराबबंदी के साथ 7 निश्चय और निश्चय के साथ सड़क निर्माण, तो 7 निश्चय पूरा होगा, जब सड़क निर्माण हो जायेगा ।

क्रमशः

टर्न-17/सत्येन्द्र/18-3-17

श्री चन्द्रसेन प्रसाद(क्रमशः): महोदय,पूरा बिहार जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातों को कहने का काम किये कि सड़क के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है । जब सड़क बनेगा तो बिहार चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो और चाहे कोई विभाग का क्षेत्र हो सभी क्षेत्रों में सड़क की भूमिका महत्वपूर्ण है । महोदय सड़क के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे गांव और वैसे वसावटों की ओर उन्होंने ध्यान देने का काम किया जिसकी आबादी 100 है, वहाँ तक आज बिहार सरकार पहुंचने का काम किया है और पथ निर्माण विभाग आज जो है सड़कों को पूरे बिहार में जोड़ने का काम किया है । हम उस ओर जाना चाहते हैं जो वर्ष 2014-15 में था और आज 2015-16 में है और 2016-17 में जो उपलब्धि आया है उस ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो सीधे दोगुना उपलब्धि बढ़ा है महोदय । हम फक्र के साथ कहना चाहते हैं कि आज बिहार सात निश्चय पूर्ण शराबबंदी के साथ पथ निर्माण विभाग पूरा तेजी से आगे बढ़ रहा है । पूर्व के वक्ताओं ने चाहे सड़क के दोहरीकरण का सवाल हो, चाहे पी0डब्लू0डी0 सड़क के विस्तार का सवाल हो, चाहे पुल पुलिया का सवाल हो, उस पर विस्तार से चर्चा हुआ । महोदय, चाहे गंगा नदी पर गांधी सेतु का सवाल हो या उसके उद्धार का सवाल हो, चाहे पटना से हाजीपुर पीपा पुल का सवाल हो सभी सवालों पर हम कहना चाहते हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने जो सफलता पायी है वह काफी सराहनीय है और हम कहना चाहते हैं कि देश के दूसरे भागों से जब हम बिहार आते हैं और जैसे ही झारखंड से बिहार में घुसते हैं, उड़ीसा से बिहार में घुसते हैं तो निश्चित तौर पर पथ निर्माण का

काम सामने में नजर आने लगता है । महोदय इसलिए हम कहना चाहते हैं चाहे पुल का सवाल हो, गंगा नदी पर बड़े बड़े पुल का कार्यक्रम हो और 2020 तक उसको पूरा करने का कार्यक्रम है महोदय । महोदय, आज बिहार जिस तरह से विकास की ओर बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू..

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) माननीय सदस्य, मात्र एक मिनट समय बचा है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: हम कहना चाहते हैं उनके नेतृत्व में सात निश्चय के तहत पूर्ण शराबबंदी पर और पथ निर्माण पर विभाग पूरी तरह से सजग है और जो आज कल्पना कर रहे हैं कि युवा उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से पथ निर्माण विभाग में अपने पूरे लगन और विश्वास के साथ उन्होंने जो काम किया है वह काबिलेतारीफ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छा पथ निर्माण विभाग का मंत्री मिला है इसलिए इनके माध्यम से कदम से कदम मिलाकर के इस विभाग का कल्याण होने वाला है। समय को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं और अपने क्षेत्र की ओर जाना जाना चाहते हैं पथ निर्माण विभाग

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) अब बैठ जाईए। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: पथ निर्माण विभाग ने जो सफलता पायी है और उस सफलता के बीच में कुछ छोटे मोटे कार्य बच गये हैं । महोदय, हमारा क्षेत्र इस्लामपुर विधान-सभा पड़ता है, एन0एच-110 पर मेरा आवास है लेकिन हमने कल भी उठाया था माननीय मंत्री से हम आग्रह करना चाहते हैं कि दनियावां तक जो सड़कें फोर लेन बना है उसको दनियावां से हिलसा होते हुए एकंगरसराय इस्लामपुर होते हुए राजगीर पर्यटक स्थल को फोर लेने से जोड़ने का काम किया जाय और हिलसा में, एकंगरसराय में, इस्लामपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था बाईपास का उसका अभी तक कार्य बाधित है इसलिए हम माननीय मंत्री जी आग्रह करना चाहते हैं कि उस कार्य को शुरू करवाने का काम किया जाय ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) अब बैठ जाईए, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती आशा सिन्हा: सभापति महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पथ निर्माण विभाग हेतु प्रस्तावित 68 अरब 35 करोड़ 90 लाख रू0 की राशि में 10 रू0 से घटायी जाय । किसी भी राज्य में उसके चतुर्मुखी विकास हेतु सड़क की भूमिका महत्वपूर्ण है परन्तु इस मुद्दे पर सरकार का दावा खोखला प्राप्त होता है । महोदय, आज एक तरफ सरकार द्वारा राज्य के किसी कोने से पांच घंटे में राजधानी पहुंचने के लिए दावा किया जाता है लेकिन सड़क का बुरी हाल है मेनटेनेंस का सभी जगह अभाव है। महोदय, सड़क निर्माण में भी अनियमितता बरती जाती है और सड़क को मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है जिस कारण सड़क एक वर्ष के भीतर ही टूट जाती है

और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। विधायक पहले जनता की मांग पर गांव गांव में गलियां के पक्की सड़क और नाली का अनुशंसा करती थी जिससे इस क्षेत्र में कई कि०मी० सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा होता था लेकिन राज्य सरकार ने इस अधिकार को छीनकर केवल प्रतिनिधि कहलाने का कार्य किया है। महोदय, जनता के साथ में झूठा भी वादा किया गया है। पथ निर्माण विभाग बजटीय राशि खर्च करने में भी पीछे चल रही है। अभी तक विभाग में महोदय 72.23 फीसदी राशि खर्च हो नहीं पायी है। महोदय, अभी सत्ता पक्ष के सदस्या जो कह रही है हमलोग विधायक 2005 से हैं जब हमलोग क्षेत्र में जाते थे महोदय उस समय रोड का नाली का अनुशंसा होता था। जब 2005 में एन०डी०ए० की सरकार बनी थी तो उस समय इस राज्य में रोड का जाल बिछाया गया था। आज माननीय सदस्य अपने सीना में हाथ धरकर कहें कि क्या आप लोग खुश है, अंदर अंदर महोदय खुश नहीं है ऊपर के मन से आप लोग भाषण दे रहे हैं। आज जनता की समस्या आप लोग नहीं खत्म कर रहे हैं महोदय यह स्थिति आ गयी है। महोदय, राज्य पथ निर्माण के एजेंसी को सत्ताधारी लोग के गुंडे, अपराधी द्वारा रंगदारी मांगा जा रहा है और सड़क निर्माण में लगाये गये भारी भारी मशीनों को आग के हवाले किया जा रहा है। महोदय, यहीं नहीं धमकी देकर उनके ठीकेदार एजेंसी के इंजीनियर मुंशी, सुपरवाइजर की हत्या की जा रही है और सरकार इन पर रोक नहीं लगा पा रही हैं। आज राज्य में विधि व्यवस्था का यही हाल है। महोदय इससे बिहार में निर्माण कम्पनी कैसे काम कर पायेगी। दूसरे राज्य के जोड़ने वाली पथ पटना बक्सर फोर लेन बनाने का काम अधूरा है कई वर्षों से सरकार उदासीन चल रहा है उसका अधूरा काम लटका हुआ है। हम चाहेंगे कि गुणवत्ता पूर्वक सड़क बने, उसके मेनटेन करने के साथ-साथ पटना बक्सर पथ, पटना डोभी पथ को बनाना हमारा प्रायोरिटी है लेकिन उसके निर्माण से जुड़े कम्पनी कर्मचारी इंजीनियर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वह विफल है महोदय इस सरकार में, महागठबंधन के सरकार में वहां जो इंजीनियर आता है उनकी हत्या की जा रही है महोदय उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी आप लोग खासकर सत्ता पक्ष के सदस्यगण से मैं कहना चाहती हूँ। (कमशः)

टर्न-18/मधुप/18.3.2017

...कमशः...

श्रीमती आशा देवी : महोदय, अभी भोला भाई बता रहे थे कि जाल बिछ रहा है, सड़क का जाल महागठबंधन की सरकार में नहीं बिछा है, जाल तो हमलोगों ने एन०डी०ए० की सरकार में 2005 से 2010 तक बिछाया है। उस समय सड़क का जाल बिछाया गया था।

(व्यवधान)

टूटा नहीं है, अभी महागठबंधन की सरकार को उसको मरम्मत करना है लेकिन मरम्मत भी नहीं हो रहा है। जिस समय हम विधायक बने थे, पुल-पुलिया का अनुशंसा करते थे जहाँ 10 का करते थे, 10 बनता था। आज तो 10 का अनुशंसा करते हैं, एक भी नहीं बन रहा है। हमलोग दिन-रात क्षेत्र में रहते हैं। अभी हमारी बहन लोग बता रही हैं, होता है - होता है। गलत मत बोलिये, क्षेत्र में जाइयेगा तब न बताइयेगा कि क्या हो रहा है। आपलोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, एक साल में आपने कितना काम किया है? मैं यह जानना चाहती हूँ। आप सारे माननीय सदस्य लोग, सारे जनता के हित में काम करते हैं, हमलोग सभी जनता के जन-प्रतिनिधि हैं। यह स्थिति है।

मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि दानापुर दियारा में पुल निर्माण के लिये माननीय लालू प्रसाद जी गये थे, चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि चुनाव में जब जीत जायेंगे, सरकार में आयेंगे तो पुल बनायेंगे। एक साल हो गया है, अभी वहाँ शिलान्यास भी नहीं हुआ है। जनता के साथ झूठा वायदा किया जाता है। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमलोगों ने रोड बनवाया है, महागठबंधन के मंत्री लोग उसका मरम्मत करा रहे हैं। सड़क का जाल तो हमलोगों ने बिछाया है, नक्शा बना-बनाकर जो आहर-पइन था उसको सड़क बनाकर हमलोगों ने दिखाया था। उस समय माननीय नन्द किशोर यादव जी पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। हमलोगों ने सड़कों का जाल बिछाया है, आपलोगों ने नहीं बिछाया है।

माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ आपके ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमलोगों के भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे एक भाई बोल रहे थे, मुख्यमंत्री विपक्ष का भी काम करते हैं। जन-प्रतिनिधि जब बनते हैं तो पक्ष-विपक्ष सबका काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबका काम करते हैं, आपके खाली मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। इसलिये आपलोग ऐसी बात मत बोलिये। महोदय, आज अपराधी हावी हो गया है। आपको बता रहे हैं फुलवारी एम्स जो बन रहा है, उस रोड की स्थिति काफी खराब है, हमारे माननीय मंत्री जी वहाँ गये होंगे, देखे होंगे कि क्या स्थिति है, नौबतपुर जाने वाले रोड में भी। दूसरा रोड सगुना मोड़ से आर0 के0 पुरम होते हुये जाती है, जर्जर स्थिति है। उसपर भी ध्यान दिया जाय। सिर्फ आपलोग भाषण मत दीजिये, सिर्फ पेपर और न्यूज में मत छाड़िये कि काम हो रहा है, काम हो रहा है।

(व्यवधान)

आपलोग उपर के मन से बोलते हैं, नीचे से आपका दिल रोता है, जब क्षेत्र में जाते हैं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, एक महिला बोल रही है, बोलने दीजिये । इन लोगों को सब दिन ऐसे ही नहीं कहने देंगे ।

हमने सच्चाई बताया कि सच्चाई क्या है । महोदय, प्रधानमंत्री जो देश के लिये कर रहे हैं, वह सराहनीय है ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ । अब आप बैठ जायं । श्री वशिष्ठ सिंह ।

श्रीमती आशा देवी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ । महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, सरकार के पक्ष में और पथ निर्माण विभाग पर विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये आपके बीच में मैं खड़ा हूँ । महोदय, बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार के मुखिया परम आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में नौजवानों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव मिलकर जो बिहार में काम कर रहे हैं, उसको केवल बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की भी जनता सराहने का काम कर रही है ।

महोदय, बिहार में सड़कों का जाल बिछा है और आगे हमारी सरकार पी0डब्लू0डी0 का सड़क बनाने का काम कर रही है, फोरलेन बनाने का काम कर रही है और एक लक्ष्य बनाई है कि बिहार के किसी भी सुदूर इलाके से पटना राजधानी तक पाँच घंटा में पहुँचने के लिये हम जनता का काम कर रहे हैं और इस लक्ष्य पर हमारी सरकार काम कर रही है । मुझे भरोसा है कि यह लक्ष्य पाने में हम सफल होंगे और आज सफलता के नजदीक हम पहुँचे हुये हैं ।

महोदय, 2016-17 में दिसम्बर माह तक 2232 कि0मी0 राष्ट्रीय उच्च पथ तथा 4021 कि0मी0 राज्य उच्च पथ का नवीकरण और उन्नयन कार्य हुआ है, 13675 कि0मी0 वृहद् जिला पथों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ है । महोदय, पथ के मामले में मैं बताना चाहता हूँ कि पथ इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिये, इस शरीर को बढ़ने के लिये, दौड़ने के लिये, इस शरीर में जितने धमनी की जरूरत है, जितना वेन की जरूरत है उतना ही इस बिहार के विकास के लिये, हिन्दुस्तान के विकास के लिये पथ की जरूरत है । अगर हमारा पथ निर्माण विभाग काम ठीक-ठाक कर रहा है और पथ निर्माण विभाग से जब सड़क बन जाती है तो हमारी जनता को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा होती है । उसी तरह हमारी सरकार पथ निर्माण विभाग में शरीर में जैसे नस के रूप में, वेन के रूप में काम कर रही है, उसी तरह बिजली का भी काम जिस तरह से हमारे नस में, हमारे वेन में जिस तरह से तेजी से ब्लड का संचार होता है, उसी तरह से बिजली का संचार भी बिहार में हो रहा है ।

महोदय, हम इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार बड़े-बड़े नदियों में कई जगह बड़ा-बड़ा पुल बनाने का काम कर रही है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने का काम कर रही है। गंगा नदी में भागलपुर-खगड़िया के बीच, बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच, कच्ची दरगाह-बिदुपुर के बीच, आरा-छपरा के बीच ये जो पुल बन जायेंगे, जल्दी बनने वाले हैं, हमारी भोजपुर से छपरा, सीवान और गोपालगंज की दूरी कम हो जायेगी और हमारा भोजपुर जिला जो भोजपुरिया के नाम से जाना जाता है और छपरा, गोपालगंज और सीवान जो भोजपुरी के नाम से जाना जाता है, हम दोनों आपस में मिल जायेंगे। महोदय, सोन नदी पर एक तरफ सोन नदी के बगल में हम भोजपुर इलाके के लोग, रोहतास जिला से हमलोग आते हैं, नासरीगंज से एक मगह इलाके के दाउदनगर को जोड़ने के लिये पुल का काम अंतिम स्थिति में है, वह भी पुल बनने जा रहा है।

महोदय, हम बधाई देना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री जी को कि जब से आप सरकार में आये हैं और जब से आप पथ निर्माण विभाग का कार्यभार सँभाले हैं तब से बिल्कुल सेंसिटिव विचार को रखते हुये आप सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं। हम यह भी देखें हैं कि जो माननीय विधायक अगर किसी भी तरह का अपना पत्र लिखकर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को देते हैं किसी भी समस्या को लेकर, तो वहाँ उसका तुरंत रिजल्ट के रूप में हमलोगों के पास किसी न किसी तरह से पेपर के माध्यम से अपनी बात को बताते हैं कि इस स्थिति में आपका कागज है। इसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, इस पथ निर्माण विभाग के साथ-साथ इनके पास पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग का काम है, भवन निर्माण विभाग का काम है, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुराना आजादी के पहले का जो यह बना हुआ बिहार विधान सभा का भवन है, इसके बगल में हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार विधान सभा का नया भवन बनाने जा रही है। यह बिहार सरकार का सबसे अद्भुत और सफल कार्य है। महोदय, बेली रोड पर इस देश का सबसे बड़ा म्यूजियम का काम फाइनल स्थिति में पहुँचा हुआ है।

महोदय, हमारी सरकार हमेशा काम में विश्वास रखती है, जुमले में विश्वास नहीं रखती है। और लोगों की जो सरकार है, वह केवल जुमलों में विश्वास रखती है, जैसे एक विपक्ष के हमारे सदस्य बोल रहे थे कि सरकार कही थी कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात, ये गलत बोल रहे हैं, इनलोगों की आदत है गलत बोलना, फितरत में है गलत बोलना, झॉसे में डालना और झॉसे में लाकर हुकूमत करना इनलोगों की फितरत में है। ये कहते हैं जय श्रीराम, आगे मुँह से कहते हैं जय श्रीराम लेकिन कम्बल ओढ़कर घी पीने का काम करते हैं। इसका जीता-जागता प्रमाण मैं देना चाहता हूँ। ...क्रमशः...

टर्न-19/आजाद/18.03.2017

.... क्रमशः

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, गोवा में हमारी कांग्रेस विधायकों की संख्या ज्यादा थी, मणिपुर में भी हमारे विधायकों की संख्या ज्यादा थी लेकिन इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट करके और लोकतंत्र के मर्यादा को तार-तार करके इन लोगों ने धन-बल पर सरकार बनाने का काम किया, हिन्दुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी और इतना ही नहीं महोदय, इन लोगों के पास कोई नेता नहीं है। महोदय, गोवा में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो ये लोग देश के रक्षा मंत्री को गोवा का मुख्यमंत्री बनाते हैं और उत्तरप्रदेश में इन लोगों को मुख्यमंत्री का कैंडीडेट नहीं मिलते हैं। ये झांसा में सरकार बना लिये लेकिन ये पिछड़ा और अतिपिछड़ा के लिए कुछ नहीं किया। महोदय, अतिपिछड़ा समाज के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमको याद है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को अतिपिछड़ा के रूप में प्राजेक्ट किया था लेकिन जब से देश में सरकार बनी, अतिपिछड़ा समाज के लिए कोई काम नहीं किया। जबकि बिहार की सरकार पिछड़ा, अतिपिछड़ा

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, इस राज्य के सड़कों के निर्माण पर बोलिये न।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, सड़क के साथ-साथ इसमें अतिपिछड़ा, पिछड़ा जुड़ा हुआ है, भवन निर्माण विभाग भी इसमें जुड़ा हुआ है। मैं विषय से विषयांतर नहीं हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अतिपिछड़ा समाज को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में 20 प्रतिशत आरक्षण दे करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं एकल पद पर बैठाने का काम किया, यह गरीब की सरकार है, यह समाजवादियों की सरकार है, ये बड़े लोग और अमीरों की सरकार नहीं है। इसलिए महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, पथ निर्माण के सवाल पर हम आपको बताना चाहते हैं कि पथ निर्माण में मेरा एक छोटा सा सुझाव है। सुझाव यह है कि पथ निर्माण में जहां सड़क बन रही है, उस सड़क के बगल में नाली का निर्माण भी अवश्य कराना चाहिए, यह मेरा छोटा सा सुझाव है। महोदय, दूसरा यह है कि कई पथ निर्माण विभाग में स्टेट हाईवे पर हम देख रहे हैं कि स्टेट हाईवे पर कहीं-कहीं ब्रेकर लगाने का काम करते हैं। जिससे यात्रियों को चलने में परेशानी होती है, दुर्घटना होती है। हम जब सड़क पर चलते हैं तो कई जगहों पर देखते हैं कि ब्रेकर लगाया गया है, इसपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। महोदय, यह पथ निर्माण के सवाल पर एक सदस्य हमारे विपक्ष के बोल रहे थे कि मैंने इतना-इतना पैसा दिया और मैं कह रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी है, तब से बिहार सरकार के सभी योजनाओं में पैसा का कटौती किया गया है

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, भारत सरकार ने सभी योजनाओं में पैसा का कटौती किया गया है ।

इसलिए महोदय,

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : क्या व्यवस्था है ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, व्यवस्था मेरी यह है, माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने सभी योजनाओं में कटौती किया है, मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये साबित कर दें, मैं इनको चुनौती देता हूँ ।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज बैठिए । माननीय सदस्य बैठ जाईए ।

माननीय सदस्य आप बोलिये ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, मैं इनका चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ, सभी योजनाओं में 90 प्रतिशत से काटकर के 60 प्रतिशत कर दिया गया है और कहते हैं कि अच्छा दिन लायेंगे, ये अच्छा दिन लाने वाले लोग नहीं हैं । हम इनसे कहना चाहते हैं कि इनकी सरकार के लोगों ने कहा था कि मेरी सरकार जब बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का काम करेंगे लेकिन ये एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं दिये । ये वही लोग हैं जो मुँह में राम और बगल में छूरी

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाईए ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, हम नया सदस्य हैं, मुझे एक मिनट दिया जाय । महोदय, कोचस में मेरा क्षेत्र की एक समस्या है, कोचस के बगल में एक परिसदन है, हम मांग करते हैं हम अपने मंत्री महोदय जी से कि आप वहां पर एक बढिया आईबी0 बना दीजिये ताकि उत्तरप्रदेश जाने वाले हमारे कोई भी पदाधिकारी हो या नेता को रूकना पड़े तो वहां एक-दो घंटा के लिए रूक सके । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ बहुत,बहुत धन्यवाद।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग में हो रहे वाद-विवाद में कटौती प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आपको जानकारी होगी अपनी समय का ।

श्री महबूब आलम : महोदय, थोड़ा समय हमलोगों को दिया जाय । महोदय, हमारे नवाज भाई बोल रहे थे तो मैं उसके काऊन्टर पर बोलता हूँ :-

ये दाग-दाग उजाला, यह सब वजीरा शहर,
वो इन्तजार था जिनका, यह वह शहर तो नहीं,
कि जिनकी आरजू लेकर चले थे कि
यह मिल जायेगी पहाड़ों पर सवार ।

महोदय, सड़कों की हालत पर जो व्याख्यान हो रहा है, लेकिन आज पटना से जब हम सीमांचलवासी पूर्णिया और कटिहार जाते हैं तो बिहार की सबसे पुरानी पथ निर्माण

विभाग की जो सड़क है, वह आपको एन0एच0 जो बख्तियारपुर होते हुये हमलोग जाते हैं, मोकामा होते हुये बेगूसराय एवं पूर्णिया तक, यह सड़क अभी तक फोरलेन की सड़क नहीं हुई है । बिहार में सीमांचल और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है महोदय, यह उपेक्षित क्षेत्र रहा है और इसकी उपेक्षा का कारण राजनीति है और राजनीति में इस क्षेत्र से कोई कद्दावर नेता नहीं खड़ा हो रहा है समझ लीजिये, यह बिहार का वह क्षेत्र है, जिसको ये लोग कोई महत्व नहीं रखते हैं । वह अकलियत डोमिनेट एरिया है महोदय, इसीलिए आज इस सड़क की हालत देखिये, क्या है ? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 5 घंटा में कटिहार से पटना पहुँचाऊँगा । महोदय, बारसोई वासियों को 7 कि०मी० सड़क तय करके कटिहार आने के लिए 3 घंटे का समय लगता है । 1977-78 के आसपास बनी हुई कटिहार से बारसोई जो सिंगल पथ है, आज तक महोदय, उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ । महोदय, बलरामपुर विधान-सभा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से बलरामपुर दलकोला में बिहार टू बिहार जाने के लिए हमें बंगाल के 7 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है । महोदय सुना जाय, मानपुर, करीमगंज, सुदानी, तेलपा, आदमपुर की सड़क को पी०डब्लू०डी० सड़क के रूप में, बारसोई गानवेय विभोर की सड़क को पी०डब्लू०डी० के सड़क के रूप में, नगरिया रंगबरिया करनपुर पथ को पी०डब्लू०डी० पथ और कटिहार-बलरामपुर के पथ को चौड़ीकरण की मांग रखता हूँ । प्राजेक्ट इन पाईप लाईन में आपने कटिहार-बलरामपुर सड़क का लिया है महोदय.....

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, प्लीज अब आप बैठ जाईए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में हो जाय । साथ-साथ महोदय, टियर आन्दर रोड जो सिवान में है के अधिग्रहण के लिए पथ निर्माण के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी घोषणा कर दिया जाय महोदय ताकि वह पथ बन जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं और आप शुरू करा दिये। सभापति महोदय, पिछले सत्र में ही मैं एक सड़क का चर्चा किया था गैर-सरकारी संकल्प में, माननीय मंत्री जी ने कहा था, मैं उसको संज्ञान में देना चाहता हूँ । एन0एच0 टू मोहनिया से भभुआ माँ मुण्डेश्वरी भगवानपुर, सबार, अमावत, करमचत, चेंनारी, मल्लीपुर, दरियाँव, आलमपुर-दलियाँव होते हुये तारा चण्डी धाम 105 कि०मी०, इसी सदन में पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा किया था स्टेट हाईवे का चार धाम को जोड़ने वाली, पाँच धाम को जोड़ने वाली सड़क । माँ मुण्डेश्वरी, गुप्ता धाम, गीताघाट आश्रम, तारा चण्डी धाम, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि पिछले बार कहे हैं और अब उनके घोषणा के विपरीत बात जा रही है कि 2017-18 के बजट सत्र में हम खड़े हैं और उन्होंने 2016-17 में कहा था । हम इनसे दो-दो बार कहा, हम दर्जन बार मिल चुके हैं और

अभी तक नहीं हुआ है । इसलिए मैं इनसे आग्रह करूँगा कि इसी वित्तीय वर्ष में, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 2017 में बना देंगे । तब बना दें, कम से कम जो वादा किये हैं, वे वादाखिलाफी नहीं हो ।

दूसरी बात दो-तीन सवाल और है, सभापति महोदय, हम दो-तीन बार नितिन गडकरी साहेब से मिला । डॉ० अरूण कुमार,सांसद, मैं और शिवराज सिंह पार्टी के महासचिव, जिसमें मैंने दो सड़कों की चर्चा की, जिसमें एन०एच० टू जिसकी चर्चा इलियास साहेब कर रहे हैं कि 50 करोड़ रू० दिया गया है, मैं उसी पर

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, थोड़ा समय पर भी ध्यान रखा जाय ।

श्री ललन पासवान : महोदय, बस मैं बता दे रहा हूँ, हमारा दो-तीन सवाल है, कोई आगे सवाल नहीं है । एन०एच० टू डिहरी यदुनाथपुर पथ से 120 कि०मी० की दूरी है, 10 कि०मी० के बाद एस०एच०-5 शुरू होता है रेणुकट 75 में जाकर मिलता है, जो 700 कि०मी० 5 राज्यों को जोड़ने वाली मुम्बई तक की दूरी 500-600 कि०मी० की कम होगी । मैंने इनसे भी निवेदन किया था और माननीय नितिन गडकरी जी से भी निवेदन किया था । इनसे अनुशांसा मांगी गई थी, इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी अनुशांसा भारत सरकार को भेज दें ।

..... क्रमशः

टर्न-20/अंजनी/दि० 18.03.2017

श्री ललन पासवान...क्रमशः... दूसरी सड़क एन०एच०-2 मोहनियां टुसी से अधौरा, भगवानपुर अधौरा से सोनभद्र होते हुए राबसगंज जाकर मिर्जापुर 7 और 76 का दोनों का डिमांड किया था और दोनों की अनुशांसा माननीय तेजस्वी जी से मांगी गयी और मैंने दो-दो बार श्री नितिन गडकरी से और दर्जनों बार इनसे भी मिला हूँ । सभापति महोदय, एक और आग्रह है कि पंडुका पुल भारत सरकार की योजना में बिहार सरकार को दो हजार करोड़ रूपया का पैकेज है । पंडुका पुल झारखंड और बिहार को जोड़नेवाली पुल है, जिसका डी०पी०आर० भारत सरकार ने बिहार सरकार को बनाने का आदेश दिया है । मैं व्यक्तिगत रूप से श्री तेजस्वी जी से मिला था । पंडुका पुल के संबंध में माननीय मंत्री जी सर्वेक्षण के संबंध में कहे थे

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : आप उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री जी से मिले थे, तेजस्वी जी से नहीं मिले थे.....

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री से भी मिला था और मैं एक दर्जन बार उनसे मिला और उन्होंने कहा कि चलूँगा । पंडुका पुल का डी०पी०आर० अभी तक नहीं बना है महोदय । मैं इनसे आग्रह करूँगा कि जल्दी बने ।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : वे जहां भी होंगे, आपकी बात गंभीरतापूर्वक सुन रहे होंगे ।
अब आप बैठ जाइए, आपका समय हो गया ।

श्री ललन पासवान : मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय विधायक मधुबनी जिला के हरलाखी के श्री सुधांशु शेखर जी का एक सड़क है । हरलाखी विधान सभा क्षेत्र के उमगांव चौक से हिसार बौरा होते हुए बेनीपट्टी प्रखंड तक 25 किलोमीटर तक सड़क काफी जर्जर है, इसको बनाने की मांग हम करते हैं और एक और आग्रह है कि इलियास साहेब कहे उनको हम बधाई देते हैं, उन्होंने पैसा दिया है लेकिन 1 करोड 25 लाख...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जाइए ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट सर ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट, एन0एच0 टूसी में माननीय मंत्री जी ने पैसा जरूर दिया है लेकिन उपरी सड़क.....

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठिए । काफी जानकार आप हैं, अब आप बैठिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के बजट के खिलाफ में, माननीय नेता श्री अरूण कुमार सिन्हा जी के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय महोदय, किसी भी राज्य का आईना होता है पथ, जैसे ही हम राज्य के किसी कोने में प्रवेश करते हैं तो वहां के पथों को देखने के बाद लगता है कि हम आईना में अपना चेहरा देख रहे हैं और बिहार में, बिहार के साथी जो सत्ता पक्ष में हैं, कई प्रकार की लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि आज से चार साल पहले पथ निर्माण विभाग ने पुल निर्माण निगम या सेतु बिहार के मुख्यमंत्री सेतु योजना को बंद कर दिया । आज एक रूपये का भी काम सेतु योजना से नहीं हो रहा है, कुछ काम भी सेतु योजना से हुआ था, वह भी काम पूरा नहीं हो सका । पथ निर्माण विभाग लंबी-चौड़ी बातें कर रही है कि यह प्रोग्रेस हो रहा है, वह प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन विभाग में लगातार कटौती होती जा रही है । पुलों का काम बंद होता जा रहा है और पुल निर्माण निगम भी मृतप्रायः होते जा रहा है । मैं उस पुल निर्माण निगम के बारे में कहना चाहूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पथ निर्माण मंत्री जी सदन में नहीं हैं, उस पथ निर्माण विभाग के अन्डर में जो पुल निर्माण निगम है, उसमें बड़े डी0पी0आर0 का घोटाला है, 22 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं डी0पी0आर0 बनाने में । यहां पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, उस डी0पी0आर0 का, जो बड़ा घोटाला है तो पुल निर्माण निगम के उस डी0पी0आर0 घोटाले की जांच होनी चाहिए । मैं कुछ और घोटाले के

संबंध में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बेलीरोड पर जीरो कि०मी० से चौथे कि०मी० तक का काम हुआ, 13 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति हो गयी, पेमेन्ट भी हो गया, लेकिन 4 करोड़ रुपये का उसमें घोटाला है, निगरानी विभाग ने उसकी जाँच किया। पथ निर्माण विभाग के मुख्य सचिव के अंडर में वह जाँच हुई। वह पूरा कागज पड़ा हुआ है, जाँच में घोटाले साबित हो गये, लेकिन आज तक विभाग के पदाधिकारियों और माननीय मंत्री जी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। महोदय, मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि आप इसमें कार्रवाई करें। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 से 87 तक इस विभाग में कनीय अभियंताओं की बहाली हुई, 50 ऐसे कनीय अभियंता हैं जिनकी बहाली फर्जी है और महोदय उस मामले में पटना हाईकोर्ट में सी०डब्लू०जे०सी०-11771/2016 दायर है। पदाधिकारी बैठे हैं, यहां मैं चैलेंज करता हूँ इस सदन में कि आप इसकी जाँच करवाइये और वैसे लोग जिनकी फर्जी नियुक्ति हुई है, फर्जी बहाली हुई है, उनको भी प्रमोशन देकर विभाग के किसी अच्छे पद पर बैठाया गया है, इसकी जाँच आप करवा लीजिए। महोदय, मैं उत्तर बिहार से आता हूँ और कई बार सदन में चर्चाएं हुई कि उत्तर बिहार, बिहार का लाइफ लाइन है, पटना का गांधी सेतु पुल- पटना के गांधी सेतु पुल को बंद करने की बात है, चूंकि बनाना है ठीक बात है, लेकिन पीपा पुल बनाकर आवागमन चालू करने की बात है- मंत्री जी जब खड़े होंगे तो बतायेंगे कि बरसात के महीने में जब बरसात का महीना आयेगा और इस पुल को तोड़ दिया जायेगा तो हमलोग किस रास्ते से उत्तर बिहार की तरफ जायेंगे या किसी नये टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पीपापुल को बरसात के दिनों में भी कंटीन्यू करने की कोई व्यवस्था है क्या ? माननीय मंत्री जरा इसको बतायेंगे। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो एन०एच० 28 की तरफ बढ़ेंगे जो पिपरा से गोपालगंज की तरफ जाती है, 33 करोड़ रुपये दिये गये सी०के० इन्फ्रास्ट्रक्चर को, सी०के० इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसको बिहार में एग्रीमेन्ट किया गया, जिसको एप्रोच पथ बनाना था, पुल के नीचे का पथ बनाना था, वह काम छोड़कर भाग गया। आप डुमरिया घाट के पास का पुल देखिए, खजुड़िया का ओवर ब्रिज देखिए, गोपालगंज का ओवरब्रिज देखिए, सारे जगह के रास्ते ऐसे ही पड़े हुए हैं और 33 करोड़ रुपये का क्या हुआ, पता नहीं दुबारा फिर उसी सी०के० इन्फ्रा०प्रा०लि० को एग्रीमेन्ट किया गया है, कब तक वह काम करेगा, किस प्रकार से करेगा ? माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे तो हमलोगों को संतुष्ट करेंगे। महोदय, 2011 में जब माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा निकली थी तो उत्तर बिहार के तरफ वे बेतिया गये थे। हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं विनय बिहारी जी कई महीनों तक इन्होंने आंदोलन किया है और 2011 में जब मनुआ पुल पर गये तो वहां उनकी गाड़ी फंस गयी, अप्रोच नहीं था उस पुल में तो वहां के एस०पी० और डी०एम० अपने से गाड़ी ठेलकर पुल को पार कराये। माननीय

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं पटना लौटूंगा और इस एप्रोच का काम हो जायेगा, लेकिन आज तक महोदय उस एप्रोच को नहीं बनाया गया। मैं सदन में चैलेन्ज करता हूँ कि आप उसकी जाँच करवा लीजिए और जाकर देख लीजिए और उसी प्रकार से अन्य कई योजनाओं की बात मैं करता हूँ कि जो पुल निर्माण निगम ने डी0पी0आर0 बनाया जिसके लिए उसको 22 करोड़ रूपया अभी तक दिया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे पुल का उसने डी0पी0आर0 बनाया जिसमें एप्रोच नहीं बनाया। पुल तो बनेगा लेकिन एप्रोच नहीं बनेगा और एप्रोच भी बनेगा तो एप्रोच में इतनी कम राशि दी जायेगी कि वह एप्रोच गाड़ी चढ़ने के लायक नहीं होगा। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बिहार में वैसे जितने पुल हैं आप उन पुलों का सर्वे कराइये और पुनः उसकी निविदा करके जरा उसको ठीक कराइये ताकि वह पुल चलने के लायक हो जाय। महोदय, इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि तब मैं 2012 में केसरिया का विधायक था जब सत्तर घाट के पुल का निर्माण शुरू हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी गये थे केसरिया में और कहे थे कि 15 अगस्त 2015 तक उस पुल को चालू कर दिया जायेगा। महोदय, पता नहीं दुर्भाग्य में फंसा है, अलगाववाद में फंसा है इंजीनियरिंग के किसी काम में फंसा है या पदाधिकारियों के रोक के चलते वह पुल फंसा हुआ है, अभी उस पुल का 40 प्रतिशत भी काम नहीं हो पाया। जो उसका नियत समय था उससे दो साल ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उस काम की प्रगति बहुत ही कमजोर है। महोदय, मैं और भी अन्य विषयों पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। महोदय, सी0आर0एफ0 के बारे में हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारत सरकार पैसे नहीं देती है, पूर्वी चम्पारण जिले में सी0आर0एफ0 का पड़ा हुआ है। मेरे हाथ में कागज है, मैं विभाग के सेक्रेटरी से मिल चुका हूँ उनको भी पत्र दिया हूँ। महोदय, मैं आदरणीय पथ निर्माण मंत्री जी को दो-दो बार पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि आप उन सड़कों को बनाइये। महात्मा गांधी गये थे चम्पारण, ये 2017 का वर्ष है 100वाँ वर्ष हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चम्पारण के सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मना रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आप एक मिनट समय शेष है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : उन्होंने पत्र देकर कहा था कि जल्दी हम इस काम को करा देंगे, पत्र भी मेरे हाथ में है, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। महोदय, कुछ अपने क्षेत्र के और जिले के पथों के विषय में कहना चाहूंगा और आपने समय मुझको कम कर दिया है। इसलिए मैं बहुत अधिक बात न करते हुए मैंने जो कुछ लिखकर रखा है, अगर आपका आदेश होगा तो मैं दे दूंगा, ये प्रोसिडिंग का पार्ट हो जायेगा।

...क्रमशः....

टर्न-21/शंभु/18.03.17

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : कमशः.....बहुत कुछ बोलने का समय और अवसर नहीं मिला, लेकिन आपने जो कुछ अवसर दिया मुझको बोलने के लिए मैंने अपनी बात रखी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार के भाइयों को बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर पुनः एक बार कल्याणपुर अपने क्षेत्र की जनता सहित पूरे बिहार के भाइयों को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद।

श्री संजय सरावगी : सर, इसको प्रोसिडिंग का पार्ट बनवा दीजिए।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : दे दीजिए, भेज दीजिए।

श्री(मो0) नेमतुल्लाह : महोदय, पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, पथ निर्माण विभाग जो है वह किसी भी डेवलपमेंट का रीढ़ होता है। अगर मजबूत हो पथ तो इकोनोमिकली, सोशली, कल्चरली डेवलपमेंट होगा, अगर वह कमजोर होगा तो ठप पड़ जायेगा। पथ मंत्री डिप्टी सी0एम0 साहब ने जिस तरह से सीरियसनेस दिखाया है पथ डेवलपमेंट में उसकी जितनी भी तारीफ की जाय कम है। उन्होंने यहां से लेकर दिल्ली तक गुहार लगाया, कई मर्तबे नीतिन गडकरी साहब से जो केन्द्रीय मंत्री हैं उनसे भी मिलकर बिहार के पथों के बारे में इनकी समस्या के बारे में जानकारी दी। एक मर्तबा माननीय लालू यादव के साथ भी गडकरी साहब से मिलने गये, लेकिन उनके जाकर मिलने पर यहां डिबेट शुरू हो गया। इन लोगों ने जानकारी भी नहीं लिया कि माननीय गडकरी साहब ने खुद लालू जी को बुलाया था कुछ डिस्कश करने के लिए तो माननीय डिप्टी सी0एम0 साहब ने गडकरी साहब से गये थे मिलने, लेकिन यह डिबेट चलने लगा टी0वी0 पर कि लालू जी गये थे, डिप्टी सी0एम0 के साथ- अरे तथ्य की जानकारी हासिल कीजिए तब टी0वी0 पर, रेडियो पर डिबेट चलाइये। आप इस तरह का सहारा न लीजिए, आज जिस तरह से पथ पर खर्च हुआ है और 90 परसेंट खर्चा कर दिया मुख्यमंत्री ने पथों पर जिस तरह से बिहार को डेवलपमेंट के अगली सीढ़ी पर ले जाना चाहते हैं उसमें आपका सहयोग चाहिए, आप भी उसमें सहयोग कीजिए, चूँकि जब पथ बनता है तो सिर्फ आप नहीं चलते हैं, हम नहीं चलते हैं सारे लोग चलते हैं। आपलोग राजनीति मत कीजिए- ये गुलिस्तां है इसको गुलिस्तां ही रहने दीजिए, मत बांटो कौमों मिल्लत को ये हिन्दुस्तान है इसको हिन्दुस्तान ही रहने दो। महोदय, आपने देखा है कि पुल का निर्माण- माननीय डिप्टी सी0एम0- जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेतु योजना को खतम कर दिया उसको रोड के साथ जोड़ दिया गया। अब ग्रामीण विकास उस रोड को बना रहा है और अगर उसमें पुल है तो ग्रामीण विकास बनायेगा। जो पथ निर्माण विभाग बना रहा है तो पथ निर्माण उस पुल का निर्माण करेगा। उससे जोड़ दिया गया है, उसको बनाने के लिए और आप कह रहे हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में आप देखिए यहां से

बाहर निकलिये, आप देखिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन ओवर ब्रिज बना रहा है, वही बना रहा है कोई दूसरा नहीं बना रहा है। उससे भी काम हो रहा है। आपने एन0एच0-28 की बात की कि उसमें काम रूका था, वादा हुआ था जो गोपालगंज में उनपर एफ0आइ0आर0 हुआ, उनको हटा दिया गया और काम तेजी से हो रहा है। आपने जिस तरह से आपने मोनेटरिंग में काम में तेजी लाया है, वह एक सराहनीय कदम है। महोदय, बिल्कुल सही है, एकदम देखिए किस तरह से तेजी से वह काम चल रहा है, वह कंपनी काम कर रही है। ये माननीय डिप्टी सी0एम0 जी का मोनेटरिंग का नतीजा है। आपने देखा मुख्यमंत्री जी एक डायनेमिक आदमी हैं। यहां पर जिस तरह से प्रकाशोत्सव मनाया गया, उसमें रोड को जिस तरह से चकाचौंध मनाया गया, पटना सिटी में आये देश और विदेश के लोगों ने जिस तरह से तारीफ की बिहार की, वह देश में ही नहीं हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी तारीफ की गयी। इसीलिए डिप्टी सी0एम0 साहब कहते हैं कि गलियों को शहरों को हम अंधेरा होने न देंगे, मेरे जिंदगी में सवेरा हो न हो, हम आपके जिंदगी में अंधेरा होने न देंगे। इसलिए आप उनके मंसूबा को देखिए, उनके भिजन को देखिए, आप उनका सहयोग कीजिए। आप सहयोग कीजिए, आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे- आप तो बिजली को बांट देते हैं कि ईद में मिलती है और होली में नहीं मिलती है। अरे बिजली जाती है तो वहां हिन्दू भी रहता है और मुसलमान भी रहता है, निचला भी रहता है उंचला भी रहता है, सबके घर में जाती है। आप मत बांटो हिन्दुस्तान को हम एक हैं एक रहने दो, यही सी0एम0 साहब का और डिप्टी सी0एम0 साहब की यही इच्छा है। इस इच्छाशक्ति के साथ बिहार में आपके मंसूबे को उपजने नहीं देंगे, आपके मंसूबे को चकनाचूर कर दिया जायेगा। आपको रोक दिया जयेगा। आप जिस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, आप जिस तरह से घोटाला कर रहे हैं, पॉलीटिकल घोटाला गोवा में किया, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या है इस तरह का काम, यह कंस्टीच्वेशन की हत्या है। कंस्टीच्वेशन में जिस मेजोरिटी पार्टी का बहुमत है उसको इनवाइट किया जाता है, लेकिन आपने नहीं इनवाइट किया। आपने क्या तोड़ जोड़ से सरकार बनाकर, आपने उसको सरकार बना दिया। महोदय, आप

अध्यक्ष : अब आप एक दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : हां-हां करा लीजिएगा कोई पीछे नहीं भागता है। महोदय, गोपालगंज में.....

अध्यक्ष : अब आप क्षेत्रवाली बात सब बता दीजिए।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, एक सियान सनपरा रोड है उस रोड में एक ओ0पी0आर0एम0 पैकज नं0-37 दिया गया था। उसको बनाना था किसी कंपनी को एच0आर0 बिल्डर कोई है, उसके साथ 17 रोड दिया गया था, 5 साल तक उसको मेनटेन करना था, लेकिन 3 साल हो गया उस किसी रोड का मेनटेनेन्स नहीं हो रहा है। मेरा विभाग से निवेदन है

कि उसपर कार्रवाई किया जाय। महोदय, दूसरी बात कि वह जिला तीन मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सी०एम० गोपालगंज जिला दिया है। इसलिए कुछ सड़कों ऐसी हैं- जैसे गफूर रोड है वहां से निकलकर वह गफूर रोड से पिपरा होते हुए सीवान सरफरा रोड मिलता है। उस रोड को भी अधिग्रहण करके माननीय पथ मंत्री जी बना दें। एक गोपालगंज और तरवारा रोड है उसका भी चौड़ीकरण करने के लिए मैंने लिखा था और डिप्टी सी०एम० ने आश्वासन दिया है और वहीं से निकलकर भगवानपुर से लोहजीरा होते हुए मांझा प्रखंड तक वह रोड जाती है। उसको भी अधिग्रहण करके बड़ी लंबी 6 कि०मी० सड़क का भी अधिग्रहण कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी। आपने हमें समय दिया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 के पथ निर्माण विभाग हेतु प्रस्तावित 66 अरब 35 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि में से 10 रू० कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए सदन में खड़ा हूँ। महोदय, किसी भी राज्य का समृद्ध विकास वहां की सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल.....क्रमशः।

टर्न-22/अशोक/18.03.2017

श्री विद्या सागर केशरी : क्रमशः... पेयजल, बिजली की समस्याओं से निदान पर आधारित होती है । सड़क से गांव, कस्बा, शहर का जब तक आपस में जुड़ाव नहीं हो जाता तब तक हम तरक्की का, विकास का जितना भी पीठ थप-थपा लें बेकार है । महोदय, दुनिया में जो भी राष्ट्र विकसित हुये हैं उसके पीछे सड़क की अहम भूमिका रही है । पूरी दुनिया में सड़क मार्ग पर अत्यधिक भार एवं भीड़ के निदान हेतु फ्लाई ओभर रोड ने अहम भूमिका निभाई हैं, जहां बिहार बहुत पीछे है इस मामले में महोदय । बिहार में अभी हम पहली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं, अभी हमारा गांव, कस्बा, शहर भी एक दूसरे नहीं जुड़ पाया हैं महोदय, सरकार बड़ी बड़ी घोषणा की कि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछेगा, मील का पत्थर साबित हो रहा हैं महोदय। सरकार राज्य पथ को पूरे राज्य में फुटपाथ के साथ दो लेन सड़क बनाने का विचार रखती हैं लेकिन अब तक कितने कार्य हुये यह सर्वविदित हैं महोदय । महोदय, ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । इसके निदाने के लिए सरकार को बाई पाय जैसी रोड की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ेगा । महोदय, सड़कों का मैन्टेनेन्स, जिसके लिए सरकार ने पांच साल का संवेदक को समय निर्धारित की है लेकिन आप चल जाईये किसी भी राज्य के किसी भी कोने में जो मैन्टेनेन्स की राशि दी जाती हैं संवेदकों को वह राशि सिर्फ पांच साल के अन्तराल में धीरे धीरे करके पदाधिकारियों के मिली भगत से पैसे का न्यारा व्यारा हो जाता हैं और मैन्टेनेन्स के नाम पर सड़क जैसे तैसे उसी वस्तुस्थिति में रह जाती हैं ।

महोदय, राज्य में पांच हजार 737 कि.मी. ऐसी सड़क है जो साढ़े तीन मीटर या उससे कम चौड़ी है, आमने सामने दो गाड़ी भी पास नहीं कर सकती है। इसके लिए चौड़ीकरण की सख्त आवश्यकता हैं, लेकिन आज तक इस पर क्या विचार हुआ, यह सरकार बताने का प्रयास करे। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग और पुल निगम के द्वारा बहुत ही उपेक्षित रखा गया है उस क्षेत्र को। महोदय, एक लाईफ लाईन जो वर्तमान समय में फोर लेन जो माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के द्वारा दी गई थी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना, जिसके चलते आज हमलोग उस क्षेत्र का लाभ उठा पा रहे हैं, उसके बाद आज तक उस क्षेत्र में कोई भी ऐसी योजना नहीं चलाई गयी जिससे उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, हमने पूरे भारत राज्य का 25 सालों में दौरा किया महोदय, हमने देखा कि राज्यस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वांचल के आसाम, मणीपुर, अरूणाचल, जितने भी क्षेत्र थे पूर्वांचल के, उन क्षेत्रों में सड़कों का जो विकास हुआ, बिहार में मिलों दूर देखने को नहीं मिल रहा है महोदय। हमारा सीमांचल क्षेत्र में जो सीमावर्ती क्षेत्र जो है, वह सामरिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उस क्षेत्र में आज तक जो हमारे यहां एक परवान नदी बहती है महोदय, आजादी के बाद एक भी पुल का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं हुआ। हर कंट्री का माल जोगबनी बोर्डर से जाती है। लेकिन एक स्कू पाईल का पुल बना हुआ है, 1962 में जो पुल बना और उसकी जो भार क्षमता थी मात्र 15 टन की थी, आज 80-80 टन का लोड उस पुल पर रहता है, आप समझें अगर पुल किसी कारण से ध्वस्त हो जाती है तो नेपाल से हमलोगों का आने जाने का जो संबंध है, रोटी-बेटी का जो संबंध है और एस.एस.बी. का मुख्यालय बथनाहा में है, उन सारे दृष्टिकोण से उस पुल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन हमारे पथ निर्माण विभाग आज तक उस पुल के प्रति संवेदशील नहीं हैं। महोदय, हमारे क्षेत्र में फारविसगंज से ख्वासपुर कौआचार तक पिछले वर्ष आये बाढ़ मे पूरी तरीका से नाला में तबदील हो गई लेकिन मैंने शून्य काल में, निवेदन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से कई बार सदन में उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं ने अपनी बातों को रखा था। आज तक यह कह कर टाला जाता रहा कि उस सड़क का डी.पी.आर. अभी तक नहीं बना है, मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जो तीन विधान सभा की सड़क को जोड़ती है, उस सड़क से लाखों लोगों का आना जाना रोज का है, लेकिन आज तक उस सड़क का कभी भी किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से उसका न डी.पी.आर. बनाया गया है और न देखा गया। महोदय उसी क्षेत्र का बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो आज तक, चार पाया बन गया और उसी

अवस्था वर्षों से पड़ा हुआ है, सर्वगांव का एक पुल है जिसके लिए 6 करोड़ 70 लाख का टेण्डर हुआ था, तीन पाया पुल बनकर आज भी अधर में पड़ा हुआ है एप्रोच रोड के कारण । पीपरा घाट, बराजपुर घाट, कऊआचाल घाट, कमतावली अडी घाट- चार ऐसे महत्वपूर्ण पुल हैं जहां से लाखों लोगों का रोज आना जाना लगा रहता है, बरसात के दिन में चचरी के पुल पर से आना जाना लगा रहता है । जिससे छात्र-छात्रायें कई एक बार उस नदी में गिर कर के काल-कवलित हो गये । महोदय जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ

अध्यक्ष : केशरी जी, अब एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : बोर्डर रोड से संदर्भित है, बोर्डर रोड हमारे यहा बन रही हैं लेकिन बोर्डर रोड से जोड़ने का जो रोड है वह आज तक एक भी रोड का चयन नहीं किया गया महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम हमारे क्षेत्रों का एक बार जरूर दौरा करें । जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस क्षेत्र में परवान नदी अभिशाप के रूप में हैं । मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन होगा कि कम से कम परवान नदी के दोनों छोर पर रिंग बांध बनाकर उस पर पक्कीकरण कराकर उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें । लूप लाईन के रोड के तौर पर जो हम जानते हैं वह है फारविसगंज से किशनगंज को मानते हैं, उस रोड में भाया फारविसगंज-कौआटाड़-पटेगना होते हुये स्टेट हाई वे का निर्माण करावे । हमारे यहां ही रामपुर से डाकबंगला और पूर्णिया को जाने वाली रोड को, उस रोड को भी जिस पर सघन आबादी हैं उसमें भी माननीय मंत्री महोदय से चाहेंगे कि उस रोड का ...

अध्यक्ष : अब आप स्थान गहण करें ।

श्री विद्यासागर केशरी : अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि

“ जिसे दिया था कुछ वो दिलदार खा गया ।
कुछ अफसर ले गये, कुछ इंतजार खा गया ॥
सड़कें बहा रही हैं अस्तित्व पे आँसू ।
कुछ सरकार खा गई, कुछ ठीकेदार खा गया ॥ ”

महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, पथ निर्माण विभाग के बजट पर वाद-विवाद में जितने सदस्य हैं, जिन्होंने भाग लिया है, भोला यादव जी, रत्नेश सदा जी, सुनील

कुमार जी, विजय शंकर दूबे जी, अनवर जी, चन्द्रसेन सेठ जी, आशा देवी जी, वशिष्ठ सिंह जी, महबूब आलम जी, ललन पासवान जी, सचिन्द्र जी, नेमतुल्लाह जी, विद्या सागर केशरी जी, अरूण जी का भी जिनका कटौती प्रस्ताव हैं, उन सबों का आभार प्रकट करने का काम करते हैं और हमने गंभीरता से सभी लोगों की बातों को सुनने का काम किया, हमारे अधिकारियों ने भी सारी बातों को सुनने का काम किया है और ये दूसरी बार मुझे मौका मिला है पथ निर्माण विभाग के मांग को रखने का और हमने रखा। महोदय, जैसा आपको याद होगा कि पहली बार जब बजट की मांग पर जब चर्चा चली थी और मेरा जो भाषण था उसमें हमलोगों ने जो बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सोच है कि कोई भी दूर दूराज के इलाके से पांच घंटे में पटना पहुंचा जा सके, उस दिशा की ओर हमलोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं विस्तार रूप से अपने भाषण में उसका उल्लेख करूंगा। पहले उन्होंने का लक्ष्य रखा था 6 घंटा का जिसको हमलोगों ने एचिभ करने का काम किया और मुझे निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि जो हमलोगों का जो सपना है, जो विजन है, उसको हमलोग जरूर पूरा करने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ बिहार की जनता की बड़ी उम्मीदें हैं महागठबन्धन सरकार से, आदरणीय नीतीश जी से, लालूजी से, हम सबलोगों से और हमने पहले भी कहा था कि हमलोग भोग लगाने के लिए मंत्री नहीं बने है बल्कि सेवा के लिए बने हैं। क्रमशः

टर्न-23/ज्योति

18-03-2017

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : हम ईमानदारी से सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि एक साल और डेढ़ साल का जो कार्यकाल हमलोगों का रहा ईमानदारी से, निष्ठा से हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है और हमारी कोशिश रही है चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, जिन्होंने वोट दिया हो या ना दिया हो सब लोगों को एक साथ लेकर के चलो और सब लोगों का काम करना है और रोड के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोड सेक्टर है, इन्फ्रास्क्ट्रक्चर सेक्टर है राज्य के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए जबतक अच्छी रोड न हो अच्छी सड़क न हो, अच्छे पुल पुलिया न हो तबतक वहाँ का विकास अधूरा रहता है। महोदय, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं और बिहार को ऊंचाईयों तक हमलोगों को पहुंचाना है, विकास की गति में और तेजी लायी जाय उसके लिए हमलोगों ने काम किया है। माननीय सदस्य ने डा0 सुनील कुमार जी ने बात उठायी थी कि बख्तियारपुर से बिहार शरीफ और रजौली होते हुए जो सड़क

जाती है उसकी स्थिति ठीक नहीं है । उनको पता होना चाहिए महोदय, कि यह जो रोड है एन.एच.आई. के जिम्मे है और इसका जो भी मेंटीनेंस है, रख रखाव है एन.एच.आई. को करना है और हमलोगों ने नहीं करना है और एन.एच.आई. किनके जिम्मे हैं उनको पता होगा । दूसरा, ललन पासवान जी ने, अपने रोड को बताने का काम किया जो उनकी मांग रही महोदय, जो भी पथ है इनका भगवान पुर से नवगढ़ भाया जैदपुर, नवगढ़ से रामपुर, सवार से चेनारी, मालीपुर से दरीगांव । महोदय, इसकी 2017 योजना के तहत स्वीकृति हो चुकी है । प्रशासनिक स्वीकृति का अभी प्रक्रियाधीन है इसपर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ सचीन्द्र जी ने बातों को रखा । घोटालों की बात की है तो यह जान जाईये कि जबतक हमलोग हैं, हमलोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी दोषी होगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और न्याय के साथ विकास होगा । अगर आपका कोई पर्टिकुलर में कोई बात आप कह रहे हैं तो पर्टिकुलर में आप डिटेल हमको देने का काम कीजिये, जिन बातों को आपने रखने का काम किया ऐसा लगता है वह पहले का है। इसपर हमलोग नजर डालेंगे कि क्या प्रौब्लेम हुआ कि किसने किया आप डिटेल दीजिये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसपर हमलोग कार्रवाई करने का काम करेंगे जाँच कराने का काम करेंगे । अब सुन लीजिये । आपने बताया, आप मिल लीजियेगा अलग से, हम तो फ्री रहते हैं । अब विनय बिहारी जी को हमलोगों ने कुर्ता पैजामा पहना ही दिया अब ऐसा तो है नहीं कि हमलोग पक्षपात करने का काम करते हैं, सब लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं । सारी बिन्दुओं को महोदय, सब लोगों का डिमान्ड था साथ में सचीन्द्र जी ने कहा कि पुल का जो एप्रोच है पुल बन जाता है कैसी नीति है एप्रोच रोड नहीं बन पाता है तो इनको भी जान लेना चाहिए कि नंद किशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, प्रेम कुमार जी पथ निर्माण मंत्री थे, इनके नेता सुशील मोदी जी, डिप्टी सी0एम0 रह चुके थे । ये पुल एक साल में तो बने नहीं है जिनका एप्रोच रोड नहीं बना यह तो उस समय की नीति थी उन्हीं नीतियों को तो हम सुधार रहे हैं जो आपलोगों ने गलत निर्णय लिया और उसको हमलोग सुधारने का काम कर रहे हैं और पुल कॉरपोरेशन को हमलोगों ने निर्देश दिया है कि सारे जो पुल हैं उसमें पहले जो नया काम लेने से पहले आप, जिन जिन का पुल एप्रोच रोड नहीं बना है आप उसमें विशेष तौर पर ध्यान देने का काम कीजिये और उस काम को पूरा कराने का काम कीजिये । यह तो बड़ी दुविधा है हमसे सवाल उधर सुशील मोदी जी पूछते हैं और इधर ये लोग पूछते हैं कि एप्रोच रोड क्यों नहीं बना यह तो आपलोगों को तय करना चाहिए ऐसे कैसे नीति आपलोगों ने बना दी जब हमने पहली बार समीक्षा की थी जब पुल का, सुनने को आता था कि इसका उपयोग नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा है तो कारण क्या

है इसका एप्रोच रोड नहीं है तो इसप्रकार की नीति तो आपलोगों की थी कि पुल बना दिया, लाखों करोड़ रुपये खर्च कर दिए और उसके बाद भी ये स्थिति है कि पैसा चला गया उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है अब जैसे पुल जर्जर स्थिति में हो गए हैं, उसको भी सुधारना हम ही को करना है यानी आपके गलत काम को हम सुधारने का काम कर रहे हैं और आपलोग हम ही को ब्लेम करने का काम कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ हमको और इस विषय में नहीं कहना है लेकिन आपलोगों को पता होगा कि हमारे पथ निर्माण विभाग ने बिहार रोड मास्टर प्लान, 2035 बनाने का काम किया वर्तमान को देखते हुए नहीं बल्कि भविष्य को देखते हुए, वर्तमान में जो ट्रैफिक कंजेशन है अगर भविष्य में देखा जाय तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी अगर हम उसपर कार्रवाई नहीं करेंगे । कितना लोड बढ़ जायेगा रोड पर, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जायेगी और आर्थिक रूप से भी लोगों को काफी नुकासान होगा और हर चीज में नुकसान होगा तो हमने जो बिहार रोड मास्टर प्लान 2035 का, बीस साल का जो हमारा वीजन था । जो पहला पाँच साल 2015 से 2020 वह ट्वेंटी ट्वेंटी योजना के तहत हमने पिछले बार सदन में कहा था कि जितनी भी सड़के हैं तीन मीटर की उसको पाँच मीटर में किया जायेगा, पाँच मीटर की सड़के जो हैं वह सात मीटर में किया जायेगा, एन.एच.आई. के जितने सिंगल रोड थे बल्कि एन.एच.आई. का गार्डलार्इन है कि जितनी भी एन0एच0 की सड़के हैं उसको सिंगल लेन जिसको टू लेन वीथ पेडसोल्डर होना ही चाहिए, ये सारे एन0एच0 की सिंगल सड़के थी जिसको टू लेन वीथ पेडसोल्डर होना चाहिए था जो कि नहीं था। हम डिटेल् में आपको बतायेंगे अगर आपलोग सुनना चाहेंगे तब लेकिन आपलोग तो ...

श्री संजय सरावगी : सही बात बोलियेगा तो सुनेंगे भाषण दीजियेगा तो नहीं सुनेंगे । दीघा एप्रोच रोड का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अब इन्टरभियू तो हो नहीं रहा है कि एक सवाल आप पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे । हम पूरा स्पीच और भाषण लेकर सब लोगों की बातों को रखते हुए अगर आपलोग बातों को सुनियेगा अगर आपलोग सक्षम हैं सच को जानने में तो आपलोगों की भलाई है इसमें और आपलोगों की जानकारी भी बढ़ेगी और अज्ञान में कुछ भी डाटा देते रहते हैं आपलोग तो यह तो बहुत जरूरी है आपलोगों को जानना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ये लोग सुनें या सदन के कोई दूसरे सदस्य सुनें न सुनें आप पूरी बात सुना दीजिये क्योंकि आप जो सुनाईयेगा वह बिहार की जनता सुनेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : सुनाना है, सबको सुनाना है ।

श्री संजय सरावगी : गलत सही का निर्णय जनता करेगी ।

अध्यक्ष : वह भी जनता करेगी ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जितनी भी एन0एच0 से सड़के जाती हैं उससे हमारा जुड़ने का प्लान था । जितने भी हेडक्वार्टर से अनुमंडल जाती है या अनुमंडल हेडक्वार्टर से एस0एच0 है, एम0डी0आर0, ये सारी चीजों को हमलोगों को जोड़ने का , रोड कनेक्टिविटी देने का पिछले बार हमने बताया था कि हमलोग काम करेंगे । साथ ही साथ जो हमने यह भी बताया था कि डिस्ट्रीक्ट लेन जो गंगा ब्रीज है जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट नदी पर लम्बा पुल होने जा रहा है जिसकी लागत पाँच हजार करोड़ है और हमने एक बात और कही थी कि कोई भी योजना शुरू करने से पहले - पहले होता क्या था कि कोई भी योजना शुरू करने से पहले सब कुछ फाईनल कर दिया जाता था लेकिन जो जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई है वह नहीं की जाती थी, कई ऐसे पुल है डी.पी.आर. भी नहीं बना और एवार्ड भी कर दिया जाता था तो सारी चीजों को सिस्टम में लाकर हमलोगों ने यह काम शुरू किया है जैसे कि सिक्स लेन गंगा ब्रीज जो बनने जा रहा है कच्ची दरगाह से विदुपुर इसमें हमलोगों ने 70 फी सदी से भी ज्यादा जमीन अधिग्रहण कर दिया है और तेजी से काम शुरू होने जा रहा है । कैम्प- वैम्प लग रहा है । हम जो निर्णय ले रहे हैं इससे यह होगा कि एप्रोच रोड और पुल जो है साथ साथ बनने का काम होगा । महोदय, साथ ही साथ लोहिया पथ चक्र जो पटना के लिए ट्रैफिक को देखते हुए जो बेलीरोड से होते हुए हर जगह जाने का काम है कई इसमें पुल का प्रावधान है उसमें भी तेजी से काम शुरू हो चुका है महोदय, और मुझे खुशी है सदन में यह बताते हुए कि 15-16 में और 16-17 में - 15-16 में लगभग 1998 कि.मी. सड़क टोटल डिपार्टमेंट ने बनाने का काम किया था और 2016-17 में अबतक का विभाग का रेकॉर्ड एचीभमेंट है कि हमलोगों ने इस बार सबसे ज्यादा 2500 कि.मी. रोड बनाने का काम किया है ओर 250 पुल पुलियों को बनाने का काम किया है । साथ ही साथ 1400 कि0मी0 एस0डी0बी0सी0 अंडर ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज के तहत रोड आता है उसको हमलोगों ने बनाने का काम किया है । महोदय, और कई लोगों को शक होता था कि भाई कैसे लोगों को नौजवान है कि नहीं है, परिपक्व है कि नहीं है, जिम्मेदारी संभाल पायेगा कि नहीं संभाल पायेगा लोगों की शंका रहती थी जब बातें चल रही थी लेकिन आप जब विभाग का एचीभमेंट देखेंगे तो सबके सामने यह बात आ गयी है और हम अपने कार्य से, अभी भी इतने एचीभमेंट्स के बाद भी संतुष्ट नहीं है । हमें और काम करना है और आगे बढ़ना है । हमारा कंपीटीशन हमसे ही है और किसी से नहीं है।

आज हमने जो लक्ष्य 250 कि.मी. जो बनाने का काम किया है, अगले बार हमारी कोशिश होगी कि इससे ज्यादा वित्तीय वर्ष में सड़क बनाने का काम करें। यह हमारी कोशिश है। क्रमशः

टर्न-24/18.3.2017/बिपिन

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: क्रमशः साथ-ही-साथ 780 कि.मी. जो एस.एच. को जो दो लेन से कम था महोदय, उसको हमलोगों ने टू-लेनिंग के लिए ए.डी.बी. की स्वीकृति हमें मिल गई है महोदय। ए.डी.बी. प्रिंसपल एप्रूवल दे चुका है, सैद्धांतिक एप्रूवल इसमें मिल गया है, अब टू-लेनिंग का कार्य, बचे हुए जो टू-लेन से कम थे, जितने एस.एच., दो लेन बनाने के लिए, अब पैसा उपलब्ध हो जाएगा तो तेजी से हमलोग कार्रवाई करेंगे। हमलोगों का जो वीजन 2020 है, इसको हमलोग, एक साल के भीतर इतनी तेजी से कार्रवाई चली है कि जो वीजन 2020 है, उससे पहले भी हो सकता है कि सारी चीजों को हमलोग उसको पूरा कर लें। साथ-ही-साथ, एम.डी.आर. टोटल महोदय, 11054 कि.मी. है जिसमें कि 5933 कि.मी. सिंगल-लेन है जिसमें से 1888 कि.मी. जो है, उसको हमलोगों ने फैसला लिया है कि इंटरमीडिएट-लेन में उन सारे एम.डी.आर. को अपग्रेड करने का काम करेंगे। साथ-ही-साथ, 790 कि.मी. का जो प्रपोजल हमलोगों ने एम.डी.आर. का जाइका को हमलोगों ने प्रस्तुत किया है, इसपर भी हमने जो जाइका के कंट्री हेड थे, उनसे भी विशेष तौर पर हमने मांग की है और अपने प्रपोजल को उनके समक्ष खुद स्वयं रखने का भी काम किया है और इसपर हमलोग लगे हैं ताकि जो बचा हुआ 790 कि.मी. है, अगर जाइका के सहयोग से अगर हमें मदद मिलती है तो इन सारी सड़कों को भी हमलोग अपग्रेड करने का काम करेंगे महोदय। रेस्ट जो है, बाकी के 3255 कि.मी. सिंगल लेन है वह 2020 तक सबको इंटरमीडिएट-लेन में करने का हमलोगों का लक्ष्य है महोदय और जितने भी स्कू-पाइल ब्रिजेज थे जो हमको आर.सी. सी. में कंवर्ट करना था या जितने भी आपका नैरो-ब्रिजेज थे, उसको हमलोगों को ठीक करना था, उसमें हमलोगों ने इस 2016-17 वित्तीय वर्ष में 51 पुल-पुलियों की हमलोगों ने स्वीकृति दी है और जो बाकी टोटल जो जर्जर स्थिति में नैरो ब्रिजेज थे या स्कू-पाइल के ब्रिजेज थे, ये लगभग टोटल 385 ऐसे पुल-पुलिये थे जिसपर हमलोगों का बाकी के जो हैं, जो भी वित्तीय वर्ष आता जाएगा 2020 तक, इसको भी हमलोग पूरा कर लेंगे महोदय। साथ-ही-साथ, जितने सिंगल-लेन हैं और दो-लेन हैं, उसको हमलोगों को टू-लेन विथ पेभ शोल्डर में कंवर्ट करना है। जो हमने पहले जिक्र किया कि एन.एच. की जो सड़कें, जो सिंगल-लेन है या दो लेन से कम में है या दो लेन में है, वैसे सड़कों को हमलोगों ने मांग की नितिन गडकरी जी से कि हमलोग को जो गाइड लाइन

है एन.एच.ए.आई. का, बिहार में ही केवल सड़कें गाइड लाइन के मुताबिक नहीं है, उसको आपलोग इसको करवाने का काम कीजिए ताकि जो एन.एच. की जो स्थिति है, जो कई सदस्यों ने भी बताया कि चौड़ाई कम होने की वजह से काफी लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए महोदय, हमलोगों के विभाग ने पहली बार नए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो डी.पी.आर. बनाने का जो हमलोगों का काम है, नई तकनीक, जिसको कहा जाता है लिडार टेक्निक से हमलोग डी.पी.आर. बना रहे हैं ताकि हमलोगों का समय बचे तो हमारा जो काम, हमारी सरकार जो कर रही है, हमलोग चाहते हैं कि नई-नई मशीनरी आई है, नई-नई टेक्नोलॉजी आई हैं तो सबों का हमलोग इस्तेमाल अपने यहां सारे प्रोजेक्ट्स में हमलोग करने का काम करें और तेजी से इसके माध्यम से हमलोग डी.पी.आर. बनाने का काम हमलोग कर रहे हैं महोदय । आप सब लोग जानते हैं कि ओ.पी.आर.एम.सी. के तहत जो रोड मेंटेनेंस होता है हमलोगों का, उसमें कई ऐसे एस.एच. हैं, एम.डी.आर. हैं जो ओ.पी.आर.एम.सी. के पैकेज में आता है और ओ.पी.आर.एम.सी. के लिए कई लोगों का शिकायत भी सुने हैं कि उस पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा है तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने ओ.पी.आर.एम.सी. के लिए व्यवस्था बनाई थी जिसमें कि लोग भी फोटो खींच कर वाट-शॉप पर वे फोटो भी भेज सकते हैं, ई-मेल के माध्यम भी और इसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि हमलोग अच्छे से मोनिटरिंग करें और एक पी.एम.इ.यू. जो यूनिट चलता है जिसको आप रोड एम्बुलेंस भी कह सकते हैं कि तुरंत मरम्मत के लिए गाड़ी पहुंच जाती है और मरम्मत करने का काम करती है, इसकी ट्रॉकिंग को देखते हुए कि किस प्रकार इसकी ट्रॉकिंग की जाएगी, इसके लिए भी उन तमाम लगभग 70 के आसपास पी.एम.इ.यू. है, महोदय, इसमें भी हमलोगों ने जी.पी.एस. लगा दिया है और इसका हम अपने चेम्बर में भी लगाकर देखे हैं कि कौन-सी गाड़ी चल रही है, कौन-सी गाड़ी काम कर रही है तो यह सारी व्यवस्था, इन सारी चीजों को देखते हुए की गई है कि जो रोड की शिकायत आए तो इसके लिए कॉल सेंटर भी खोली गई है महोदय और सारी चीजें ई-मेल के जरिए भी और स्पेशल इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां कि इंजीनियरिंग लेवल के लोग इसको मोनिटरिंग करने का काम करते हैं और इम्मेडिएट रिप्लाय भी, जिनका रजिस्टर होता है कम्प्लेन, उनको एस.एम.एस. जाता है । कई बार जो शिकायतें आती हैं, अन्य विभागों की आती है, तो हमलोगों का विभाग भी उन शिकायतों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देता है ताकि वह विभाग भी उन सड़कों को देखने का काम करें और मरम्मत का काम जल्द-से-जल्द कराया जाए । साथ-ही-साथ हमलोगों ने नई इनिशिएटिव लिए हैं । पुलों की जो स्थिति होती थी, रोडों का तो रख-रखाव के लिए ओ.पी.आर.एम.सी. पैकेज के तहत उसका मेंटेनेंस चलता रहता था लेकिन आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी-बड़ी पुलें हैं, उसका मेंटेन नहीं हो पाता है और

जर्जर स्थिति में आ जाती है, जैसे, गांधी सेतु पुल या विक्रमशीला पुल जर्जर स्थिति में आ जाती है तो उसको देखते हुए हमलोगों ने एक पॉलिसी और एक ब्रीज मेंटेनेंस, एक नया विंग ही बनाया है ताकि वह उसको मेंटेन करने का काम करेगा महोदय । यह नई-नई चीजें जो कि नन्द किशोर जी को और इनलोगों को करना चाहिए था, वह हमलोगों को करना पड़ रहा है ताकि ठीक रहे सब कुछ

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: और दूसरा महोदय, रोड सेफ्टी को देखते हुए हमलोगों ने एक रोड सेफ्टी सेल भी बनाने का काम किया है । कई बार सदस्यों द्वारा कम्प्लेन आता है कि यहां घटना हो गई या पार्टिकुलर जो रोड होता है वहां कई बार होता है कि एक्सिडेंट काफी ज्यादा हो जाता है । इसको देखते हुए हमलोगों ने रोड सेफ्टी सेल भी बनाने का काम किया है ताकि ऐसे जगहों को, ऐसे सड़कों को वह चिन्हित कर सके या ऐसी पुलों को चिन्हित कर सके कि किस वजह से, चाहे ब्लैक होल हो, ब्लैक स्पॉट हो या कोई अलग कारण हो तो उसको देखते हुए ये सारी चीजें हमलोगों ने सेल गठित की है ताकि एक्सिडेंट की जो घटनाएं ज्यादा होती थी वह कम-से-कम हो । महोदय, कई बार यहां सदस्य द्वारा आवाज उठाई गई कि बिहार में कांट्रैक्टर सुरक्षित नहीं है, इंजीनियर सुरक्षित नहीं है । आपको पता होगा, इनलोगों को भी पता होगा । तमाम कांट्रैक्टरों को जो बड़ी योजना करते हैं, सौ करोड़ के उपर या सौ करोड़ के लगभग, सारे कांट्रैक्टरों को, बड़े कांट्रैक्टरों को पहली बार किसी मंत्री ने अपने पास बुलाकर उनकी मिटिंग कराई है सिक्युरिटी को लेकर । यह इनिशिएटिव हमलोगों ने उठाया है । उनको भरोसा दिलाया गया है कि आप काम कीजिए और पिछले बार हमने यह भी कहा था कि अगर कोई काम रूकेगा, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हम वहां खुद रह कर कैम्प कर उस काम को हम पूरा कराने का काम करेंगे । इसके लिए हमलोगों ने मिटिंग भी की । पिछले बार चड्डा एंड चड्डा कंपनी की जो हत्या हो गई थी उनके इंजीनियर की दरभंगा में, हम सदन को बताना चाहेंगे, जो भी आज हत्याएं जिन्होंने किया था, हत्यारे जो थे, उनको आज सरकार ने और पुलिस ने पकड़ कर जेल के भीतर करने का काम किया है । यहां कानून का राज्य है । इसमें कोई समझौता नहीं होगा । न्याय के साथ विकास होगा जो कि हमलोग करने का काम कर रहे हैं । हमने खुद लगातार कई बार कम्प्लेन भी आता है तो कांट्रैक्टरों को हमने प्रधान सचिव से लेकर अपने भी नम्बर भी दे रखा है कि कभी कोई हल्का, छोटा-सा भी, अगर कोई धमकी भी देने का काम करता है, प्रैंक कॉल भी करते हैं धमकाने के लिए, छोटी-से-छोटी भी अगर घटना है तो

सूचना आप हम तक पहुंचाने का काम कीजिए । कई बार लोग करते हैं तो हमने डी. जी.पी. से भी बात की है, होम सेक्रेट्री से भी बात की है कि वैसा जहां प्रॉबलम्ब होती है, वहां सिक््युरिटी की भी व्यवस्था की जाए । कई कांट्रैक्टरों को सैफ जवान दिलाने का भी हमलोगों ने काम किया है और जिसका चड्डा एंड चड्डा कंपनी के साइट पर जिस इंजीनियर की हत्या हुई थी, सदन को बताते हुए हमें खुशी हो रही है, जिन विपक्ष के लोगों ने माहौल खराब करने का कोशिश किया कि काम न हो, हम बताना चाहेंगे, वही प्रोजेक्ट तेजी से हो रहा है और समय पर वह खतम हो जाएगा । कोई डरने का और वैसा वातावरण कहीं पूरे बिहार नहीं है ...

(व्यवधान)

टर्न: 25/कृष्ण/18.03.2017

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री : संजय सरावगी जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री : एक बार तो हमको बोलने का मौका मिलता है, एक बात तो सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

तो क्या हम गलत बोल रहे हैं ? आप बैठ जाईये, बैठ जाईये ।

अध्यक्ष : आप जारी रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : कई माननीय सदस्यों का यह होता है कि जो आर0डब्ल्यू0डी0 की सडकें हैं, जो अलग विभाग की जमीन हैं, उसको टेक-ओवर कर के पथ निर्माण विभाग लेकर उसको बनाने का काम करें । हम बताना चाहेंगे कि हमलोगों ने एक मापदंड तय किया है, एक संकल्प हमारे मंत्रालय ने बनाने का काम किया है और मेरा फर्ज था कि सब को अवगत करा दें कि किन-किन प्रकार की जो सडकें हैं, वह हम विभाग के द्वारा अधिग्रहण करेंगे, एक कमिटी है, प्रधान सचिव के नेतृत्व में और भी विभागों के लोग, इन्जीनियर्स वगैरह हैं, भाग लेते हैं और हमने सारे एम0एल0सी0, एम0एल0ए0 से ले करके लोक सभा, राज्य सभा के बिहार के एम0पी0 हैं, सबको हमने एक पत्र निर्गत कराया है कि जो भी आप का रीकोमेंडेशन आता है तो यह मापदंड है, काईट्रिरिया है, उसको फुलफिल करना है, एक कमिटी बनी है, वह सारी चीजों को देखने का काम करती है, उसके बाद ही हमलोग निधि को देखते हुये कोई निर्णय लिया जाता है । तो हमलोगों ने सबलोगों को बता भी दिया है, सूचित भी कर दिया है कि किन-किन तरह के जैसे एन0एच0 टू एन0एच0, एस0एच0 टू एन0 एच0 हो गया, ए0डी0आर0-एस0एच0 हो गया या एस0एच0 टू एस0 एच0 हो गया, ऐसी

सडकें या पर्यटन स्थल को देखते हुये कोई धार्मिक स्थल को देखते हुये, एग्रीकल्चर एरिया को देखते हुये, इन्डस्ट्रीयल एरिया को देखते हुये, जो सडके हैं, ये मापदंड हैं, इसको आपलोग बता सकते है । हम तो चाहते हैं कि सब का एक ही बार सब का सडक बना दें लेकिन विभाग की भी मजबूरी रहती है । राशि को देखते हुये उस हिसाब से किया जाता है । कहां किस को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको देखते हुये फैसला लेते हैं । लेकिन जिनका नहीं हो पाता है, वे थोड़े से नाराज रहते हैं । हमारी कोशिश रहेगी कि 5 साल की सरकार है महागंठबंधन की, जिन-जिन सदस्यों का रीकोमेंडेशन आता है, जिन सदस्यों का मापदंड के हिसाब से फुलफिल होता है, उन सबों का जितना हो सकता है, हम लेने का प्रयास करेंगे । लेकिन वह मापदंड और संकल्प के हिसाब से होना चाहिए । इस में कोई पक्षपात की बात नहीं है। ठीक है न ?

श्री संजय सरावगी : पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, पार्टी देख कर काम करते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री : नहीं, नहीं । महोदय, जैसे पुल नहीं बन पाया तो उसका जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया था, इस वजह से एप्रोच रोड नहीं बन पाया तो उसके लिये हमने अलग से लैंड एक्वीजीशन सेल बनाने का काम किया है ताकि जहां-जहां एप्रोच रोड फंसे हुये हैं या जिस भी प्रोजेक्ट्स में जमीन की जो स्थिति है, जो फंसे हुये हैं, उसके लिये अलग से लैंड एक्वीजीशन सेल बनाने का काम किया है । बी0एस0आर0डी0सी0 में भी बनाया है, पुल निगम में भी बनाने का काम किया है । हमलोग प्रस्ताव ला रहे हैं कि पथ निर्माण विभाग में भी यह सेल गठित किया जाय ताकि जमीन अधिग्रहण करने में जो देरी होती है, जल्द से जल्द उसका निपटारा होगा और जल्द से जल्द हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, उसमें तेजी आयेगी । महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे विभाग में हुआ है । ए0ई0 टू इन्जीनियर इन चीफ एक साथ हमलोगों ने प्रमोशन देने का काम किया है । यह विभाग की बड़ी उपलब्धि है । यह मामला कई सालों से लटका हुआ था । प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, एक साथ हमलोगों ने सभी इन्जीनियरों को प्रमोशन देने का काम किया है । इससे उनलोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, सम्मान मिला है और उस हिसाब से ये लोग सहयोग भी कर रहे हैं । अगर कोई गलत करता है तो हमलोग बख्शाने वाले नहीं हैं और जो अच्छा काम करेंगे, उनको हमलोग एवार्ड देने का काम करेंगे ।

(व्यवधान)

साथ ही, गांधी सेतु की जो बात थी पिछले भाषण में हमने बताया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है और इसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार को गंभीर हो कर करना था, इस पुल के निर्माण के लिये ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए । ऐसे मॉडल के जो पुल थे, वह चाहे गोवा में हो या चीन में हो, ध्वस्त हो चुके हैं । उसके पुर्ननिर्माण के लिये हम लगातार श्री नीतीन गडकरी जी से मिले, दिल्ली

गये, अपनी बातों को रखने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिल्ली जा कर मिलने का काम किया और अपनी बातों का रखा और प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी, जब आये थे, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखने का काम किया था और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के दबाव से, मुख्यमंत्री जी और हमारे दबाव से और इस पुल के लिये बार-बार दिल्ली जाकर हमलोगों ने स्वीकृत कराया, इसका निर्माण राज्य सरकार के प्रयास से जल्द से जल्द शुरू होनेवाला है ।

(इस अवसर पर भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

महोदय, छपास की बीमारी है । इनको प्रेस मीडिया में फोटो खिंचवाना पड़ता है । नया-नया जुमला, गुमराह करनेवाली नई-नई बातें ,बाहर जाकर बतायेंगे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आपने विनय बिहारी जी को पूरा परिधान पहनाकर उनको सदन में बुलाने का जो काम किया, उसका असर दिख रहा है ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, सदन में धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला । इस सदन में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग को सामने से धन्यवाद दे रहा हूँ और सजेशन के लिये दो शब्द कहूंगा ।

अध्यक्ष : अब शब्द मत कहिये, धन्यवाद को डायल्यूट मत कीजिये ।

श्री विनय बिहारी : दो शब्द - पुलिस निर्माण निगम को जो बंद किया गया है, उसको चालू किया जाय, क्यों चालू किया जाय, मैं इसीलिये कह रहा हूँ आर0ई0आ0 सड़क बनेगी तो आर0ई0आ0 बनायेगा, पीडब्ल्यू0डी0 की सड़क बनेगी तो पी0डब्ल्यू0डी0 बनायेगा।

अध्यक्ष : आप मिल लीजियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री : आप हमसे अलग से मिल लीजियेगा ।

अध्यक्ष : विनय जी, आप माननीय मंत्री जी की संवेदनशीलता देख चुके हैं । जब ये आपको पूरा कपड़ा पहना सकते हैं तो यह पुल निर्माण निगम की बात तो आप इनको समझा ही सकते हैं । इसलिए अभी इनकी बात सुनिये ।

मंत्री जी, आप जारी रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री : महोदय, गांधी सेतु का पुनर्निर्माण हो रहा है । इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार और हम सब लोगों का बड़ा योगदान है । यह कितने लंबे समय से लटका हुआ था । स्थिति ठीक नहीं थी । जो हमलोगों का अधिकार था, जो जायज बातें थी, हमलोगों ने वहां जाकर उनके समक्ष रखने का काम किया और हमलोगों ने इसकी स्वीकृति ले आने का काम किया । इसका ऊपर को जो स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ कर के नया स्टील स्ट्रक्चर से बनाया जायेगा जो कि तकरीबन 1300 करोड़ का है। हमने इसके लिये विशेष तौर पर एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिलाधिकारी, हाजीपुर, पटना, एस0पी0, टैफिक एस0पी0, सबलोगों को बुलाया था, कंट्रैक्टर को बुलाया था, एस्कॉन एजेंसी है, उसको एवार्ड हुआ है, उनको बुलाकर एक-एक चीज हमने प्रजेंटेशन

देखा था कि किस प्रकार से आप तोड़ेंगे, किस प्रकार से आप बनायेंगे। गांधी सेतु लाईफ लाईन है, तोड़ दीजियेगा और विकल्प के रूप में कुछ उपाय नहीं कीजियेगा तो तो पटना और पूरे उत्तर बिहार की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हम लोग तो छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। चाहे वह कोई भी बात हो। हमलोगों ने सारे विकल्प की व्यवस्था करने का काम किया है। आप बगल में देखा सकते हैं, अभी हाल ही में पीपा पुल का उद्घाटन हुआ है। एक लेन बन गया है, दूसरा लेन मई तक पूरा कर लेना है। ताकि ट्राफिक लोड कम हो जाय। अभी तक एजेंसी का प्लान था, सिर्फ तोड़ने का। हमने कहा कि आप तोड़ दीजियेगा तो लोग कहां से आयेंगे-जायेंगे तो यह फैसला हुआ कि एक लेन तोड़ा जायेगा और एक लेन में यह नहीं कि पूरा इकट्ठे सारा का सारा तोड़ा जायेगा। जो 6 स्पैन हैं, पहले वह तोड़ जायेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : हर स्थिति में एक लेन चालू रहेगा।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री : हां। हर स्थिति में एक लेन चालू रहेगा। इसके लिये हमलोगो ने ट्रायल कराने का फैसला किया है। दो दिन हमलोग ट्रायल करेंगे, पहला जो स्पैन तोड़ेगा, वहां तक सिंगल लेन रहेगा, उसके बाद डायवर्सन बनाकर, जो दोनों लेन है, वह चालू रहेगी, आनेवाले दिनों में हमलोग ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि ट्राफिक के विकल्प में और हमलोग क्या कर सकते हैं और क्या सुधार ला सकते हैं, सारी चीजों को देखा जायेगा। महोदय, सदन में यह बताते हुये खुशी है कि विकल्प के तौर पर आरा छपरा पुल जो निर्माणाधीन था, जो अटका हुआ था, उसको भी हमलोग जून तक पूरा कर लेंगे ताकि ट्राफिक की स्थिति अच्छी होगी। साथ ही साथ एक और पुल है, रेलवे कम रोड दीघा-सोनपुर, उसका भी हमलोग जून तक उद्घाटन कर देंगे, ये दो बड़े पुल के उद्घाटन होने के बाद जो आवागमन की स्थिति है, जो कन्जेशन होगा, वह ठीक हो जायेगा।

क्रमशः

टर्न-26/राजेश/18.3.17

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री, क्रमशः लेकिन हमलोगों ने अभी करने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि जो एजेंसी है, उस एजेंसी के द्वारा अब तक महोदय ना तो जे0ए0डी0 एप्रूभ हो पाया है, न ही ऑथोरिटी इंजीनियर की ही नियुक्ति हुई है, न ही मशीनरी, चूंकि विदेशों से मशीन आनी है, पहली बार इस तरह का काम करेगा, अलग मशीन है, वह जब तक नहीं आता है और जो बार्ज है, तो जब तोड़ देगा पुल, तो गंगा नदी को वह पोलुट नहीं करें, उसके लिए बार्ज मंगाया जा रहा है महोदय, तो जब तक ये सारी

चीजें आ नहीं जाती हैं, तब तक हम अनुमति नहीं दे सकते थे कि इसको तोड़ दिया जाय, क्योंकि इसको तोड़ने का प्लान था, बनाने का नहीं था, तो हमलोगों ने बोला कि जून तक आप सारा चीज ले आइये, तब हम आपको आदेश देंगे, तब तक वैकल्पिक उद्घाटन भी हो जायेगा और सारी व्यवस्था हो जायगी और लोगों को उससे दिक्कत भी नहीं होगी, अच्छे से सब लोग आयेंगे, जायेंगे, तो यह सारी चीजें हमलोगों ने करने का काम किया और जो पीपा पुल जो बना है, वह एशिया का सबसे बड़ा पीपा पुल बना है महोदय और महोदय जो बिहार को एन0एच0 का एलोकेशन मिलता था, वह 841 करोड़ था, हमलोग लगातार चार बार नीतीन गड़कड़ी जी से मिले, कई बार चिट्ठी लिखे कि बिहार को उसका अधिकार मिलना चाहिए, इतने कम से काम नहीं चलने वाला, लगातार दबाव हमलोगों ने डालने का काम किया, उसके बाद परफौरमेंस को देखते हुए, हमारी सरकार का परफौरमेंस को देखते हुए, 841 करोड़ से 1548 करोड़ तक इसको बढ़ाने का काम किया गया महोदय और जो टारगेट 120 किलोमीटर का मिलता था, उसको 300 किलोमीटर किया गया परफौरमेंस को देखते हुए और जिस प्रकार से परफौरमेंस चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले बार 550 किलोमीटर हमलोगों को मिल जायेगा महोदय जो टारगेट करने का है ।

महोदय, आर0ओ0बी0 47 की जो स्वीकृति मिली है, हमलोगों ने रेल मंत्री जी से भी दो बार मिले, सारी बातें हमने रखने का काम किया, टोटल 51 आर0ओ0बी0 की स्वीकृति मिली थी, जिसमें चार बी0आर0जी0एफ0 योजना से किया जा रहा है, बाकी 47 जो है, उसको हमलोगों को करना है लेकिन अभी भी रेलवे द्वारा, भारत सरकार द्वारा, अभी तक यह फाइनल नहीं किया जा रहा है कि इसका डी0पी0आर0 कौन बनायेगा, इसका एजेंसी कौन होगा, ये सारे मामले अभी तक लटके हुए हैं, अभी तक कोई लेटर में हमलोगों को सूचना नहीं मिली है, हम बी0जे0पी0 के लोगों से मांग करते हैं, ये लोग आर0ओ0बी0 पर बहुत राजनीति किये हैं, ये लोग केन्द्र सरकार के पास जाय और रेल मंत्री जी से मिले और जो काम बचा हुआ है, उसको ये लोग एप्रूभ कराकर ले आये, क्योंकि डिसिजन अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि राज्य सरकार की जो एजेंसी है, उसका 5 परसेंट जो है, वह एजेंसी चार्ज लगता है और जो रेलवे का था, वह 8, 9 परसेंट एजेंसी चार्ज लगता था, इसलिए कि हमलोग 5 परसेंट से ज्यादा नहीं करेंगे, हमने रेल मंत्री जी से मिल कर अपनी बातों को रखा हलाँकि रेल मंत्री जी ने मौखिक तौर पर हमलोगों को बोले कि हॉ ठीक है, आपकी बात जायज है, पाँच परसेंट स्टेट एजेंसी वाला को देना होगा, तो दे देंगे, लेकिन इसका कोई लिखित तौर पर या ऑफिसियली तौर पर, हमलोगों को उपलब्ध नहीं करा पाये हैं, जिसके कारण टोटल ये 47 आर0ओ0बी0 अभी भी लटके पड़े हैं महोदय लेकिन हमारी कोशिश है, ये 2010 से ही आर0ओ0बी0 लटके पड़े थे, बीच में हमने इसमें तत्परता बहुत तेजी से लायी है लेकिन इकट्ठे इतने सारे की

स्वीकृति मिल गयी है लेकिन अभी यह डिसिजन लेना है कि कौन एजेंसी होगा और डी0पी0आर0 बनायेगा और 50-50 पर यह शेयरिंग कॉस्ट है, जो हमलोग करने जा रहे हैं महोदय । तो सी0आर0एफ0 फंड है, जो 200 करोड़ रुपया बिहार को मिला करता था, तो इस बार हम लग-लगा करके, सारी बातें रख करके हमलोगों ने इस बार 200 करोड़ से लेकर एक हजार करोड़ तक का प्रावधान किया, सारी चीजों का, एक हजार करोड़ की स्कीमों का, हमलोगों ने केन्द्र सरकार को बनाकर भेज दिया है लेकिन अभी इस पर एप्रूभल हुआ नहीं है, विपक्ष के लोग से हम चाहेंगे, इसपर हमने सब लोगों को बुला करके हमने मिला भी था, सब लोगों चाहे वह पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सब लोगों का इसमें है, हम चाहेंगे कि विपक्ष के लोग जा करके जल्द से जल्द इसका एप्रूभल लाये, क्योंकि इनकी केन्द्र में सरकार है, इनके मंत्री हैं, तो जल्दी होनी चाहिए, साथ ही साथ आर0सी0डी0 से महोदय पहली बार पाँच हजार का जो बजट था, उसको हमलोगों ने छूने का काम किया है, तो ये लोग जो गलत डाटा पेश कर रहे थे कि विभाग पैसा नहीं खर्च करती है, तो हम इनलोगों को बता देना चाहते हैं कि विभाग ने अब तक 91 परसेंट राशि को खर्च कर दिया है और 31 मार्च तक सारी राशि यानि शत-प्रतिशत राशि को खर्च कर देने का काम कर देंगे महोदय, यह हमलोगों की बड़ी उपलब्धि है और आपलोगों को याद होगा प्रकाश पर्व में, हमारा विभाग योगदान देने का काम किया और कंगनघाट से ले करके वहाँ पर पुल के निर्माण से, रोड के निर्माण से, सारी चीजों में हमलोगों का योगदान रहा और बिहार का जो नाम हुआ है प्रकाश पर्व यानि गुरु गोविन्द सिंह जी की जयंती पर, वह पूरे देश और दुनिया में इसका संदेश गया है, इस प्रकाश पर्व में पूरे देश दुनिया के लोग आये थे और साफ-सफाई से ले करके सारी चीजों का, हमारा डिपार्टमेंट ने ध्यान देने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में । महोदय, ये लोग बात करते हैं कि राज्य सरकार काम नहीं करती है लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं बी0एस0आर0डी0सी0 जो रोड कॉरपोरेशन है, इसको अवार्ड मिला है बेटर परफॉरमिंग प्रोजेक्ट अवार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमी एफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए0डी0बी0 से महोदय, इनके ही लोग अवार्ड दे रहे हैं कि बहुत तेजी से हमलोग काम कर रहे हैं और कहा है कि इनका बड़ा ही एचिभमेंट रहा है, साथ ही साथ महोदय हमारा जो विजन है, जो 20-20 विजन है, जो मास्टर प्लान 2035 का विजन है, यह जुमले पर बेस नहीं है, जो हमलोगों ने कहा है, वह हमलोगों को करके दिखाना है और हमलोग कर भी रहे हैं, जो डाटा हमने आपके समक्ष रखने का काम किया है, इससे सारी चीजें सामने आयी हैं, महोदय, एक पंक्ति हम बोलेंगे, हलाँकि विपक्ष के लोग तो चले गये लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि:

“किसी को जुमले पसंद हैं, किसी को फिक्क है नाम हो ज्यादा,
लेकिन हमारी कोशिश है यही, कि बातें कम, काम हो ज्यादा ।”

महोदय, हमारी महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय लालू जी के आशीर्वाद से, माननीया सोनिया जी के आशीर्वाद से, जो हमलोगों ने सपना देखा है, उसको तेजी से, बिहार को ऊचाईयों तक पहुंचाने का, हमलोग खोखले वादे नहीं कर रहे हैं महोदय, हमलोग जमीन पर काम करने का काम कर रहे हैं, हमलोग धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लालू जी को और सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वह विपक्ष के हों या पक्ष के हों, भले ही विपक्ष के लोग सामने में समर्थन नहीं देते हैं लेकिन पीछे में वे समर्थन देने का काम करते हैं, काम की तारीफ करते हैं, हमारी सरकार की तारीफ करते हैं और सब लोगों का आशीर्वाद हमलोगों को प्राप्त है और एक बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट है, किसी भी राज्य में जाते हैं या बड़े मैट्रो सिटीज में जाते हैं, एयरपोर्ट से जब भी कोई उतरता है, एयरपोर्ट में टूरिस्ट से लेकर बाहर के लोग, सारे लोग आते-जाते रहते हैं, एक अहम प्रोजेक्ट है, हलाँकि यह बहुत ही इनिसियल प्रोजेक्ट है, हमलोगों का विचार है, सोच है, जिस प्रकार मैट्रो सिटीज, आप दिल्ली देखें, हैदराबाद देखें, बंगलोर देखें, जिस हिसाब से एयरपोर्ट के लिए स्पेशल, डेडिकेटेड आपका एक्सप्रेस-वे रहता है, राज्य सरकार या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि एयरपोर्ट जो होगा, वह बिहटा में होगा, उसको देखते हुए हमलोगों का भी एक कालखण्ड में एक्सप्रेस-वे होगा, उसका निर्माण के लिए, शुरु में अभी इसपर प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पी0पी0आर0) की कार्रवाई चल रही है और एयरपोर्ट के निर्माण के साथ-साथ हमलोग चाहेंगे कि एयरपोर्ट का जो परसेप्शन है या बातें हैं और जिस प्रकार से आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिस हिसाब से पुल का जाल बिछ रहा है महोदय, उस हिसाब से एक छोटे से रूप में, जो आने वाले लोग हैं, वे इसे देखने का काम करें बिहार में, यह किस तेज गति से काम चल रहा है और लोगों का परसेप्शन भी काफी एप्रूभ होगा बिहार के प्रति, यह बड़ी और ब्यूटीफिकेशन के प्रति, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लेकर पटना के ब्यूटीफिकेशन के बारे में, हमलोग काम कर रहे हैं और काफी चीजें हमको बोलना था, बाकी बात हम सदन के पटल पर रखवा देंगे महोदय लेकिन बी0जे0पी0 के द्वारा जो इनलोगों का रवैया रहा, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किये, विशेष पैकेज की जो घोषणा किये, 55 हजार करोड़ रुपये के पैकेज देने की बात की थी लेकिन अभी तक कोई भी नयी योजना के लिए एक भी पैसा नहीं देने का काम किया है । महोदय जो नक्सल क्षेत्र इलाके थे, पहले जो वहाँ पर रोड बनता था, होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका पैसा दिया जाता था शत-प्रतिशत लेकिन इसमें भी इनलोगों ने 60-40 का रेशियो देकर इस गरीब राज्य में बोझ डालने का काम किया है, इसके लिए हमने होम

मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिखने का काम किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार में है, वहाँ भी मैंने चिट्ठी देने का काम किया है ।

क्रमशः

टर्न-27/सत्येन्द्र/18-3-17

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री(क्रमशः): इनको देना था लेकिन उल्टा चीज और भार देने का काम कर रहे हैं महोदय और 970 करोड़ रू० जो पेंडिंग है, हम बार-बार उठाते हैं लेकिन अबतक वह मिल नहीं पाया है और ज्यादा कुछ न कहते हुए महोदय हम एक बात बतलाना चाहेंगे कि अब आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा एक बिहारी बी०जे०पी० को हराने का काम करेगा और नरेन्द्र मोदी जी को एक बिहारी हराने का काम करेगा । महोदय, ये बात हम आपके समक्ष कहना चाहते हैं और कंकल्यूजन हम अपना करना चाहेंगे महोदय एक पंक्ति से

‘सभी सुन ले मेरी बात, आगे और जाना है,
नहीं छूटेगा अपना साथ, आगे और जाना है,
अभी तो हमने सिर्फ, झांकी ही दिखाई है,
अभी होनी है पूरी बात, आगे और जाना है।’

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांग संख्या-41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 66,35,90,08,000(छियासठ अरब पैंतीस करोड़ नब्बे लाख आठ हजार) रू० का अनुदान मांग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखा है उनसे कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“इस शीर्षक की मांग 10/- से घटायी जाय।”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“पथ निर्माण निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 66,35,90,08,000/- (छियासठ अरब पैंतीस करोड़ नब्बे लाख आठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मांग स्वीकृत हुई।

आज दिनांक 18 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 41 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 20 मार्च, 2017 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।